राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 9 अंक 343

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, शुक्रवार, 22 मई, 2026

www.jagran.com

पृष्ठ 14

अमेरिकी कंपनियों ने भारत में 60 अरब डालर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई

>> 10

जागरण विशेष

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस

जैव विविधता का संकेतक खतरे में, बचाने को चली मुहिम

सिलीगुड़ी : इंटरनेशनल यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर की रेड लिस्ट में शामिल है डायनासोर काल का हिमालयन सैलामैंडर। ● पेज-7

संपादकीय

केवल किफायत से नहीं चलेगा काम: छिटपुट सुधारों और सीमित गति वाली प्रगति का दौर अब बीत चुका है। अब व्यापक सुधार करने, सक्षम प्रदर्शन और गहन रूपांतरण का समय है। **तरुण गुप्त** का आलेख।

कोचिंग संस्कृति की चपेट में शिक्षा: नव उदार आर्थिकी के आने के बाद जब बाजार आक्रामक हुआ तो उसने शिक्षा और परीक्षा को भी अपनी चपेट में ले लिया। **बद्री नारायण** का दृष्टिकोण। ● पेज-8

विमर्श

सरकारी स्कूलों में व्यवस्थागत सुधार: प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुंच के बिना विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। **डा. वेदप्रकाश** का विश्लेषण।

राष्ट्रहित में त्याग की परंपरा: संकट के समय में समाज की शक्ति त्याग और सामूहिक सहयोग से बढ़ती है। **डा. मीना कुमारी जांगिड़** का आलेख। ● पेज-9

दैनिक जागरण **सप्तरंग**

मनोरंजन की दुनिया का

कान में छाया देसी ग्लैमर

सिनेमा की पिच पर क्रिकेट का जुनून ● पेज-13

आइपीएल 19 **धूम धड़ाका**

आज का मैच

सनराइजर्स हैदराबाद vs रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु

शाम 7:30 बजे स्थान: हैदराबाद

प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स/जियो हाटस्टार

सभी मंत्रालय और विभाग अनावश्यक खर्च में करें कटौती : मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया संकट के बीच 40 अरब डालर के निवेश प्रस्तावों के साथ पांच देशों की यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अपनी मंत्रिपरिषद के साथ लंबी बैठक की और हर स्तर पर तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपने-अपने विभागों में अनावश्यक खर्चों में कटौती को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने मंत्रियों को संवेदनशीलता और सर्तकता के साथ बढ़ने का संदेश देते हुए हर स्तर पर ऐसे कदम उठाने का निर्देश दिया जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बरकरार रखें। उनका जोर सुधारों को तेजी से लागू करने पर रहा। बैठक में नौ प्रजेंटेशन दिए गए। इनमें बताया गया कि पश्चिम एशिया में अनिश्चितता है और कोई भी देश उसके प्रभाव से बाहर नही है। भारत मजबूती से खड़ा है, लेकिन बहुत सावधानी से बढ़ने की जरूरत है। मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री की पांच देशों की सफल यात्रा और उसकी उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई।

- 40 अरब डालर के निवेश प्रस्तावों के साथ लौटे पीएम घरेलू मोर्चे पर डटे
- मंत्रियों को दिया संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ बढ़ने का संदेश
- मंत्रिपरिषद के साथ लंबी बैठक कर हर स्तर पर तैयार रहने को कहा

नरेन्द्र मोदी। फाइल

पांच देशों की यात्रा पर जाने के पहले पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से यथासंभव डीजल-पेट्रोल के खर्च में कटौती करने और एक वर्ष के लिए सोने की खरीद टालने की अपील की थी। इस अपील पर अमल करते हुए खुद मोदी ने अपने सुरक्षा काफिले में कटौती कर दी थी। कैबिनेट की बैठक में वह सिर्फ दो गाड़ियों के साथ गए थे। इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने सुरक्षा काफिले में कटौती का एलान किया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में मोदी ने इस अपील को दोहराया और कहा, सभी मंत्री खुद के साथ-साथ अपने करीबी लोगों को भी इस पर अमल करने के लिए प्रेरित करें।

मंत्रिपरिषद की बैठक में भाजपा सहित राजग के सभी घटक दलों ने पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने दुनिया के अन्य देशों की तुलना में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि कर जनता पर कम बोझ डालने को भी अच्छा कदम बताया। साथ ही पेट्रो पदार्थों की आपूर्ति बाधित होने के बाद डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए उठाए गए कदमों की प्रसंशा की। ज्ञात हो, 26 मई को मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और नौ जून को तीसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ भी होगी। इस बाबत सभी विभागों से उपलब्धियों का ब्योरा भी मांगा गया।

पुलवामा आतंकी हमले का साजिशकर्ता अर्जमंद गुलाम जम्मू-कश्मीर में ढेर

अज्ञात हमलावरों ने मुजफ्फराबाद में अर्जमंद गुलजार उर्फ हमजा बुरहान को मारीं चार गोलियां

आइएसआइ ने दिखावे के लिए चार वर्ष से कालेज का बनाया था संचालक और प्रिंसिपल

जागरण न्यूज नेटवर्क, श्रीनगर

पुलवामा आतंकी हमले का साजिशकर्ता व कई अन्य हमलों में वांछित अल-बदर मुजाहिदीन का आपरेशनल कमांडर अर्जमंद गुलजार उर्फ हमजा बुरहान गुरुवार को गुलाम जम्मू-कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक हमले में मारा गया। उसे दो अज्ञात हमलावरों ने ओजरा क्षेत्र में एमएस कालेज परिसर के पास चार गोलियां मारीं। बताया जा रहा है कि हमलावरों में से एक को पिस्तौल के साथ मौके पर ही पकड़ लिया गया। ज्ञात हो, अर्जमंद को दिखावे के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने चार वर्ष से इस कालेज का संचालक व प्रिंसिपल बना रखा था। उसे आइएसआइ ने निजी अंगरक्षकों का एक दस्ता और तीन एसयूवी गाड़ियां दे रखी थीं। समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, मूलतः पुलवामा के खरबतपोरा के रहने वाले अर्जमंद पर सुरक्षा बलों ने 10 लाख का इनाम रखा था। गृह मंत्रालय ने भी उसे 20 अप्रैल 2022 को आतंकी घोषित किया था।

अर्जमंद आठ वर्ष से पाकिस्तानी सेना व आइएसआइ का चहेता था। अल-बदर मुजाहिदीन की कमान काउंसिल में बख्त जमीन व यूसुफ बलोच के बाद उसका नंबर आता था। घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का नेटवर्क लगभग तबाह होने के बाद आइएसआइ अर्जमंद को आतंकवाद के स्थानीय चेहरे के तौर पर पेश कर आतंकियों की भर्ती का षड्यंत्र चला रही थी।

कई वारदात में था वांछित : दक्षिण कश्मीर में 2018 के दौरान आठ पुलिसकर्मियों व उनके स्वजन को अगवा करने के पीछे अर्जमंद का ही हाथ था। उसके इशारे पर वर्ष 2019 में कुलगाम में अल-बदर के कमांडर अबु अलकामा के मारे जाने के बाद उसकी रिश्तेदार युवती को आतंकियों ने सेना के लिए मुखबिरी करने के आरोप में मार डाला था। कुलगाम के अर्रेह क्षेत्र में दो जून 2022 को बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या में भी उसका हाथ था।

- पुलवामा का रहने वाला हमजा आठ वर्ष से गुलाम जम्मू-कश्मीर में था सक्रिय
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया था आतंकी घोषित, सुरक्षा बलों ने 10 लाख रुपये का रखा था इनाम

प्रतीकात्मक

बेंगलुरु में डाक्टरी की पढ़ाई करने वाला पहुंचा पाकिस्तान

बताया जाता है कि आतंकी बनने से पूर्व अर्जमंद बेंगलुरु के किसी कालेज में डाक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। अवकाश पर घर लौटा तो आतंकियों के मोटिवेटर के संपर्क में आया। इसके बाद वह वाघा बार्डर के रास्ते पाकिस्तान पढ़ने गया। पाकिस्तान में कुछ समय रहने के बाद वह आतंकी बनकर लौटा। इसके बाद वह अल-बदर के नेटवर्क को तैयार करने में जुट गया। सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2018 के अंत या 2019 की शुरुआत में उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में सुरक्षाबल के साथ मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी थी। उसने कुछ समय तक अपना इलाज कराया और फिर एलओसी पार कर गुलाम जम्मू-कश्मीर भाग गया। वहां पहुंचने के बाद उसने कश्मीर में अल-बदर के नेटवर्क को चलाना शुरू कर दिया। वर्ष 2020 में बारामुला व कुपवाड़ा के रास्ते कश्मीर पहुंचे हथियार अधिकांश उसके ही नेटवर्क के लिए थे।

पुलवामा हमले में 40 जवान हुए थे बलिदान, भारत ने की थी एयर स्ट्राइक

14 फरवरी 2019 को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलवामा में आतंकियों ने विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ के काफिले में शामिल वाहन को टक्कर मारी थी। हमले में 40 जवान बलिदान हो गए थे। जवाब में भारत ने 26 फरवरी को गुलाम जम्मू-कश्मीर में बालाकोट में जैश के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया था। इसमें कई आतंकी मारे गए थे।

पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में मारे गए प्रमुख आतंकी

- **11 मई, 2026:** लश्कर के टाप कमांडर मीर शुक्र खान की पाकिस्तान के क्वेटा में हत्या हुई। वह लश्कर में युवाओं की भर्ती में जुटा था।
- **27 अप्रैल, 2026:** लश्कर कमांडर शेख यूसुफ अफ्रीदी की खैबर पख्तूनवा में गोली मारकर हत्या। उसे पांच गोलियां मारी गईं।
- **21 मार्च, 2026:** मुरीदके में लश्कर हेडक्वार्टर के पास आतंकी कमांडर बिलाल आरिफ सराफी की नमाज के बाद चाकू घोंपकर हत्या।
- **16 मार्च 2025:** लश्कर आतंकी व हाफिज सईद के करीबी अबू कतल की सिंध प्रांत में हत्या। वह 2024 में जम्मू के रियासी जिले में शिवखोड़ी में श्रद्धालुओं पर हुए हमले की साजिश में शामिल था।
- **18 मई, 2025:** पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लश्कर-ए-तैयबा के टाप कमांडर सैफुल्लाह खालिद को अज्ञात हमलावर ने मार गिराया।
- **फरवरी 2025:** पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हाफिज सईद के एक और करीबी मौलाना काशिफ अली को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया।
- **मार्च 2025:** आइएसआइ के अंडरकवर एजेंट मुफ्ती शाह मीर की बलूचिस्तान के तुरबत शहर में बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

एबी अवार्ड्स में दैनिक जागरण को पब्लिशर आफ द ईयर सम्मान

जागरण संवाददाता, गोवा: इनमा ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने के बाद मीडिया और विज्ञापन जगत के प्रतिष्ठित एबी क्रिएटिव अवार्ड्स 2026 में दैनिक जागरण को पब्लिशर आफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीन स्वर्ण, दो रजत, दो कांस्य पदक और एक मेरिट सम्मान के साथ कुल आठ पुरस्कार जीतने के साथ ही दैनिक जागरण शीर्ष पर रहा। 'मुद्रित समाचारपत्र का सर्वश्रेष्ठ विपणन' श्रेणी में दैनिक जागरण को उसके अभियान 'नया नाम, नई पहचान' के लिए स्वर्ण पदक, 'हिंदी हैं हम' और 'संस्कारशाला' अभियानों के लिए रजत पदक व 'कितने सुरक्षित हैं स्कूल?' अभियान को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया।

'सरोकार संबंधी पहल' श्रेणी में दैनिक जागरण को 'कितने सुरक्षित हैं स्कूल?' और 'नया नाम, नई पहचान' अभियानों के लिए स्वर्ण पदक व 'भारत रक्षा पर्व' के लिए कांस्य पदक प्राप्त हुआ। वहीं, 'मिशन 1000 टन' अभियान को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ जागरण प्रकाशन ने एक बार फिर यह साबित किया है कि सामाजिक सरोकार, नवाचार और प्रभावशाली अभियानों के माध्यम से वह मीडिया उद्योग में नए मानक स्थापित कर रहा है। गौरतलब है कि विज्ञापन, मीडिया और विपणन के क्षेत्र में रचनात्मकता के लिए प्रदान किया जाने वाला भारत का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। एडवरटाइजिंग क्लब व एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन आफ इंडिया और वन क्लब फार क्रिएटिविटी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित गोवाफेस्ट में एबी अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं।

- एबी क्रिएटिव अवार्ड्स में दैनिक जागरण ने जीते तीन स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य
- 'हिंदी हैं हम' को भी सम्मान
- नवाचार, प्रभावशाली अभियान व जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए दैनिक जागरण को किया गया पुरस्कृत

श्रेणी	अभियान	पदक
मुद्रित समाचारपत्र का सर्वश्रेष्ठ विपणन	नया नाम, नई पहचान	स्वर्ण
मुद्रित समाचारपत्र का सर्वश्रेष्ठ विपणन	हिंदी हैं हम	रजत
मुद्रित समाचारपत्र का सर्वश्रेष्ठ विपणन	संस्कारशाला	रजत
मुद्रित समाचारपत्र का सर्वश्रेष्ठ विपणन	कितने सुरक्षित हैं स्कूल	कांस्य
सरोकार संबंधी पहल	कितने सुरक्षित हैं स्कूल	स्वर्ण
सरोकार संबंधी पहल	नया नाम, नई पहचान	स्वर्ण
सरोकार संबंधी पहल	भारत रक्षा पर्व	कांस्य
सरोकार संबंधी पहल	1000 टन	सांत्वना

मराठी में नीट पेपर का अनुवाद करने वाले शिक्षकों ने प्रश्न रटे और छात्रों को बता दिए: एनटीए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नीट-यूजी के पेपर लीक मामले में गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के शीर्ष अधिकारी शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए। उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि सिस्टम में कंप्रोमाइज हुआ था। अंतिम प्रश्न पत्र को मराठी भाषा में अनुवाद करने के लिए जिन शिक्षकों को दिया गया था, उन्होंने ही प्रश्नों को रट लिया था। बाद में उन्हें कागजों पर उतारकर गेस पेपर के रूप में छात्रों को मुहैया करा दिया।

समिति के कुछ सदस्यों ने एनटीए महानिदेशक अभिषेक सिंह से कहा, जब हूबहू प्रश्नपत्र गेस पेपर के जरिये बाहर आया तो इसे लीक ही माना जाएगा। समिति ने प्रश्न पत्र तैयार करने से जुड़े प्रश्न भी किए। इस पर सिंह सिर्फ इतना बोले, सीबीआइ जांच चल रही है।

- संसदीय समिति के समक्ष पश हुए एनटीए अफसरों की सफाई
- कहा, पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ
- दिग्विजय बोले, यह पेपर लीक, भाजपा सांसदों ने कहा, जांच पूरी हुए बगैर यह कहना ठीक नहीं

संबित ने दिग्विजय पर एजेंडा लीक करने का आरोप लगाया

सत्रों की मानें तो बैठक शुरू होने से पूर्व ही भाजपा सांसद संबित पात्रा ने समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह पर एजेंडा लीक करने का आरोप लगाया। बैठक में हंगामे के बीच दिग्विजय ने कहा, पेपर लीक को लीक न बोला जाए तो क्या कहा जाए? इस पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, जब तक सीबीआइ की रिपोर्ट पेश नहीं हो जाती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए। ज्ञात हो, दिग्विजय की अगुवाई वाली इस बैठक में लोस व रास के 15 सदस्य पहुंचे थे। इनमें भाजपा, कांग्रेस, सपा के सांसद शामिल थे। वहीं शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी व एनटीए के अधिकारी भी मौजूद थे।

एनटीए महानिदेशक बोले- राधाकृष्णन समिति की 70% सिफारिशों पर अमल पेज>>5

'बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी पर बंगाल सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सुजय पाल और पार्थसारथी सेन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने शुक्रवार को यह टिप्पणी करते हुए कहा, बकरीद के अवसर पर पशुओं की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया कि राज्य में लागू नियमों के कारण बकरीद पर कुर्बानी को लेकर अनिश्चितता पैदा हो रही है।

उमालूम हो कि राज्य में 1950 के पशुधन कानून के तहत बिना प्रशासनिक अनुमति गोवंश वध पर रोक है। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के पशुओं के वध की अनुमति नहीं है। मांस काटने और बिक्री के लिए स्थानीय प्रशासन अथवा पशुपालन विभाग से लिखित अनुमति लेना भी अनिवार्य है। इस पर अदालत ने कहा कि राज्य में पशुधन संबंधी कानून और प्रशासनिक नियम पहले से प्रभावी हैं, उनका पालन करना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कानून लागू नहीं होता तो वर्षों से इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी करने और मामले दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं होता। साफ किया कि सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के दायरे में रहकर ही धार्मिक गतिविधियां की जा सकती हैं। अदालत के फैसले के बाद ईद से पहले राज्य में गोवंश वध को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है।

- कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज की प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका
- कोर्ट ने कहा- कानून के दायरे में ही होंगी धार्मिक गतिविधियां

प्रतीकात्मक

बंगाल के सभी मदरसों में अब अनिवार्य होगा 'वंदे मातरम्'

कोलकाता : बंगाल में अब सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पूर्व प्रार्थना सभा के दौरान 'वंदे मातरम्' गाना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा पर अमल करते हुए राज्य के मदरसा शिक्षा निदेशालय ने गत दिवस आदेश जारी कर दिया है। (पेज-4)

शुभेंदु बोले-अब सीधे बीएसएफ को सौंपे जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिये पेज>>4

कर्मियों के सर्कुलर पर विवाद, 24 घंटे में सरकार ने सीमित किया दायरा पेज>>4

आकलन

एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख ने कहा- सुशासन के बूते पार्टी अपना रसूख रख सकेगी कायम, लगातार जीत के बाद पार्टी के सामने चुनौती भी बड़ी, करना होगा सुपर परफार्म

भाजपा का कम से कम 20 वर्ष तक कायम रहेगा प्रभुत्व

नई दिल्ली, प्रेट्र: भाजपा सरकारें ऐसे ही काम करती रहीं तो अगले 20 साल तक उनका प्रभुत्व यूं ही कायम रहेगा। 2014 में शुरू हुआ भाजपा के राजनीतिक दबदबे का मौजूदा दौर सुशासन के बूते आगे भी चलता रहेगा। यह कहना है सर्वेक्षण संस्था 'द एक्सिस माई इंडिया' के प्रमुख और चुनाव विश्लेषक प्रदीप गुप्ता का।

एक साक्षात्कार में गुप्ता ने कहा, 'राजनीति में एक सीमा होती है। पहले कांग्रेस ने 1977 तक लगातार शासन किया। उसके बाद उसे मुश्किलें आने लगीं। उन दिनों हम लगभग 20 साल तक चलने वाली राजनीतिक पीढ़ी की बात करते थे। वह 20 साल का दौर अब भी बना रहेगा।' भाजपा लंबे समय तक भारतीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव बनी रह सकती है।'

उनके अनुसार सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों का ही भविष्य काफी हद तक मौजूदा सरकार के कामकाज पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद भाजपा से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। इसलिए भाजपा और राजग को अब सुपर परफार्म करना होगा। 'जब तक उनका प्रदर्शन कमजोर या खराब नहीं होता, वे जीतते रहेंगे और विपक्ष हारता रहेगा।' उन्होंने कहा, कांग्रेस अतीत के कुशासन से जुड़ी धारणाओं का बोझ है और इससे उबरने में अभी वक्त लगेगा। 'अगर आप 2029 की भी बात करें तो इसका मतलब होगा लगभग 15 साल (कांग्रेस के लिए सत्ता से बाहर रहने के)। मुझे लगता है कि उन्हें पूरे देश को मनाने में कम से कम पांच साल और लग सकते हैं।' साथ ही उन्होंने कहा कि जब आप टाप पर पहुंचते हैं तो बाद में नीचे आने की भी प्रवृत्ति बनी रहती है। भाजपा भी उस स्तर पर पहुंच गई है जहां उससे आकांक्षाएं बढ़ गई हैं।

नई दिल्ली में एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए। प्रेट्र

तमिलनाडु के मतदाताओं ने विजय को द्रविड़ पार्टियों का विश्वसनीय विकल्प माना

चुनाव विश्लेषक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि उनकी एजेंसी ने तमिलनाडु में विजय के उभार को विस चुनाव से एक वर्ष पहले पहचानना शुरू किया। मतदाताओं ने अभिनेता-राजनेता विजय को द्रविड़ पार्टियों का विश्वसनीय विकल्प माना। विजय का वोट शेयर चुनाव से छह माह पहले 25% था जो वोटिंग के दिन 35% पर पहुंच गया। विजय की लोकप्रियता ने उन्हें नेता के रूप में स्थापित किया। अन्नाद्रमुक के कमजोर होने से विजय को राजनीतिक उभार मिला।

जिनमें स्पार्क दिखता है उसी के साथ जुड़ जाते हैं प्रशांत किशोर

चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) के बारे में कहा, पीके और उनकी टीम उन नेताओं और पार्टियों के साथ जुड़ते हैं, जहां उन्हें "स्पार्क" दिखता है। उनके राजनीतिक आकलन उभरते रुझानों की समझ पर आधारित होते हैं। पीके की 2025 की शुरुआत में की गई भविष्यवाणी का उल्लेख करते गुप्ता ने कहा, उन्होंने कहा था कि विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में उभर सकते हैं, यह आकलन महज तुक्का नहीं था।

खराब थी दाईं किडनी, निकाल दी बाईं, देना होगा दो करोड़ जुर्माना

नई दिल्ली, प्रेट्र: उप्र के एक डाक्टर के हाथों सर्जरी के दौरान घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। खराब की जगह स्वस्थ किडनी निकालने के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने डाक्टर को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया और दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने इस मामले को चिकित्सा जगत की सबसे घोर लापरवाहियों में से एक बताया है। यह मामला 2012 का है, जब एक महिला की खराब दाईं किडनी की जगह बाईं किडनी निकाल दी गई थी। बाद में महिला की मौत हो गई थी।

एनसीडीआरसी के अध्यक्ष एपी साही और सदस्य भारतकुमार पंड्या की पीठ ने मामले की सुनवाई की और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया। आयोग ने उत्तर प्रदेश के सर्जन डा. राजीव लोचन को गंभीर चिकित्सा लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। वह घटना के समय अलीगढ़ में आशीर्वाद नर्सिंग होम का संचालन करते थे और यही उनका आवास बताया जा रहा है।

- एनसीडीआरसी ने सुनाया यह फैसला, कहा- घोर लापरवाही का है मामला
- उत्तर प्रदेश के डाक्टर ने 2012 में की थी सर्जरी, महिला की हो गई थी मौत

लापरवाही के सबसे गंभीर रूपों में से एक पेज>>7

27 मई तक के लिए आरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि भीषण गर्मी और लू का दौर अभी सप्ताह भर और जारी रहेगा। अधिकतम एवं न्यूनतम ताप्मान क्रमश: 45 और 31 डिग्री रहने की संभावना है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार, 22 मई, 2026

आज का मौसम

कुछ जगह लू चलेगी। रात भी गर्म होगी। 25 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा चलने की संभावना है।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
22 मई	45.0	31.0
23 मई	45.0	31.0
नोएडा		
22 मई	43.0	28.0
23 मई	44.0	27.0
गुरुग्राम		
22 मई	44.0	29.0
23 मई	44.0	29.0

डिग्री सेल्सियस में

ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल में सात हजार वाहनों का परिचालन प्रभावित

- पर्यावरण मंत्री की ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक का नहीं निकला नतीजा, आज सीएक्यूएम अधिकारियों के साथ बैठक
- हड़ताल से आटो, टैक्सी, टूरिस्ट वाहन व कैब सेवा रहीं अलग, सब्जी मंडी व थोक बाजारों में आंशिक असर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) में बढ़ोतरी के साथ ही नवंबर से बीएस-4 व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरोध में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के पहले दिन गुरुवार को मिलाजुला असर रहा।

हड़ताल का आह्वान करने वाली आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआइएमटीसी) समेत अन्य ट्रांसपोर्ट संगठनों का दावा है कि उसकी हड़ताल से गुरुवार को दिल्ली में तकरीबन सात हजार व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रभावित रहा। खासकर हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) व भारी मोटर वाहन (एचएमवी) का परिचालन करीब 30 प्रतिशत ही रहा।

गाजीपुर व आजादपुर समेत कई अन्य थोक मंडियो में व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही कम रही। संगठनों के पदाधिकारियों ने सफाई दी कि जो ट्रक रास्ते में थे, उन्हें आने दिया गया है। इसलिए गुरुवार को 30 प्रतिशत ट्रक चले। हड़ताल का मुख्य असर शुक्रवार और शनिवार को दिखाई देगा।

सुचारु रूप से चले आटो, टैक्सी, कैब

दावों और आशंकाओं से इतर दिल्ली की सड़कों पर आटो, टैक्सी, कैब, टूरिस्ट बस व ई-रिक्शा का संचालन सुचारु रहा, जिससे दिल्ली वालों को कुछ खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बहादुर शाह जफर मार्ग पर ग्राहकों का इंतजार करने आटो चालकों में से एक श्रीकांत ने बताया कि यह हड़ताल केवल व्यावसायिक वाहनों की है। वह लोग उसमें सम्मिलित नहीं है। दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन, व आटो, टैक्सी संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने कहा कि सीएनजी के दाम में वृद्धि से उन लोगों को चिंता है, लेकिन वह हड़ताल में शामिल नहीं है।

इस बीच, हड़ताल को खत्म कराने को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा तथा पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ ट्रांसपोर्टरों की बैठक भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस संबंध में एआइएमटीसी के अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने बताया कि शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अधिकारियों के साथ बैठक तय है। बैठक में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) में भारी बढ़ोत्तरी व बीएस-4 व्यावसायिक वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध को लेकर वार्ता होगी। ट्रांसपोर्टर चाहते हैं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार उठाए और वहां से राहत का आग्रह करे।

गाजीपुर सब्जी मंडी में गुरुवार में ट्रकों पर सब्जियां और फल लोड, अनलोड होते रहे। चंद्र प्रकाश मिश्र

वैसे, हड़ताल का असर बाजारों में दिखाई पड़ा। जहां सामानों की आवाजाही प्रभावित रही। फेडरेशन आफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन (फेस्टा) के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने बताया कि अधिकतर कारोबारियों ने सामानों की आपूर्ति तथा माल मंगाने की व्यवस्था हड़ताल के मद्देनजर तीन दिनों के लिए स्थगित कर दी है।

क्या है मुद्दा: एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जरूरी वस्तुओं लेकर आने वाले मालवाहक ट्रकों पर भी पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लागू कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में ट्रक न आएं और ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरलवे से गुजरें इसके लिए ईसीसी की दरों में वृद्धि कर दी। इसमें दो एक्सेल और तीन एक्सल वाले मालवाहक वाहनों पर जहां पहले 1400 व 2600 रुपये का ईसीसी लगता था, उसे बढ़ाकर क्रमशः 2000 और 4000 रुपये दिल्ली में प्रति प्रवेश कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वार काउंसिल चुनावों की गिनती पर रोक हटाने से किया इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल आफ दिल्ली (बीसीडी) चुनाव की वोटों की गिनती पर रोक लगाने वाले पहले के आदेश को संशोधित करने से इन्कार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट से 25 मई को याचिकाओं पर सुनवाई करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत व न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने आग्रह किया कि वोटों की गिनती पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के 18 मई के आदेश को संशोधित किया जाए। सिंह ने कहा, मतगणना चल रही है। इसे पूरा होने दीजिए। हाई कोर्ट के आदेशों के अधीन इसे जारी नहीं किया जाएगा।" कहा कि वोट बिखरे हुए हैं और यह वोटों से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाता है। सीजेआइ ने कहा, हम आदेश में संशोधन नहीं करेंगे। बीसीडी चुनावों के संबंध में गंभीर मुद्दे हैं। पीठ ने आदेश दिया, " दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले को एक डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हैं।

न्यूज गैलरी

आज से नमो भारत लगाएगी आठ अतिरिक्त फेरे

नई दिल्ली: दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कारिडोर पर यात्रियों की बढ़ी भीड़ को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) शुक्रवार से व्यस्त घंटों के दौरान नमो भारत ट्रेन के आठ अतिरिक्त फेरे की शुरुआत कर रहा है। नए शेड्यूल में सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे के बीच तथा शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे के बीच सराय काले खां से मेरठ साउथ के बीच ट्रेन आठ अतिरिक्त फेरे लगाएगी। दो और ट्रेनें लगाई जाएंगी। (राब्यू)

खजूरी खास दंगे में हिंसा के मामले में तीन दोषी करार

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन आरोपितों को दोषी ठहराया है। अदालत ने माना कि ये सभी एक गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा थे, जिसने खजूरी खास इलाके में पुलिस पर पत्थरबाजी की और ड्यूटी कर रहे अधिकारियों के काम में बाधा डाली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीन सिंह ने इकराम, सरफराज और मुस्तकीम के खिलाफ सुनवाई करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा है। (जासं)

रविवार को सुबह छह बजे से चलेगी मेट्रो

नई दिल्ली: सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा देने वालों की सुविधा के लिए रविवार को दिल्ली मेट्रो की सेवा सुबह छह बजे शुरू होगी। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में आसानी होगी। आमतौर पर रविवार को पिंक लाइन, मजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर मेट्रो सेवा सुबह सात बजे शुरू होती है। (वि.)

ढाई लाख वार्षिक आय वाले परिवारों का बनेगा राशन कार्ड

फैसला ▶ मंत्रिमंडल की अगली बैठक में मिल सकती है स्वीकृति

7,71,384 लाख अपात्र व फर्जी नाम हटाए गए

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए आय की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले राशन कार्ड के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा एक लाख रुपये थी। इस वर्ष जनवरी में इसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये किया गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब इसे बढ़ाकर ढाई लाख रुपये वार्षिक किया जाएगा। मामले में मंत्रिमंडल में चर्चा हुई। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इसे स्वीकृति मिल सकती है। इससे अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता में कहा कि 13 वर्षों तक दिल्ली में नया राशन कार्ड नहीं बनाया गया। अब नए राशन कार्ड व परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए 15 मई से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्तमान में करीब 17 लाख राशन कार्डधारक हैं। सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था का व्यापक आडिट कराया गया है, जिसमें 7,71,384 अपात्र और फर्जी लाभार्थी पाए गए। इनमें 6,46,123 कार्ड धारक निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले 95,682 लोग पिछले एक वर्ष से राशन नहीं लेने वाले मिले। 6185 मृत व्यक्तियों के नाम राशन रिकार्ड में दर्ज थे और 23,394 लोग एक से अधिक स्थानों से राशन ले रहे थे। सभी अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने के बाद करीब 7.72 लाख नए पात्र लोगों के राशन कार्ड बनेंगे। पिछले 13 वर्षों में राशन कार्ड के लिए 3,72,367 आवेदन और राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए 99,501 आवेदन लंबित हैं। इन सभी आवेदकों को वर्तमान नियमों और नई पात्रता शर्तों के अनुसार फिर से आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है। राशन वितरण व्यवस्था में बड़े स्तर पर डिजिटल सुधार किए गए हैं। राशन दुकानों पर पारंपरिक वजन मशीनों की जगह ई-वेइंग मशीनें लगाई जा रही हैं और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन से लेकर इससे जुड़ी सभी सेवाएं अब आनलाइन कर दी गई है।

दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जागरण

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले परिवार की आय संबंधी जानकारी केवल स्व-घोषणा के आधार पर स्वीकार की जाती थी। इसमें गड़बड़ी की संभावना रहती थी। अब आवेदन करते समय निवास प्रमाण पत्र, नवीनतम आय प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण जमा करना होगा। भ्रष्टाचार व गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने तीन स्तरों पर जांच होगी। पहले चरण में आवेदन व दस्तावेज की डिजिटल जांच और जरूरत पड़ने पर मौके पर सत्यापन भी होगा। दूसरे चरण में सहायक आयुक्त के पास आवेदन जाएगा। तीसरे चरण में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला समिति निर्णय लेगी, जिसमें क्षेत्र के दो विधायक भी शामिल होंगे। समिति की स्वीकृति मिलते ही राशन कार्ड डिजिटल रूप से जारी हो जाएगा। इस असवर पर दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित थे।

एनसीआर में उद्योगों को राहत, अभी कर सकेंगे वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के इलाकों में काम करने वाले उद्योगों, होटलों, रेस्तरां अन्य प्रतिष्ठानों के लिए राहत भरी खबर है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक आदेश जारी कर स्वीकृत ईंधनों की सूची में दी गई ढील को एक महीने और बढ़ा दिया है। सीएक्यूएम ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की सलाह पर इन प्रतिष्ठानों को वैकल्पिक ईंधनों के अस्थायी इस्तेमाल की अनुमति दी है। इनमें हाई स्पीड डीजल, बायोमास, आरडीएफ (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल) पैलेट्स शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि ये वैकल्पिक ईंधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो, तो सीमित अवधि के लिए कोयले और केरोसिन का उपयोग भी किया जा सकता है।

गौरतलब है कि आयोग ने सबसे पहले इस साल 13 मार्च को एक महीने के लिए यह अंतरिम छूट दी थी। इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर 15 अप्रैल को इसे बढ़ाकर 13 मई तक किया गया था। अब सीपीसीबी की ताजा सिफारिशों और मौजूदा संकट को देखते हुए इस छूट को एक बार फिर मध्य जून अथवा अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण मार्च 2026 की शुरुआत से ही गैस की वैश्विक आपूर्ति बाधित चल रही है।

एक दिन में हीट स्ट्रोक के दो मामले, एक वेंटिलेटर पर, दूसरा भी गंभीर

- आरएमएल में बंगाल के छात्र सहित दोनों मरीज किए गए हैं भर्ती
- समय पर उपचार नहीं मिलने पर हीट स्ट्रोक जानलेवा साबित हो सकता है

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी में भीषण लू के बीच हीट स्ट्रोक के मामले भी सामने आने लगे हैं। एक दिन में ही हीट स्ट्रोक के दो मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों की चिंता बढ़ गई है। हीट स्ट्रोक के ये दोनों मरीज आरएमएल अस्पताल में भर्ती हुए। दोनों मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें एक वेंटिलेटर पर है। दोनों का उपचार विशेष निगरानी में किया जा रहा है। उधर, सफदरगंज अस्पताल में 18 मई को भर्ती हुए मरीज को उपचार के बाद स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर उपचार नहीं मिलने पर हीट स्ट्रोक जानलेवा साबित हो सकता है।

आरएमएल अस्पताल ने मिली जानकारी के अनुसार, पहला मामला बंगाल निवासी 24 वर्षीय छात्र का है। वह ट्रेन से हावड़ा से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचा था। वह जनरल बोगी में था। स्टेशन पर उतरते ही तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उसे बुधवार रात करीब पौने दो बजे आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर और हीट स्ट्रोक नोडल आफिसर प्रो. डा. अजय चौहान ने बताया कि छात्र के शरीर का तापमान 105 डिग्री फारेनहाइट से अधिक था। उसे लगातार उल्टियां, दस्त और बेहोशी जैसे लक्षण थे।

बाल भवन के समीप भीषण गर्मी से बचने के लिए खुद व अपने बच्चे को आंचल से ढककर ले जाती मां। हरीश कुमार

रात का तापमान पहुंचा 31.9 डिग्री के पार : राजधानी में दिन के साथ ही अब रात का तापमान भी तेजी के साथ बढ़ने लगा है। बुधवार रात का तापमान 31.9 डिग्री पर पहुंच गया, जो मई में 14 साल में रात का सबसे अधिक तापमान है। इसके चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक 31.9 डिग्री दर्ज किया गया। यह 14 साल में मई महीने का सर्वाधिक है। इससे पहले 26 मई 2012 को न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री पहुंचा था।

स्पीकर ने किया भूले-बिसरे राष्ट्रनायकों को स्मृति में पुनर्स्थापित करने का आह्वान

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : 'दिल्ली विधानसभा केवल एक विधायी संस्था नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक यात्रा व स्वतंत्रता संग्राम की जीवंत धरोहर है। लाइट एंड साउंड शो, विधायी ई-संग्रहालय तथा जन-जागरूकता कार्यक्रम जैसी पहल से हम भूले-बिसरे राष्ट्रनिर्माताओं व स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को पुनः जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।' यह बात विस अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरएसएस के शोध प्रकोष्ठ 'परंपरा लेखन समिति' दिल्ली प्रांत इकाई के प्रतिनिधिमंडल से संवाद के दौरान कही। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विजय शर्मा ने किया, जिसने गुरुवार को विधानसभा का भ्रमण किया।

प्रतिनिधिमंडल को अनुपम खेर की वाणी में प्रस्तुत वीर विठ्ठलभाई पटेल के जीवन एवं संसदीय योगदान पर आधारित डाक्यूमेंट्री व शताब्दी काफी टेबल प्रकाशन 'एक शताब्दी यात्रा' पर आधारित डाक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। इसके बाद विस भवन के महत्व, संसदीय परंपराओं, विधायी प्रक्रियाओं व सदन संचालन से अवगत कराया गया।

एक भी निगम स्कूल को नहीं किया बंद, आप के आरोप झूठे : महापौर

- महापौर ने कहा, किसी स्कूल में कमरे खाली हैं तो उनका सदुपयोग किया जा रहा है

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

महापौर प्रवेश वाही ने 48 एमसीडी स्कूलों को बंद कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने के आरोपों को खारिज किया है। साथ ही विपक्ष पर लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने से बौखलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ वर्ष पहले जब भाजपा की दिल्ली सरकार बनी व निगम में सत्ता लौटी तो निगम के 1514 स्कूल चालू थे जहां 6.50 लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। अब भी यही स्थिति है। महापौर ने कहा कि हम निगम स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर 2032 तक अंग्रेजी माध्यम में विकसित करेंगे।

महापौर ने कहा कि स्कूल बंद करके वहां आयुष्मान आयोग्य मंदिर खोलने को लेकर नेता प्रतिपक्ष के आरोप झूठ का पुलिंदा हैं। अगर, किसी स्कूल में बच्चों की संख्या कम है और कमरे खाली हैं तो उनका सदुपयोग किया जा रहा है, न कि स्कूल बंद कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं। महापौर ने कहा कि आप सरकार ने निगम में रहते और दिल्ली सरकार में रहते स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का कोई कार्य नहीं किया। मोहल्ला क्लीनिक खोलकर भ्रष्टाचार किया था। जबकि भाजपा सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत कर रही है।

आप का आरोप, 48 स्कूलों को बंद कर आयुष्मान मंदिर खोले

एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने निगम में सत्तारूढ़ भाजपा पर 48 स्कूलों को बंद कर उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तब्दील करने का आरोप लगाया है। नारंग ने कहा कि अभी तो यह सिर्फ 48 स्कूल हैं, लेकिन शिक्षा निदेशक की मिलीभगत से भाजपा की तैयारी काफी सारे एमसीडी स्कूलों को आपस में जोड़ने (मर्ज) की है।

राघव चड्ढा की आवाज और तस्वीर का दुरुपयोग रोकने की मांग खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा की आवाज और तस्वीर के दुरुपयोग को रोकने की मांग की याचिका पर अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि राजनीतिक आलोचना, व्यंग्य और कार्टून पर केवल इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वे किसी नेता को अप्रिय लगते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आलोचना और मानहानि के बीच बारीक रेखा होती है और लोकतंत्र में व्यंग्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोर्ट ने कहा कि यदि चड्ढा का प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का दावा है तो वह मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मानहानि से जुड़ी मांग जोड़ने के लिए संशोधन की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्रथमदृष्टया व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं बनता, क्योंकि जिन पोस्ट पर आपत्ति जताई गई, वे फैसलों की आलोचना से जुड़ी हैं। अदालत ने राजनीतिक कार्टूनों का उल्लेख किया।

घर में घुसकर मां-बेटे की हत्या की, नकदी व जेवर लूटे

- मां पर आठ तो बेटे पर छह बार चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट
- किचन में खून से लथपथ मिले दोनों के शव, पुलिस को जानकार पर शक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

क्राइम कैपिटल बनती जा रही राजधानी में बुधवार देर रात घर में घुसकर 40 वर्षीय महिला और 13 साल के बेटे की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद बदमाश घर से 10 लाख की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। महिला के शरीर पर आठ तो बेटे के शरीर पर चाकू मारने के छह घाव मिले हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि महिला के पति ने एक कमेटी चला रखी थी, जिसके 10 लाख मिले थे। ये रुपये और घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण गायब हैं। आशंका रही है कि लूटपाट के लिए ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। चूंकि, घर में सारी वस्तुएं व्यवस्थित मिली हैं, ऐसे में पुलिस को शक है कि वारदात को किसी जानकार ने ही अंजाम दिया है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय कुमार के मुताबिक, मूलरूप से बदायूं के रहने वाले विष्णु दयाल साहू करीब 12 साल से गोविंदपुरी की गली नंबर 10 में रह रहे हैं। 2002 में पत्नी की मौत के बाद उन्होंने 2009 में शारदा साहू से दूसरी शादी की थी। कई वर्षों तक बच्चा न होने पर विष्णु दयाल ने छोटे भाई दिनेश के तीसरे बेटे खुशहाल को गोद लिया था। विष्णु दयाल साप्ताहिक बाजार में सब्जी की दुकान लगाते हैं। बुधवार रात करीब 12.30 बजे जब वे घर लौटे और आवाज लगाई, तो लाइट जल रही थी और तेज अवाज में टीवी चल रहा था।

शारदा साहू। सौ. स्वजन

खुशहाल। सौ. स्वजन

सेंट स्टीफेंस कालेज में पूर्व प्रिंसिपल की नियुक्ति का विरोध

जासं, नई दिल्ली : डीयू से संबद्ध सेंट स्टीफेंस कालेज में पूर्व प्रिंसिपल जान वर्गीस को कालेज के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के रूप में पुनः नियुक्त किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वर्गीस इससे पहले कालेज में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत थे और अब कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें यह नई जिम्मेदारी दी गई है। इसका कालेज के कुछ अध्यापक विरोध कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह नियुक्ति सामान्य नियमों के खिलाफ मानी जा रही है। नियमों के मुताबिक, डेपुटेशन पूरा होने के बाद संबंधित व्यक्ति को अपने मूल संस्थान, यानी जान वर्गीस के मामले में अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में वापस लौटना था। ऐसे में सेंट स्टीफेंस कालेज में उनकी पुनर्नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यह मामला पहले से ही डीयू और कालेज के बीच नियमों को लेकर चल रहे मतभेदों को और बढ़ा सकता है।

भव्य आयोजन

राजधानी में 24 मई को दिखेगी देशभर की जनजाति संस्कृति

जनजाति समागम में पांच मार्गों से लाल किला पहुंचेंगे जनजाति समाज के लोग, राज्यों की अलग-अलग टोली के साथ पारंपरिक वेशभूषा और वाद्ययंत्रों पर झूमेंगे

नेमिष हेमंत • जागरण

नई दिल्ली: दिल्ली वालों के लिए यह अनुभव अनूठा व अविस्मरणीय होगा, जब 24 मई को एक साथ विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए जनजाति समाज के करीब 1.5 लाख लोगों का कारवां पारंपरिक वेशभूषा व वाद्य यंत्रों की थाप पर झूमते-गाते हुए लाल किला मैदान पहुंचेगा। यहां जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन होगा। इससे पहले कई किमी लंबी यह यात्रा सनातन धरोहर को सहेजने वाली जनजाति समाज की संस्कृति, विविधता, प्रकृति प्रेम व भारतीयता से जुड़ाव की लाइव प्रस्तुति होगी।

शोभायात्रा के लिए लाल किला के नजदीक के पांच मार्गों का चयन किया गया है। इनमें अजमेरी गेट, रामलीला मैदान, राजघाट, श्यामगिरि मंदिर व कुदेसिया पार्क शामिल हैं। 24 मई को दोपहर बाद देशभर से जुटे जनजाति समाज के लोग शोभायात्रा के रूप में लाल किला की ओर जाएंगे। यह यात्रा मार्ग 13.3 किमी का होगा। इसमें सबसे लंबा शोभा यात्रा मार्ग श्यामगिरि मंदिर से लाल किला तक 3.5 किमी का है, जबकि सबसे छोटा मार्ग कुदेसिया बाग से लाल किला का मात्र दो किमी का होगा।

जनजाति सांस्कृतिक समागम में शामिल होने के लिए अंडमान निकोबार के 116 कार्यकर्ताओं का एक दल 23 मई को दिल्ली पहुंचेगा। सौ : आयोजक

आयोजकों के अनुसार, यह मार्ग अधिक लोगों तक पहुंचने व यात्रा में शामिल लोगों की सुविधा के अनुसार तय किया गया है। गर्मी के मद्देनजर इसे छोटा ही रखा गया है। विशेष बात यह है कि इसमें अलग-अलग राज्यों की विभिन्न टोलियां होंगी, जो अपने राज्य का बैनर लेकर आगे बढ़ेंगे। लाल किला मैदान में जनजाति समाज के 75 विभूतियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें तस्वीरों के साथ उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। समागम का आयोजन जनजाति सुरक्षा मंच व जनजाति जागृति समिति द्वारा किया जा रहा है।

वड़ी संख्या में जुटेंगे जनजाति समाज के लोग : यह दिल्ली में अब तक का जनजाति समाज का सबसे बड़ा आयोजन होगा। वइसमें 100 के करीब जनजाति समाज के विशिष्ट लोग एक मंच पर होंगे, उसमें पद्मश्री, अधिकारी, चिकित्सक, अधिवक्ता, समाज सेवी शामिल होंगे।

आज से दिल्ली पहुंचने लगेगा जत्था : समागम में शामिल होने के लिए जनजाति समाज के लोगों का जत्था शुक्रवार से दिल्ली पहुंचने लगेगा। शुक्रवार को बंगाल का जत्था पहुंचेगा। जत्थों का आने का क्रम 24 मई की दोपहर तक चलेगा।

दिल्ली में बिजली नेटवर्क सुधारने को चार वर्ष में खर्च होंगे 17 हजार करोड़

- ऊर्जा मंत्री ने कहा- राजधानी में बिजली की खपत भी बढ़ी है, मास्टर प्लान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

दिल्ली में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बिजली आपूर्ति नेटवर्क को सुधारने के लिए विशेष मास्टर प्लान तैयार किया है। इसे मिशन 2030 का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत बिजली के आधारभूत ढांचे के निर्माण पर अगले चार वर्षों में 17 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि वर्ष 2031 तक दिल्ली में बिजली की मांग 13114 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने की योजना तैयार की गई है। दिल्ली मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। इन कारणों से राजधानी में बिजली की खपत भी बढ़ी है। बिजली मास्टर प्लान का उद्देश्य प्रत्येक मौसम में पूरी दिल्ली में उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

'मिशन 2030' के तहत सरकार ने आने वाले वर्षों में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए निवेश योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत 17 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में भविष्य को ध्यान में रखकर बिजली के आधारभूत ढांचे में सुधार व विकास के लिए काम नहीं किया गया। यदि शीघ्र इस दिशा में काम नहीं किया गया तो परेशानी हो सकती है।

1 और दो जून को दिल्ली में होने वाली पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट को टाल दिया गया है। यह समिट चौथी भारत-अफ्रीका फोरम समिट के साथ मिलकर आयोजित की जानी थी।

मेलोनी को 'मेलोडी' के अलावा पीएम ने भेंट किए मूगा सिल्क के स्टोल

उपहार की कूटनीति ▸ नीदरलैंड्स के पीएम को मधुबनी पेंटिंग व स्वीडन के पीएम को दिया लद्दाखी ऊन का स्टोल

यूएई के राष्ट्रपति को उपहार में दिए गुजरात के केसर आम और मेघालय के अनानास

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों की यात्रा से लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने इन देशों के शीर्ष नेताओं को जो उपहार दिए, उनमें इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टाफियों के पैकेट के अलावा मूगा सिल्क और शिरुई लिली सिल्क के स्टोल, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री राब जेटेन को मछली के डिजायन वाली मधुबनी पेंटिंग और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन को लद्दाखी ऊन का स्टोल शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मेलोनी को दिया गया मूगा सिल्क का स्टोल दुर्लभ कपड़ा है और इसे असम का सुनहरा रेशम भी कहा जाता है जो अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग के लिए मशहूर है। शिरुई लिली सिल्क मणिपुर के दुर्लभ शिरुई लिली से प्रेरित है, जो घंटी के आकार का गुलाबी-सफेद पंखुड़ियों वाला फूल होता है। यह दुनिया में कहीं और नहीं खिलता। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला को संगमरमर की जड़ाई का बाक्स उपहार में दिया गया, जिसमें मशहूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी और कर्नाटक संगीत की गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी की सीडी थीं। नीदरलैंड्स के किंग विलेम-अलेक्जेंडर को जयपुर की ब्लू पोटरी, जबकि क्वीन मैक्सिमा को मीनाकारी व कुंदन के झुमके भेंट किए गए। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री राब जेटेन को मछली के चित्र वाली मधुबनी पेंटिंग भेंट की गई। नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे को सिक्किम में मिलने वाले आर्किड के सूखे हुए फूलों व पत्तियों से तैयार पेंटिंग और आर्किड के पेपरवेट भेंट किए गए। नार्वे के किंग हेराल्ड पंचम को ओडिशा की चांदी की बारीक कारीगरी वाली पाल वाली नाव का माडल और क्वीन सोन्जा को ताड़ के पत्तों पर बनी 'पट्टचित्र' पेंटिंग भेंट की गई।

इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी को भेंट किया गया मूगा सिल्क का स्टोल (ऊपर) और शिरुई लिली सिल्क स्टोल। एएनआइ

नार्वे के प्रधानमंत्री और किंग को भेंट किए गए उपहार। एएनआइ

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को भेंट किए गए उपहार। एएनआइ

डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन को 'बिदरी' शैली का चांदी का गुलदस्ता और यूएई के क्राउन प्रिंस को भेंट किए मिथिला मखाना

स्वीडन के प्रधानमंत्री को लद्दाखी ऊन से बने स्टोल के अलावा 'लोकटक चाय' भी भेंट की गई। यह विशेष तौर पर तैयार चाय होती है। उन्हें हाथ से बना 'शांतिनिकेतन मैसेंजर बैग' भी भेंट किया गया। आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टुन फ्रास्टाडोटिर को बर्फ काटने वाली उस कुल्हाड़ी की प्रतिकृति भेंट की गई, जिसका इस्तेमाल माउंट एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई के दौरान सर एडमंड हिलेरी के शेरपा नार्गे ने किया था। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन को 'बिदरी' शैली का चांदी का गुलदस्ता भेंट किया गया। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो को राजस्थानी 'कमल तलाई पिछवाई' शैली की पेंटिंग भेंट की गई। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को गुजराती 'रोगन' पेंटिंग, गुजराती केसर आम और मेघालय के अनानास भेंट दिए गए। यूएई के क्राउन प्रिंस को कोफ्तगारी कारीगारी की कटार और मिथिला मखाने उपहार में दिए गए। यूएई की क्वीन मदर या राजमाता को महेश्वरी रेशम का कपड़ा और मणिपुरी खुशबूदार चावल 'चक हाओ' भेंट किया गया। यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंग्यु को केरल का लाल चावल, बंगाल का गोबिंदोभोग चावल, बासमती चावल, असमी जोहा चावल और उत्तर प्रदेश का कालानमक चावल के साथ महाराष्ट्र के मोटे अनाजों से बने मिलेट बार उपहार में दिए गए।

शांतिनिकेतन मैसेंजर बैग। एएनआइ

संविधान में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था नहीं : चौधरी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि संविधान में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक भाग के रूप में इसे स्वीकार किया जा रहा है। उन्होंने 2029 से 2034 के बीच आने वाले विधानसभा चुनाव तथा किसी राज्य की सरकार के गिरने के बाद की व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा के दौरान ये बातें कहीं।

गांधीनगर पहुंची संयुक्त समिति के सदस्यों ने राज्य सरकार, विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं नागरिक संगठनों और व्यापारिक संगठनों से चर्चा की। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि 2029 से 2034 के बीच किसी राज्य सरकार के गिर जाने की स्थिति में चुनाव कराएंगे या अन्य कोई व्यवस्था होगी। इस पर उनका कहना था कि इस समयावधि में सरकार के गिर जाने पर शेष समयावधि के लिए ही चुनाव कराए जा सकते हैं।

भारतीय उद्योग परिसंघ सीआइआइ ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि इससे उद्योगों और कारखानों को बार-बार श्रमिकों के अभाव से मुक्ति मिलेगी।

ट्रेनों में आग की घटनाओं के बाद रेल मंत्री का सुरक्षा पर मंथन

- खुफिया तंत्र मजबूत करने व तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने का निर्णय
- शुरुआती जांच में मिले हैं असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत

नई दिल्ली, प्रेट्र : हाल के दिनों में ट्रेनों में आग लगने की कई घटनाओं के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। यह बैठक आग की घटनाओं समेत कई घटनाओं की शुरुआती जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिलने के बाद बुलाई गई थी।

रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, वैष्णव ने दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में देशभर के फील्ड अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। अधिकारियों ने बताया कि आरपीएफ आग की इन घटनाओं की सक्रियता से जांच कर रही है। कई मामलों में रेलवे द्वारा की गई त्वरित और सक्रिय कार्रवाई के कारण बड़ी अनहोनी नहीं हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि खुफिया तंत्र को मजबूत करने और सूचनाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने के अलावा यात्रियों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे यात्रा के दौरान व स्टेशन परिसर में इंतजार करते समय असामाजिक गतिविधियों को रोकने में सहयोग करें। बैठक में तकनीक-आधारित सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय व विभिन्न फील्ड जोन के बीच सुरक्षा समन्वय बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। वैष्णव ने कहा कि रेलवे; ट्रेनों, यात्रियों, स्टेशन परिसरों व विशाल रेल नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआइ, ड्रोन और सीटीटीवी जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है।

अश्विनी वैष्णव। फाइल

ब्रिक्स का मंथन...

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को गांधीनगर में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक 2026 के उद्घाटन सत्र में स्वागत भाषण दिया। यह सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद हो रही है, जिसमें अधिकारियों ने "मध्यस्थता और मध्यस्थता में क्षमता निर्माण के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करने पर ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों की घोषणा" शीर्षक वाले संयुक्त घोषणापत्र के मसौदे को अंतिम रूप दिया। बैठक में ब्राजील, चीन, भारत, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने हाइब्रिड मोड में हिस्सा लिया। प्रेट्र

अनारक्षित कट-आफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बाहर करना गलत

विधि संवाददाता, जागरण • लखनऊ

- हाई कोर्ट ने भर्ती विज्ञापन की शर्त व आयोग के आदेश पर लगाई रोक

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से अधिक अंक लाने के बावजूद मुख्य परीक्षा में शामिल होने से मात्र इस आधार पर वंचित कर दिया जाता है कि वह आरक्षित वर्ग के कट आफ में नहीं आ सका, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन होगा। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा विज्ञापन की संबंधित शर्त तथा राज्य लोक सेवा आयोग के नौ जनवरी 2020 के कार्यालय आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 26 में को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने भावना यादव व अन्य की विशेष अपील पर पारित किया।

अपीलार्थियों ने नौ जनवरी 2020 के आयोग के आदेश और 22 दिसंबर 2025 के भर्ती विज्ञापन की शर्त संख्या-10 को चुनौती दी थी। इस शर्त में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में केवल अंतिम चयन के समय समायोजित किया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा या स्क्रीनिंग चरण में नहीं। एकल पीठ द्वारा अपीलार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में एक निश्चित अंक पाने वाला सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होता है, तो उससे अधिक अंक पाने वाला आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सिर्फ इस आधार पर बाहर कर दिया जाए कि वह आरक्षित वर्ग के कट आफ में नहीं आ सका, यह प्रथमदृष्टया समान अवसर के अधिकार के विपरीत होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलार्थियों की चुनौती समयपूर्व नहीं थी, क्योंकि आयोग का निर्णय और विज्ञापन पहले से स्पष्ट रूप से लागू थे, ऐसे मामलों में परीक्षा होने से पहले हस्तक्षेप करना आवश्यक है, ताकि बाद में जटिलताएं न पैदा हों।

इंजेक्शन से चेहरा चमकाने की अनुमति नहीं

- केंद्रीय औषधि नियामक ने कहा, कानून के तहत इस तरह के सौंदर्य उत्पादों के उपयोग की इजाजत नहीं
- देशभर में फल-फूल रहा ब्यूटी क्लीनिक और वेलनेस सेंटर में सुंदरता बढ़ाने का कारोबार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय औषधि नियामक ने स्पष्ट किया है कि इंजेक्शन के रूप में दिए जाने वाले कास्मेटिक उत्पाद कानून के तहत सौंदर्य प्रसाधनों की परिभाषा में नहीं आते हैं। उपभोक्ताओं, पेशेवरों या ब्यूटी क्लीनिकों द्वारा चेहरा चमकाने के लिए इनके उपयोग की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की यह सलाह देशभर के ब्यूटी क्लीनिकों और वेलनेस सेंटरों में इंजेक्शन के माध्यम से सौंदर्य प्रक्रियाओं की बढ़ती लोकप्रियता के बीच आई है। इस उपाय को कास्मेटिक उपचार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में और इंटरनेट मीडिया पर प्रचार के माध्यम से गैर-सर्जिकल सौंदर्य प्रक्रियाओं की लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसे में इस स्पष्टीकरण का मकसद उपचार के उद्देश्य से कास्मेटिक उत्पादों के दुरुपयोग को रोकना और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इसके साथ ही सीडीएससीओ क्लीनिकों और व्यक्तियों द्वारा भ्रामक विज्ञापन और अनधिकृत कास्मेटिक प्रथाओं पर अंकुश भी लगाना चाहता है। 18 मई को जारी सार्वजनिक सूचना में नियामक ने कहा कि कास्मेटिक्स का उपयोग केवल शरीर की सफाई, सुंदरता बढ़ाने, आकर्षण बढ़ाने या रूप-रंग बदलने के लिए रगड़ने, छिड़कने या स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इंजेक्शन के रूप में दिए जाने वाले उत्पाद सौंदर्य प्रसाधनों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। किसी भी सौंदर्य प्रसाधन को उपभोक्ता/पेशेवर/ब्यूटी क्लीनिक द्वारा इंजेक्शन के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

नियामक ने भ्रामक दावों और सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों में प्रतिबंधित वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ भी चेतावनी दी है। कहा है कि ऐसे उल्लंघनों पर औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम और सौंदर्य प्रसाधन नियम, 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग केवल उनके निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। पेशेवरों या व्यक्तियों द्वारा इनका उपयोग उपचार के लिए नहीं किया जा सकता है। नोटिस में आम लोगों से कहा गया है कि वे ईमेल या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के माध्यम से नियामक को नियमों के उल्लंघन या भ्रामक उपायों की जानकारी दें। उल्लेखनीय है कि सौंदर्य सामग्री निर्माता कंपनियां कई बार भ्रामक दावे करते हैं, जिससे प्रभावित होकर लोग उसका उपयोग करते हैं और चलकर यही उनके लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं।

प्रतीकात्मक

गैर-अनुदानित निजी स्कूलों पर लागू नहीं होगी एसएमसी की गाइडलाइन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- निजी स्कूल संचालकों की आपत्तियों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने दिशा-निर्देशों में किया बदलाव
- पिछले दिनों जारी हुई थी स्कूल प्रबंधन समिति से जुड़ी गाइडलाइन, समाज को भी सौंपी थी जिम्मेदारी

स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) से जुड़ी गाइडलाइन पर निजी स्कूलों की आपत्तियों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को साफ किया है कि ये गाइडलाइन उन निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर नहीं लागू होगी, जिन्हें किसी तरह की सरकारी मदद या अनुदान नहीं मिलता। इससे पहले मंत्रालय ने इस गाइडलाइन को जारी करते हुए कहा था कि यह सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों पर लागू होगी।

निजी स्कूल संचालक समितियों ने इस मुद्दे पर मंत्रालय को भी अपनी चिंता से अवगत कराया था। हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि वह ऐसे स्कूलों को ज्यादा पारदर्शिता, जबावदेही व सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एसएमसी गठित करने लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। मंत्रालय ने अब कहा है कि ये गाइडलाइन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सेक्शन 2 (एन) -चार के तहत आने वाले उन सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होतीं जो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कोई सरकारी अनुदान नहीं लेते हैं।

मंत्रालय ने छह मई को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि शिक्षा सरकार, स्कूलों, अभिभावक व समाज की मिली-जुली जिम्मेदारी है। इस गाइडलाइन के तहत स्कूल संचालन समिति के 75 प्रतिशत सदस्य अभिभावक होंगे। अभिभावक ही इसके अध्यक्ष होंगे।

प्रतीकात्मक

अफ्रीकी देशों से आने वाले के लिए इबोला को लेकर गाइडलाइन जारी

- लक्षण या जोखिम पृष्ठभूमि वाले लोगों को आव्रजन मंजूरी से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्ट करने कहा गया
- परामर्श में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों का विशेष उल्लेख

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने इबोला प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक स्वास्थ्य परामर्श जारी की है, जिसमें लक्षण या जोखिम इतिहास वाले लोगों को आव्रजन मंजूरी से पहले तुरंत हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भारत में अब तक इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा जारी सलाह में विशेष रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों का उल्लेख है। इन सभी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एयरपोर्ट हेल्थ आर्गनाइजेशन (एपीएचओ) द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे पर एडवाइजरी प्रदर्शित की गई है। इसमें उन यात्रियों से भी अपील की गई है, जिनका किसी संदिग्ध या पुष्टि वाले इबोला रोगी के रक्त या शरीर के तरल पदार्थ से सीधा संपर्क हुआ हो। उन्हें हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट करने कहा गया है।

भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत और अफ्रीकी संघ ने 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होने वाले भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का फैसला किया है। शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन यह पता चला है कि अफ्रीका में इबोला वायरस का प्रसार इस निर्णय का कारण था।

नया कदम

एनसीईआरटी ने देशभर के राज्य बोर्ड और एससीईआरटी को दी जिम्मेदारी, पहले चरण में देशभर के शिक्षकों को राज्य स्तर पर किया जा रहा है प्रशिक्षित

बोर्डों की परीक्षा व मूल्यांकन में एकरूपता की तैयारी

अशोक केडियाल • जागरण

देहरादून: देशभर के शिक्षा बोर्डों में परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में एकरूपता लाने की दिशा में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में एनसीईआरटी देशभर के शिक्षकों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित कर रहा है। देश में सबसे अधिक छात्र संख्या वाले सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन) एवं सीआइएससीई (काउंसिल फार द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन) बोर्ड के प्रश्न पत्रों को तैयार करना बड़ी चुनौती है। कई बार आउट आफ सिलेबस के मामले भी सामने आए। इसके अलावा राज्य बोर्डों से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के केंद्रीय बोर्ड के छात्रों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ने के मामले भी केंद्र सरकार के समक्ष रखे गए। इसे देखते हुए सभी बोर्डों में समरूपता लाने को राज्य स्तरीय माडल तैयार किया जा रहा है।

राज्यों में एससीईआरटी के माध्यम से शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इस प्रशिक्षण में वही शिक्षक रहेंगे जो बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने से लेकर प्रश्न बैंक व मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रतिभाग करते आए हैं। इस अभियान का उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रश्न बैंक, प्रश्नपत्र निर्माण, मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षण पद्धति में एकरूपता स्थापित करना है। इसके लिए विभिन्न राज्यों के शिक्षक और शिक्षा विशेषज्ञों को एससीईआरटी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं में कौशल आधारित प्रश्नों, समग्र मूल्यांकन और आधुनिक शिक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।

एससीईआरटी देहरादून में सभी विषयों और प्रदेशभर के टाप 50 शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एससीईआरटी के अपर निदेशक पदमेंद्र सकलानी की मानें तो प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों को प्रश्न बैंक बनने और एनईपी के नए राष्ट्रीय पैटर्न से रूबरू कराया जा रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद सिमल्टी ने बताया कि एनसीईआरटी की ओर से देशभर के केंद्रीय व राज्य बोर्डों में समरूपता लाने के लिए राज्य स्तर पर एससीईआरटी के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में राज्य के ऐसे विषयवार शिक्षक जो बोर्ड के लिए प्रश्न बैंक बनाते हैं, उन्हें अन्य बोर्ड की जानकारी व पैटर्न का एससीईआरटी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षकों का फीडबैक भी लिया जा रहा है।

प्रतीकात्मक

राज्य बार काउंसिलों में 30% महिलाओं का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) ने राज्य बार काउंसिलों में 30 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए योग्यता-आधारित 'सह-विकल्प' तंत्र की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शीर्ष बार निकाय, बीसीआइ ने व्यक्तिपरक नियुक्तियों के बजाय उन महिला उम्मीदवारों का चयन करके 10 प्रतिशत सह-विकल्प कोटा भरने का प्रस्ताव दिया है, जिन्होंने गैर-निर्वाचित लोगों में सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं।

प्रस्ताव का उद्देश्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से महिलाओं के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत सीटों को पूरक करना है, जिससे कुल प्रतिनिधित्व शीर्ष अदालत द्वारा पहले निर्धारित 30 प्रतिशत जनादेश के बराबर हो जाएगा।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

50 बैलेट पेपर गायब होने का मामला सामने आया है पंचायत चुनाव से पहले बिलासपुर में। इससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव में सोलन के कुनिहार में भी दो बैलेट पेपर गायब होने पर आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार, 22 मई, 2026

शुभेंदु बोले–अब सीधे बीएसएफ को सौंपे जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिये

हर सप्ताह पकड़े गए घुसपैठियों की रिपोर्ट भेजनी होगी मुख्यमंत्री कार्यालय

सीएए में नहीं आने पर तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

बंगाल में पुशबैक कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने के अगले ही दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में पकड़े जाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंपा जाएगा। हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नई व्यवस्था बुधवार से लागू हो चुकी है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त तथा रेलवे सुरक्षा बल को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब से किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठिये को अदालत नहीं भेजा जाएगा। उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा, ताकि वापस सीमा पार भेजा जा सके। यह कदम केंद्र सरकार की 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' नीति का हिस्सा है। इसके तहत अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

शुभेंदु ने मठ परिसर में दाखिल होते ही वरिष्ठ संन्यासियों के सामने मत्था टेक नमन किया। प्रेट्र

संन्यासियों के सामने हुए नतमस्तक

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को हावड़ा स्थित बेलूर मठ का दौरा किया। नौ मई को मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद रामकृष्ण मठ एवं मिशन के मुख्यालय की उनकी यह पहली यात्रा है। सुबह पहुंचने पर वरिष्ठ संन्यासियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। शुभेंदु ने मठ परिसर में दाखिल होते ही वरिष्ठ संन्यासियों के सामने मत्था टेककर नमन किया। इसके बाद रामकृष्ण मठ व मिशन के अध्यक्ष स्वामी गौतमानंद जी महाराज से मुलाकात की और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हावड़ा रेलवे स्टेशन या अन्य स्थानों पर यदि कोई ऐसा बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा जाता है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के दायरे में नहीं आता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर बीएसएफ अधिकारियों को सौंप दिया जाए। जिला प्रशासन को हर सप्ताह पकड़े जाने वाले घुसपैठियों की संख्या संबंधी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजनी होगी।

केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार घुसपैठियों की पहचान कर उनका निर्वासन किया जाएगा। इसके अनुसार दो तरह के लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा–पहला जो बिना वैध पासपोर्ट और दस्तावेजों के भारत में प्रवेश किए हों।

दूसरा, जो वैध दस्तावेजों के साथ आए हों लेकिन तय समय समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे हों।ऐसे लोगों की पहचान करने, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने और उन्हें देश से बाहर भेजने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को दिया गया है।

बंगाल के मदरसों में 'वंदे मातरम्' अनिवार्य

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

▸ मदरसों में राष्ट्रगीत अनिवार्य करने पर मुस्लिम संगठनों ने खोला मोर्चा

बंगाल की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान को लेकर बड़ा वैचारिक व राजनीतिक टकराव खड़ा हो गया है। राज्य की शुभेंदु सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' का गायन तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी यह निर्देश अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित सभी माडल मदरसों, शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर भी समान रूप से लागू होगा। यह कदम राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले सभी विद्यालयों में राष्ट्रगीत के सभी छह छंदों को अनिवार्य किए जाने के ठीक एक सप्ताह बाद उठाया गया है।

प्रार्थना में एकरूपता लाने का तर्क: प्रशासनिक गलियारों में इस फैसले को पूरी तरह नीतिगत और अनुशासनात्मक बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों की सुबह की प्रार्थना सभाओं में एकरूपता और अनुशासन स्थापित करना है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूलों के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी भेज दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे राज्य की एकता के लिए एक ऐतिहासिक और जरूरी कदम करार दिया है।

शुभेंदु अधिकारी। फाइल

सरकार के इस फैसले के आते ही राज्य के मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ तीखे तेवर अपना लिए हैं। आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के इस आदेश को चुनौती देते हुए दो-टूक कहा है कि मदरसों में 'वंदे मातरम्' नहीं गाया जाएगा। सरकार को किसी भी समुदाय के धार्मिक शिक्षण संस्थानों के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोलकाता खिलाफत कमेटी के प्रमुख मोहम्मद अशरफ अली कासमी ने कहा कि मुसलमान देश से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार पूजा सिर्फ अल्लाह की जा सकती है।

कर्मियों के सर्कुलर पर विवाद, 24 घंटे में सरकार ने सीमित किया दायरा

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: बंगाल सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के मीडिया से बातचीत और सार्वजनिक टिप्पणी पर नियंत्रण संबंधी सर्कुलर को लेकर राज्य की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में बहस छिड़ गई है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल की ओर से जारी निर्देश में बिना अनुमति मीडिया में बयान देने, लेख लिखने, सरकारी नीतियों की आलोचना करने तथा सरकारी दस्तावेज साझा करने पर रोक की बात कही गई थी। इसे लेकर विपक्ष, वकील समुदाय और मीडिया के एक हिस्से ने सरकार पर कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करने का आरोप लगाया।

विवाद बढ़ने और कानूनी सवाल उठने के महज 24 घंटे के भीतर नवान्न ने नई व्याख्या जारी कर आदेश के दायरे को सीमित कर दिया।

संशोधित निर्देश के अनुसार यह नियम केवल राज्य सरकार के नियमित विभागों, सरकारी बोर्डों, नगर निकायों, निगमों और अन्य अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू होगा।

फलता विस क्षेत्र में पुर्नमतदान, 86.11 प्रतिशत ने डाले वोट

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

▸ लोगों ने कड़ी सुरक्षा में किया अपने मताधिकार का प्रयोग, नहीं दिखे जहांगीर खान, मतगणना 24 को

बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में वर्षों बाद मतदान वाले दिन बिल्कुल अलग नजारा दिखा। न कहीं हिंसा हुई, न वोटों की लूट। लोगों ने कड़ी सुरक्षा के बीच अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार शाम पांच बजे तक 86.11 प्रतिशत की बंपर वोटिंग हुई। उसके बाद भी विभिन्न बूथों पर मतदाताओं की कतारें लगी थीं। मतगणना 24 मई को होगी।

मालूम हो कि हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव के दूसरे व अंतिम चरण के तहत 29 अप्रैल को यहां हुए मतदान में गड़बड़ी की ढेरों शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यहां फिर से मतदान कराने का निर्णय लिया था। गुरुवार सुबह मतदान शुरू होते ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई थीं। महिला और बुजुर्ग मतदाताओं की अच्छी भागीदारी देखी गई। मतदान के दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इलाके के लोगों ने बताया कि उन्हें 10-15 साल बाद मतदान का मौका मिला। तृणमूल के शासनकाल में वोट डालने नहीं दिया जाता था। मतदान के दिन घर से निकलने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी।

मतदान वाले दिन तृणमूल प्रत्याशी रहे जहांगीर खान फलता में नजर नहीं आए। उनके घर व पार्टी कार्यालय में ताला लटका था। मालूम हो कि पुनर्मतदान से 48 घंटे पहले जहांगीर चुनाव से हट गए थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा फलता के लिए की गई विशेष पैकेज की घोषणा को देखते हुए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। मतदान के दौरान पुलिस ने जहांगीर के करीबी सईदुल को गिरफ्तार किया।

फ्लैट विवाद पर सायोनी की सफाई, नाम की समानता से फैली गलतफहमी

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस सांसद सायोनी घोष ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ सह स्वामित्व वाले फ्लैट के मामले पर सफाई दी है। कहा कि कोलकाता नगर निगम की जांच में साफ हो गया है कि जिस फ्लैट को लेकर उनका और सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम जोड़ा जा रहा था, वह किसी अन्य दंपती की संपत्ति है।

सायोनी ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि कोलकाता के 19बी, 7 टैंक्स लेन स्थित फ्लैट की जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि यह संपत्ति अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी सायोनी घोष की है। दोनों नामों की समानता के कारण भ्रम फैल गया और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।

दंपती ने जांच अधिकारियों को दस्तावेज दिखाकर स्पष्ट किया कि उन्होंने करीब तीन वर्ष पहले संयुक्त रूप से यह फ्लैट खरीदा था। नगर निगम और स्थानीय पुलिस की जांच में उन्होंने पूरा सहयोग किया।

तमिलनाडु में राज्य गीत को तीसरे स्थान पर रखने से फिर विवाद

▸ नए मंत्रियों की शपथ में 'तमिल थाई वाझ्थु' को सबसे अंत में गाया गया

▸ द्रमुक ने कहा, यह घटना दर्शाती है कि राज्य को हर क्षेत्र में पीछे धकेला जाएगा

चेन्नई, प्रेट्र : तमिलनाडु में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य गीत 'तमिल थाई वाझ्थु' को अंत में गाए जाने से एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। गुरुवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले 'वंदे मातरम' और इसके बाद 'जन गण मन' गाया गया था। द्रमुक के संगठन सचिव आरएस भारती ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि जिस प्रकार राज्य गीत को क्रम में नीचे धकेला गया है, उसी प्रकार तमिलनाडु को भी हर क्षेत्र में पीछे धकेला जाएगा। मौजूदा प्रशासन तमिल भाषा और उसके सांस्कृतिक रीति-रिवाजों की अवहेलना कर रहा है। पिछले 11 दिनों में यह दूसरा मौका है, जब राज्य गीत बजाए जाने के क्रम पर विवाद हुआ है। इससे पहले 10 मई को मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में भी इस गीत को तीसरे स्थान पर बजाए जाने पर विवाद हुआ था।

भाकपा के प्रदेश सचिव एम. वीरपांडियन ने कहा कि जनता की भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारी पार्टी राष्ट्रगान के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाहती है कि सरकारी कार्यक्रमों में तमिल राज्य गीत को प्राथमिकता दी जाए। माकपा के राज्य सचिव पी. षणमुगम ने बताया कि जब मुख्यमंत्री के समक्ष तमिल गीत को अंत में गाए जाने का मुद्दा उठाया गया, तो उन्होंने प्रशासनिक प्रोटोकाल को स्पष्ट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उसके प्रोटोकाल का पालन करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल की उपस्थिति में सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' का गायन सबसे पहले होता है। द्रमुक प्रवक्ता टीकेएस एलानगोवन ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार भाजपा समर्थक राज्यपाल के दबाव में काम कर रही है।

चेन्नई में गुरुवार को शपथ लेने के बाद कांग्रेस विधायक एस राजेश कुमार (दाएं) को सम्मानित करते तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जोसेफ विजय। प्रेट्र

विजय मंत्रिमंडल का विस्तार, 59 साल बाद सरकार का हिस्सा बनी कांग्रेस: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 23 और विधायकों को मंत्री बनाया। कांग्रेस के दो विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके साथ ही 59 साल बाद कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार का हिस्सा बनी है। अन्य सभी मंत्री टीवीके विधायक हैं। कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाए गए एस. राजेश कुमार को पर्यटन और पी विश्वनाथन को उच्च शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। अन्य मंत्रियों को भी विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने कांग्रेस नेता राजेश कुमार से लिखित शपथ का पालन करने को कहा। दरअसल, शपथ लेते समय राजेश कुमार कांग्रेस नेताओं कामराज, राजीव गांधी और राहुल गांधी की प्रशंसा करने लगे, जिस पर राज्यपाल ने कहा कि यह आपकी शपथ का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस समर्थकों ने पार्टी के दो विधायकों को 21 मई को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का स्वागत किया, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है।

राष्ट्रीय फलक

कोई यदि पुलिस को चैलेंज करे तो उसे 48 घंटे में जवाब दें: सम्राट

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

सम्राट चौधरी

कहा- पुलिस के बल पर स्थापित सुशासन से ही खड़े होंगे उद्योग-धंधे

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यदि कोई पुलिस को चैलेंज करता है तो उसे 48 घंटे में जवाब देना है। पुलिस सुशासन व सख्ती के लिए है। अपराधी किसी भी हालत में नहीं बचे। वह गुरुवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में बैंक आफ बड़ौदा-बिहार पुलिस सैलरी पैकेज के बीमा लाभ वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने इस वक्तव्य से इशारों में तेजस्वी यादव के बयान पर भी टिप्पणी की। कहा कि पुलिस जाति पूछकर गोली नहीं चलाती। कुछ लोगों को अपनी चिंता होती है। कह रहे हैं कि पुलिस एनकाउंटर होता है, उसमें जाति भी पूछनी चाहिए। सम्राट ने कहा कि बिहार की समृद्धि का भी रास्ता पुलिस से जुड़ा है। पुलिस के बल पर ही सुशासन है। सुशासन होगा तो सभी सेक्टर के लिए हमारे रास्ते खुल जाएंगे। फिर उद्योग धंधे भी लगेंगे, इसलिए पुलिस बल से मेरा आग्रह है कि आप सुशासन स्थापित कीजिए, आपके परिवार की चिंता सरकार करेगी। कार्यक्रम में 61 दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों के बीच 37 करोड़ 50 लाख की बीमा राशि का चेक दिया गया। सम्राट ने कहा कि डीजीपी कह रहे कि 150 करोड़ में पुलिसकर्मियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा मिल जाएगी। मैं कहता हूं 150 की जगह 200 करोड़ ले लीजिए, लेकिन पुलिस बल को चिंतामुक्त कीजिए।

पुलिस की तत्परता ने बढ़ाई सीबीआइ की मुश्किल, नहीं मिली नवीन की ट्रांजिट रिमांड

जागरण संवाददाता, बलिया

▸ चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में गिरफ्तार नवीन सिंह को अदालत ने जेल भेजा

▸ गोदाम में छिपाए थे पांच असलहे, सीबीआइ ने वारंट-बी दाखिल किया

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बुधवार को गिरफ्तार नवीन सिंह को सीबीआइ कोलकाता नहीं ले जा सकी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि किसी भी आरोपित की ट्रांजिट या न्यायिक रिमांड से पहले उससे संबंधित समस्त कागजात (विवेचना के संपूर्ण कागजात व मेडिकल रिपोर्ट) के जांच के बाद ही आदेश दिया जाता है। ऐसे में बलिया की अदालत ने नवीन को जेल भेजने का आदेश दे दिया। सीबीआइ ने शाम को ही सीजेएम शैलेश पांडेय की अदालत में समस्त कागजात के साथ वारंट बी के लिए पुनः अर्जी दे दी। इसके तहत पहले से जेल में बंद किसी आरोपित को दूसरे मामले या दूसरी अदालत में पेश करने के लिए आदेश जारी कराया जाता है। बलिया जेल में निर्माण कार्य जारी होने के कारण नवीन सिंह को पड़ोसी जिले मऊ की जेल में रखा गया है।

नवीन सिंह को लेकर बलिया पुलिस की तत्परता ने सीबीआइ का काम मुश्किल कर दिया। केंद्रीय एजेंसी के इनपुट पर यूपी एसटीएफ ने नवीन को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बलिया पुलिस ने फौरन फेफना थाने में उसके खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इस कारण सीबीआइ को उसका ट्रांजिट रिमांड नहीं मिल सका और अदालती प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। पुलिस ने नवीन के खिलाफ फेफना थाने में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 (दो से अधिक हथियारों का अधिग्रहण), धारा 7 (अवैध हथियार रखना), धारा 25 (अवैध हथियारों का परिवहन) और धारा 27 (अवैध हथियार का उपयोग) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नवीन की निशानदेही पर घर से लगभग तीन किमी दूर स्थित शोरूम के गोदाम से पांच असलहे और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं। इनमें 9 एमएम की एक पिस्टल, .32 बोर की दो पिस्टल व दो रिवाल्वर, 45 कारतूस और मोबाइल फोन शामिल हैं।

सीबीआइ की पूछताछ में नवीन ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उसने बताया कि सात मई को बांसडीह के शीतल दवनी निवासी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मनु उसके घर आया था। उसके साथ रसड़ा का राजकुमार सिंह और बांसडीह का गोलू सिंह भी था।

शाह को धमकी मामले में बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकेंगे अभिषेक

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

▸ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध धमकी भरी बयानबाजी का मामला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध धमकी भरी बयानबाजी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी अब बिना अदालत की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि अभिषेक को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिषेक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने 30 जुलाई अथवा अगले आदेश तक अभिषेक के विरुद्ध गिरफ्तारी व सख्त पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

मालूम हो कि गत 15 मई को बिधाननगर साइबर क्राइम थाने में राजीव सरकार नामक व्यक्ति ने अभिषेक के विरुद्ध इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद अभिषेक ने हाई कोर्ट का रूख किया था।

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने अभिषेक के बयान पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि तीन बार के सांसद से इस तरह की टिप्पणी जिम्मेदाराना नहीं मानी जा सकती। एक राष्ट्रीय दल के महासचिव के तौर पर भी इस तरह की टिप्पणी गंभीर है। राज्य में चुनाव बाद हिंसा का काला इतिहास है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि पूछताछ के लिए बुलाना हो तो 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा। कानून के दायरे में ही कार्रवाई होगी। अभिषेक के जांच में सहयोग न करने पर पुलिस अदालत को सूचित कर सकती है। मामले पर आगामी 20 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

बदरीनाथ हाईवे पर लगा 12 किमी लंबा जाम, रेंगते रहे वाहन

चमोली में बदरीनाथ हाईवे पर गुरुवार को विष्णुप्रयाग से ज्योतिर्मठ तक 12 किमी से अधिक दूरी तक लगा जाम। जागरण

जागरण संवाददाता, चमोली

बदरीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण गुरुवार को बदरीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी-विष्णुप्रयाग से ज्योतिर्मठ तक 12 किमी से अधिक लंबा जाम लगा रहा। इससे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देर रात तक बदरीनाथ हाईवे यात्री वाहनों से पैक था और वाहन रेंगते हुए चल रहे थे। बदरीनाथ हाईवे पर गोपेश्वर से मारवाड़ी तक छह से अधिक जगहों पर हाईवे धंसा हुआ है। इसके अलावा नगर में निर्माण कार्यों में रोक लगने के कारण हाईवे चौड़ीकरण का काम भी नहीं हो पाया है। इस 12 किमी क्षेत्र में हाईवे संकरा और क्षतिग्रस्त होने के चलते आए दिन जाम लग रहा है।

अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जेसीबी, पोकलैंड, हाइड्रा, मलबा हटाने वाली मशीनें और पर्याप्त मैनपावर हर समय मौके के समीप तैयार रखे जाएं।

15 वर्ष बाद कटड़ा से शिवखोड़ी तक हेलीकाप्टर सेवा होगी शुरू

जागरण संवाददाता, कटड़ा

▸ उपराज्यपाल ने कटड़ा में नवनिर्मित हेलीपैड का किया उद्घाटन, अगले माह शुरू होगी सेवा

▸ मात्र 12 मिनट में शिवखोड़ी पहुंच दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, सड़क मार्ग से लगते हैं ढाई से तीन घंटे

श्री माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब शिवखोड़ी की यात्रा और अधिक सुगम होने जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटड़ा के हट क्षेत्र में नवनिर्मित हेलीपैड का उद्घाटन किया। 15 वर्ष बाद हेलीकाप्टर सेवा फिर से शुरू होने से शिवखोड़ी में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। श्रद्धालु कटड़ा से मात्र 12 मिनट में शिवखोड़ी में पहुंच दर्शन कर सकेंगे, जबकि सड़क मार्ग से ढाई से तीन घंटे लगते हैं। हेलीकाप्टर सेवा अगले माह शुरू कर दी जाएगी। करीब सात हजार प्रति सवारी इसका किराया होगा।

उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि यह परियोजना जम्मू-कश्मीर में धार्मिक पर्यटन को नई गति प्रदान करेगी। हेलीपैड का निर्माण आधुनिक तकनीक और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए के मानकों के अनुरूप किया है। उन्होंने बताया कि हेलीकाप्टर सेवा से बुजुर्गों, महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों से जूझ रहे श्रद्धालुओं को विशेष राहत मिलेगी।

कटड़ा में नवनिर्मित हेलीपैड से उड़ान भरते हेलीकाप्टर | सभी फोटो श्राइन बोर्ड |

अब सड़क मार्ग से भी चंद्रताल झील तक जा सकेंगे सैलानी

चंद्रताल झील। फाइल

जासं, मनाली : लाहुल स्पीति से चंद्रताल झील को जाने वाली सड़क सात माह बाद पर्यटकों के लिए बहाल हो गई है। चंद्रताल झील रंग बदलने के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। अर्धचंद्राकार झील दिनभर में कई बार रंग बदलती है। अब कुल्लू, मनाली व लाहुल स्पीति में पर्यटन कारोबार और गति पकड़ेगा। मनाली-काजा के बीच चल रहे फोर बाय फोर वाहनों में पर्यटक चंद्रताल झील तक जा सकते हैं।

16 सप्ताह बाद गर्भपात की अनुमति दी है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक संवेदनशील मामले में दुष्कर्म पीड़िता को। कोर्ट ने कहा कि किसी भी पीड़िता को गर्भ रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जो उसकी सहमति के बिना और क्रूरता के फलस्वरूप ठहरा हो।

नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन पर भाजपा सरकारों की लाठियों से डरने वाले नहीं : राहुल

कांग्रेस नेता ने कहा-यह लड़ाई हर उस छात्र के लिए है, जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया

प्रधान के इस्तीफा और पेपर लीक रोकने के लिए सुरक्षित सिस्टम बनने तक रुकेंगे नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक के चलते नीट-यूजी रद किए जाने के बाद राज्यों में चल रहे कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की राज्य सरकारें युवा कांग्रेस तथा एनएसयूआइ के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा रही हैं। मगर कांग्रेस डरने वाली नहीं और हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तथा देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बन जाता। यह लड़ाई हर उस छात्र के लिए है, जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया है।

राजस्थान कांग्रेस के नेतृत्व में जयपुर में गुरुवार को नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए बड़े विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई का प्रदेश कांग्रेस हैंडल से साझा किए गए वीडियो को

जयपुर में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार छोड़ते सुरक्षाकर्मी। एएनआइ

एक्स पर रीपोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा-जब मोदी इटली में टाफी खिलाते हुए रील बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे। नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी और मोदी ने न जिम्मेदारी ली, न धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, न एक शब्द कहा। अब जब छात्र, एनएसयूआइ और कांग्रेस के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं तो भाजपा की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही हैं। जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है, वह जवाबदेही से नहीं, डर से चलती है। पर हम डरने वाले नहीं हैं।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी पेपर लीक पर सरकार को घेरते हुए एक्स पोस्ट में कहा कि जो लोग नीट को साफ-सुथरा नहीं रख सकते, उनसे क्या उम्मीद की जाए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 साल से मौजूदा सरकार में पेपर माफिया हावी है। एक दशक में 100 से ज्यादा परीक्षा लीक और घोटाले सामने आए हैं। इनमें व्यापम घोटाला, 2014 का पीएमटी घोटाला, 2018 का एसएससी घोटाला, 2022 का बीपीएससी घोटाला, 2024 का यूजीसी-नीट घोटाला और 2026 का नीट घोटाला आदि शामिल हैं।

जयपुर से जागरण संवाददाता के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को जयपुर में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हुए प्रदर्शन में राजस्थान के सभी जिलों से नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से भाजपा के प्रदेश कार्यालय की ओर कूच किया तो रास्ते में बेरिकेड्स लगाकर पुलिस ने उन्हे रोक लिया। उधर, बेंगलुरु में कांग्रेस की युवा इकाई ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम सिद्दरमैया ने केंद्र की आलोचना करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

ढोंगी बाबा खरात की अकूत संपत्तियों को जब्त करेगी ईडी

राज्य ब्यूरो, मुंबई : स्वयं को भगवान शिव का अवतार बताने वाले ढोंगी बाबा अशोक खरात उर्फ 'कैप्टन' पर अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। मनी लांड्रिंग मामले में औपचारिक गिरफ्तारी के बाद विशेष पीएमएलए अदालत ने आरोपित को 26 मई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अब ईडी ने खरात और उसके करीबियों की काली कमाई से अर्जित करीब 52 से अधिक बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

स्वयं को मर्चेंट नेवी का पूर्व अधिकारी बताने वाला खरात नासिक में ज्योतिषी बनकर लोगों को ठग रहा था। उसने अंधविश्वास, तंत्र-मंत्र और मौत का डर दिखाकर प्रभावशाली व्यापारियों और आम श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपये की उगाही की। वह इमली के बीज और शहद को 'चमत्कारी' बताकर लाखों में बेचता था।

इतना ही नहीं, उसने अपने दफ्तर में नशीला पदार्थ पिलाकर कई महिलाओं का यौन शोषण किया और अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। नासिक पुलिस ने 18 मार्च को एक विवाहित महिला की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया था। फिलहाल उसके खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और नरबलि-काला जादू रोधी कानून के तहत एक दर्जन एफआइआर दर्ज है। इनकी जांच एसआइटी कर रही है।

'राष्ट्रपति के पास राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विवि कर्मी को बर्खास्त करने का पूरा अधिकार'

- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया
- इसमें कहा गया था, उनके पास ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के 'विजिटर' होने के नाते भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और उसकी सेवाएं समाप्त करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

यह पूरा मामला अमेठी स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के 'पहले रजिस्ट्रार' जितेंद्र सिंह से जुड़ा है। उनकी नियुक्ति साल 2019 में विश्वविद्यालय अधिनियम के विशेष प्रविधानों के तहत हुई थी। लेकिन नियुक्ति के बाद से ही उनका कार्यकाल कानूनी विवादों में घिर गया। साल 2020 में प्रोबेशन अवधि के दौरान ही उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जिसने एक लंबी कानूनी लड़ाई को जन्म दिया। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिसंबर 2021 में उन्हें बहाल तो किया गया, लेकिन उसी दिन एक नई जांच लंबित होने के कारण दोबारा निलंबित कर दिया गया। जब जांच समिति ने उन पर लगे

प्रतीकात्मक

अनुशासनहीनता और गंभीर अवज्ञा के आरोपों को सही पाया, तो अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति ने 'विजिटर' के रूप में उनकी बर्खास्तगी को मंजूरी दे दी थी। हाईकोर्ट ने इस बर्खास्तगी को यह कहते हुए रद कर दिया था कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के पास है, न कि विजिटर या मंत्रालय के अधिकारियों के पास।

पीठ ने हाईकोर्ट की इस व्याख्या को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए विजिटर द्वारा शक्ति का प्रयोग पूरी तरह उचित और न्यायसंगत है।

उप्र में सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्यार्थी पहनेंगे यूनिफार्म

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल ने दिए निर्देश, छात्राओं के लिए रोजगारपरक कोर्स, गुणवत्ता पर जोर

उप्र के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए यूनिफार्म लागू की जाएगी। अभी कुछ महिला कालेजों व सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों में यूनिफार्म लागू है, लेकिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे सभी संस्थानों में लागू करने को कहा है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जन भवन में जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी से संबद्ध शासकीय और वित्तपोषित महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक में महाविद्यालयों की कमियों पर गंभीर चिंता जताई। छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक से अधिक रोजगारपरक और वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। उन्होंने ब्यूटीशियन, मेहंदी, जीएसटी, बिंदी निर्माण, अकाउंटेंसी और मिलेट आधारित व्यंजन जैसे पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कहा ताकि छात्राएं स्वरोजगार और रोजगार के अवसर पा सकें। सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में ऐसी समितियां बनाने के निर्देश दिए, जहां छात्र-छात्राएं अपनी समस्याएं खुलकर रख सकें। शिक्षकों को समय से कक्षाओं में जाने, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और गुरु की गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए। जिन कालेजों में शिक्षकों की कमी है, वहां आनलाइन शिक्षण और अन्य संस्थानों के सहयोग से पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा।

राज्यपाल ने कृषि विषय पढ़ाने वाले महाविद्यालयों को जैविक खेती को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को इसके लिए प्रेरित करने को कहा। कंपनियों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रोजेक्ट आधारित पढ़ाई, तकनीकी ज्ञान, नियमित वर्कशाप और खेलो इंडिया अभियान से विद्यार्थियों को जोड़ने पर भी जोर दिया।

महाराष्ट्र में मवेशी तस्करी के आदतन अपराधियों पर लगेगा मकोका

मुंबई, प्रेट्र : देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक परिपत्र जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मवेशी तस्करी के आदतन अपराधियों, गिरोहों और संगठनों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कड़ी कार्रवाई करें। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र में मवेशियों का अवैध परिवहन, अनधिकृत वधशालाओं और अवैध वध को रोकने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि संबंधित पुलिस तंत्र को नियम के अनुसार मामलों की जांच करनी चाहिए और संगठित और आदतन पशु तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों, गिरोहों या संगठनों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। सरकार ने कहा कि राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और भार ढोने वाले पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएं और उनके वध पर प्रतिबंध लगाएं।

सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक जिले में कम से कम पांच क्रिटिकल केयर एंबुलेंस रखने का आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- देशभर के अस्पतालों में विशेषज्ञ समिति से निर्धारित आइसीयू मानदंड स्वीकार कर लागू करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक जिले में वेंटीलेटर की सुविधा वाली कम से कम पांच क्रिटिकल केयर एंबुलेंस रखें। कोर्ट ने अस्पतालों के आइसीयू के बारे में विशेषज्ञ समिति द्वारा तय मानदंडों को स्वीकार करते हुए सभी राज्यों को पहले स्तर के आइसीयू मानदंड यानी आइसीयू लेबल-वन लागू करने को भी कहा है। साथ ही उनके यहां उनमें जो कमियां है, उन्हें तय समयसीमा में दूर करने की योजना 31 जुलाई तक सौंपने को कहा है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने बुधवार को अस्पतालों में आइसीयू सुरक्षा नियमों और देशभर के लिए समान मानक नियम की मांग पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। कोर्ट ने मरीजों के अस्पतालों तक स्थानातंरण के मुद्दे पर विचार करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे हर जिले में

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

वेंटिलेटर की सुविधा युक्त कम कम पांच क्रिटिकल केयर एंबुलेंस उपलब्ध कराएं। इसके लिए राज्य कारपोरेट कंपनियों के सीएसआर फंड से अनुदान ले सकते हैं या एनजीओ से मदद ले सकते हैं। इसके लिए जो पैसा एकत्र होगा उसे अलग खाते में रखा जाएगा।

पिछली सुनवाई पर न्यायमित्र करण भरिहोक और केंद्र की ओर से एएसजी ऐश्वर्य भाटी ने अस्पतालों में आइसीयू यूनिट के मानक दिशानिर्देश तय करने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। मालूम हो कि आइसीयू भी तीन स्तर के होते हैं- लेबल वन, लेबल टू और लेबल थ्री। अभी पहले स्तर के मानदंड यानी लेबल-वन लागू किए जाएंगे। कोर्ट ने राज्यों से कहा कि वे 31 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल कर लेबल-वन के निर्धारित मानकों के तहत उनके यहां जो कमियां हैं, उसे तय समयसीमा में पूरा करने की योजना दें। कोर्ट ने भारतीय नर्सिंग परिषद से कहा कि वह नर्सिंग कालेजों में आइसीयू केयर की ट्रेनिंग कराने और कालेजों से संबद्ध अस्पतालों व आइसीयू यूनिट से दूरी के बारे में रिपोर्ट दे। परिषद के अधीन करीब 800 नर्सिंग कालेज हैं। कोर्ट यह जानकर हतप्रभ था कि नियमों के मुताबिक नर्सिंग कालेजों से अस्पताल की दूरी 30 किलोमीटर तक हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि संबद्ध कालेज की दूरी तो एक-दो किलोमीटर ही होनी चाहिए। मामले में 13 अगस्त को फिर सुनवाई होगी।

कानपुर, मेरठ और भुवनेश्वर में भी यूपीएससी के केंद्र, यहां 23 हजार देंगे परीक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने गुरुवार को कहा कि कानपुर, मेरठ और भुवनेश्वर में भी परीक्षा केंद्र होंगे। इन केंद्रों को शामिल करने के साथ सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए केंद्रों की कुल संख्या 80 से बढ़कर 83 हो गई है। 23,000 से अधिक अभ्यर्थी इन तीन नए केंद्रों पर परीक्षा देंगे।

यूपीएससी ने कहा, "लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने इन नए केंद्रों पर आवेदन किया है, जिससे सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 के लिए आसपास के केंद्रों पर भीड़ कम हो गई है।" भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस), और भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) सहित अन्य सेवाओं में भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा प्रतिवर्ष तीन चरणों में आयोजित की जाती है। इस साल की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को आयोजित होने वाली है। आयोग ने कहा कि उसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 8,19,372 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

एनटीए महानिदेशक बोले-राधाकृष्णन समिति की 70% सिफारिशों पर अमल

प्रथम पृष्ठ से आगे

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के निदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक नहीं हो सकते हैं। उन्होंने परीक्षाओं से जुड़े प्रोटोकाल की जानकारी दी। साथ ही बताया कि राधाकृष्णन समिति की करीब 70% सिफारिशों को वह अमल में ला चुके हैं। बैठक में एनटीए को सुझाव भी दिया गया कि प्रश्न पत्र के 10 सेट बनवाए जाएं और उन्हें मिक्स करके अलग-अलग राज्यों में भेजा जाए। इससे यदि पेपर लीक भी होगा तो वह सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित होगा।

नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार को नई दिल्ली में संसदीय समिति के समक्ष पेश होने जाते एनटीए निदेशक अभिषेक सिंह। एएनआइ

पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, नरेन्द्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि

- तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदुर में 21 मई को राजीव की हत्या कर दी गई थी
- 31 अक्टूबर 1984 से दो दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी

नई दिल्ली, एएनआइ : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गुरुवार को देश ने उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से दो दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 21 मई को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदुर में राजीव की हत्या कर दी गई थी।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राष्ट्रीय राजधानी में वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी।

कांग्रेस ने श्रद्धंजलि देते हुए कहा, राजीव गांधी जी का दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण और उनके विचार कांग्रेस परिवार को सदा प्रेरित करते रहेंगे। पी. चिदंबरम, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ कई पार्टी

गुरुवार को नई दिल्ली में वीर भूमि पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 35वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। एएनआइ

कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मल्लिकार्जुन खरगे ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर राजीव को "भारत का एक असाधारण सपूत" बताया और उनके द्वारा शुरू की गई पहलों का उल्लेख कर उसकी सराहना की।

आरोपित पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के मकान पर चलेगा बुलडोजर

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के पूर्व वित्तीय और प्रशासनिक विवादों में घिरे पूर्व प्रिंसिपल डा संदीप घोष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कोलकाता नगर निगम ने उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेते हुए उनके बेलीघाटा स्थित आवास के अवैध हिस्से को ढहाने का निर्देश जारी किया है।

नगर निगम के सूत्रों के अनुसार, बेलीघाटा स्थित इस मकान के खिलाफ अंशुमान सरकार नामक व्यक्ति ने अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले पर चली लंबी सुनवाई के बाद, गत 14 मई को निगम ने अंतिम आदेश पारित किया। आदेश के तहत मकान की छत पर बने अवैध हिस्से को अगले 45 दिनों के भीतर पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा। इस इमारत में मुख्य रूप से तीन नियमों का घोर उल्लंघन पाया गया है। छत पर बिना किसी अनुमति के एक 'परगोला' (छज्जा जैसी संरचना) खड़ी कर दी गई थी, जो मूल बिल्डिंग प्लान का हिस्सा नहीं थी।

सुबूत मिटाने और साजिश के आरोपों की नए सिरे से जांच करेगी एसआइटी

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

आरजी कर कांड में बड़ा मोड़

- घटना की रात डिनर से लेकर पीड़िता के अंतिम संस्कार तक के घटनाक्रम की जोड़ी जाएंगी कड़ियां

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज और अस्पताल के बहुचर्चित दुष्कर्म व हत्या मामले में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले में सुबूतों को नष्ट करने और पूरी घटना को दबाने के गंभीर आरोपों की नए सिरे से जांच करने का एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने मामले की गहन पड़ताल के लिए सीबीआइ के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक की अगुआई में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। टीम के बाकी दो सदस्यों का चयन अगले 48 घंटों के भीतर कर लिया जाएगा। मालूम हो कि अगस्त 2024 में हुई इस वारदात के बाद नागरिक स्वयंसेवक संजय राय को जनवरी 2025 में कोर्ट द्वारा उम्रकैद सुनाई जा चुकी है।

सीबीआइ को 25 जून तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश : हाई कोर्ट ने एसआइटी को उस रात पीड़िता द्वारा डिनर किए जाने के समय से लेकर अगले दिन उसके अंतिम संस्कार तक के पल-पल के घटनाक्रम और कड़ियों को फिर से जोड़ने को कहा है। सीबीआइ को किसी भी संदिग्ध या आवश्यक व्यक्ति से पूछताछ करने का पूरा अधिकार दिया गया है। गौरतलब है कि पीड़िता के माता-पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर आशंका जताई थी कि इस जघन्य कृत्य में एक से अधिक लोग शामिल थे और तत्कालीन प्रशासन ने असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश की थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआइ को निर्देश दिया है कि वह घटना स्थल का दोबारा दौरा करे, केस डायरी, आडियो-वीडियो रिकार्डिंग्स और तस्वीरों समेत सभी दस्तावेज की री-वेरिफिकेशन करे और आगामी 25 जून तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपे।

महत्वपूर्ण निर्णय

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने किया स्पष्ट-मानवाधिकार आयोग आदेश जारी नहीं कर सकता, फरीदाबाद के एक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश रद

मानवाधिकार आयोग कोर्ट नहीं, केवल सिफारिशी संस्था

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) अदालत की तरह बाध्यकारी आदेश या निर्णय जारी नहीं कर सकता। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एनएचआरसी केवल एक सिफारिशी संस्था है और उसके पास न्यायालय जैसी निर्णायक शक्तियां नहीं हैं।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने फरीदाबाद से जुड़े एक मामले में एनएचआरसी द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की। आयोग ने मामले में आपराधिक जांच स्थानांतरित करने, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने और उन्हें वर्तमान पदस्थापन से हटाने जैसे निर्देश जारी किए थे।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई की। अदालत ने माना कि यह मामला केवल एक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा बड़ा कानूनी प्रश्न यह है कि क्या मानवाधिकार आयोगों की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं और क्या वे संवैधानिक अदालतों जैसी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि इसका उत्तर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की स्पष्ट भाषा में ही निहित है।

अदालत ने टिप्पणी की कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कानून में किसी अधिकार के बिना विवादित निर्देश जारी कर दिए। हाई कोर्ट ने अधिनियम की संरचना और प्रविधान का हवाला देते हुए कहा कि आयोग केवल सरकार को कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। इसमें पीड़ित को मुआवजा देने या मानवाधिकार उल्लंघन में शामिल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करना शामिल हो सकता है, लेकिन वह सीधे आदेश जारी नहीं कर सकता।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एनएचआरसी को केवल सिफारिशी संस्था मानने का अर्थ यह नहीं है कि वह पूरी तरह शक्तिहीन हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर आयोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और वहां से निर्देश या आदेश प्राप्त कर सकता है।

बंगाल में नहाने लायक हो गया गंगा का अधिकांश हिस्सा

नई दिल्ली, प्रेट्र : गंगा नदी का वह भाग जो पहले अत्यधिक प्रदूषित था अब काफी साफ हो चुका है। दावा किया गया है कि बंगाल में गंगा का अधिकांश हिस्सा अब नहाने लायक हो गया है।

नमामि गंगे के अनुसार प्रवाह क्षेत्र वाले अन्य राज्यों से सीवेज और प्रदूषक को वहन करने के बावजूद प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय सुधार दिख रहा है। बंगाल में ही गंगा नदी समुद्र में मिलती है। 'नमामि गंगे' गंगा नदी का प्रदूषण समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने का मिशन है।

नमामि गंगे ने यह भी कहा कि बंगाल में उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग से संबंधित नीतिगत कार्य लगभग पूरा हो चुका है। राज्य की उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग नीति को अगले दो महीनों के भीतर अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है।

स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (एमएमसीजी) ने कहा कि एक्स पर

- दावा - राज्य में गंगा नदी के प्रदूषण में आया उल्लेखनीय सुधार
- उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग संबंधी नीतिगत कार्य लगभग पूर्ण

प्रतीकात्मक

पोस्ट में कहा कि जब तक गंगा नदी बंगाल पहुंचती है, तब तक वह हिमालय से लेकर प्रवाह क्षेत्र में स्थित हर राज्य, हर शहर, हर नाले का संयुक्त भार वहन कर रही होती है। यही वह हिस्सा है जिसमें प्रदूषण में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन 'नमामि गंगे' पहल को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है।

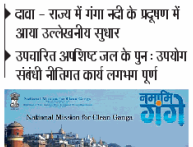

एमएमसीजी ने पिछले सात वर्षों में जल की गुणवत्ता में आए बदलाव को रेखांकित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रदूषित नदी क्षेत्रों (पीआरएस) के आकलन का हवाला दिया। नमामी गंगे के अनुसार, बंगाल में त्रिवेणी से डायमंड हार्बर तक फैले नदी के हिस्से को 2018 में "प्राथमिकता तीन" प्रदूषित नदी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सीपीसीबी के नवीनतम आकलन के अनुसार बंगाल में गंगा के अधिकांश हिस्से अब स्नान-योग्यता मानकों के अनुरूप हैं, केवल बहरामपुर से डायमंड हार्बर तक का निचला हिस्सा ही प्राथमिकता पांच श्रेणी के अंतर्गत है। हालांकि नवीनतम आकलन में प्रदूषित क्षेत्र भौगोलिक रूप से लंबा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक प्रदूषण भार में काफी कमी आई है। मानचित्र पर लंबी रेखा नजर आती है, लेकिन पानी में प्रदूषण काफी कम है।

500 जिलेटिन छड़ों के साथ राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) ने सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। आरोपितों के पास विस्फोटक सामग्री के वैध दस्तावेज नहीं थे।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार, 22 मई, 2026

रेलवे स्टेशन पर आग की आहट मिलते ही खुल जाएगा 'रिले रूम' का ताला

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- स्टेशन मास्टर के पास सीलबंद डिब्बे में होगी एक अतिरिक्त चाबी
- ताला खोलने के लिए एसएंडटी स्टाफ की मौजूदगी की अनिवार्यता खत्म

आग की घटना के कारण ट्रेनों के सिग्नल सिस्टम में कोई खराबी न आए और ट्रेनों के आवागमन में विलंब न हो, इसके लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर आग लगने या आपातकालीन स्थिति में 'रिले रूम' (वह कमरा जहां से ट्रेनों के सिग्नल कंट्रोल होते हैं) को स्टेशन मास्टर खोल सकेंगे। उनके पास सीलबंद डिब्बे में एक अतिरिक्त चाबी रहेगी। जैसे ही रिले रूम में धुआं दिखे या फायर अलार्म बजेगा, स्टेशन मास्टर सील तोड़कर दरवाजा खोल सकेंगे।

यह फैसला मथुरा के पास रेलवे स्टेशन के रिले रूम में आग लगने के दौरान चाबी मिलने में हुई देरी को देखते हुए लिया गया है। 10 मिनट देर से चाबी मिलने के कारण सिग्नल सिस्टम जल गया था और ट्रेनों का संचालन घंटों ठप रहा था। किसी भी रेलवे स्टेशन का रिले रूम उस स्टेशन का कंट्रोल सेंटर है। यहीं से तय होता है कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफार्म पर आएगी और किसे लाल या हरा सिग्नल मिलेगा। सुरक्षा कारणों से यह कमरा हमेशा डबल लाक में बंद रहता है। पहले नियम यह था कि तकनीकी टीम की मौजूदगी के बिना इसे नहीं खोला जा सकता था। अब आपातकालीन स्थिति में स्टेशन मास्टर चाबी का उपयोग करने के तुरंत बाद इसकी जानकारी रिले रूम रजिस्टर में दर्ज करेंगे और काम पूरा होने के बाद तकनीकी स्टाफ द्वारा इसे फिर से सील किया जाएगा।

इस संबंध में जारी आदेश को एनसीआर समेत सभी जोन में लागू कर दिया गया है। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रिले रूम के लिए बोर्ड के सुरक्षा निर्देश लागू कर दिया गया है।

भीषण गर्मी से बिगड़ने लगी सेहत, बढ़े हीट स्ट्रोक के मामले

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- बांदा पांचवें दिन भी देश में सबसे गर्म, कहर ढा रहीं गर्म हवाएं
- दिल्ली और लखनऊ के अस्पतालों में बढ़े ब्रेन स्ट्रोक के मरीज

पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से बेहाल है। उत्तर प्रदेश का बांदा 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गुरुवार को पांचवें दिन भी देश का सबसे गर्म शहर रहा। चिंता की बात यह है कि अत्यधिक तापमान और आग उगलती लू के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है। राजधानी दिल्ली में हीट स्ट्रोक के दो मामले सामने आए हैं। इनमें एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया है, दूसरे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। लखनऊ स्थित लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के न्यूरोलाजी वार्ड में 32, केजीएमयू में 28 और एसजीपीजीआइ में 20 ब्रेन स्ट्रोक के रोगी भर्ती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर उपचार नहीं मिलने पर हीट स्ट्रोक जानलेवा साबित हो सकता है।

स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभों के अभाव में इस साल मैदानी क्षेत्रों में खासी गर्मी पड़ रही है। तापमान तो सामान्य से अधिक चल ही रहा है, लू वाली स्थिति भी बनी हुई है। बता दें, भीषण गर्मी के चलते देश के कई हिस्सों में जलसंकट भी हो गया है।

जल के साथ जान का संकट : भीषण गर्मी के बीच गुजरात के वलसाड में जल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर 45 फीट से ज्यादा गहरे कुएं में उतरकर पानी निकालना पड़ रहा है। तेजी से गिरते भूजल स्तर से जीवन संघर्ष बन गया है। यह चित्र जल प्रबंधन के साथ इसके दीर्घकालिक समाधान पर भी प्रश्नचिह्न उठाता है। एएनआइ

आइएमडी के अनुसार, दिल्ली में मई महीने की लगभग 14 सालों में गुरुवार की रात सबसे गर्म रात रिकार्ड की गई, जिसमें न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन के समय अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में करीब दो सप्ताह से भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। खासकर, बांदा, झांसी, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के जिलों में अधिकतम तापमान हर दिन रिकार्ड बना रहा है। प्रयागराज में 46.6, वाराणसी में 45.6, हमीरपुर 45.2, सुल्तानपुर 45.2, उरई 45 और आगरा 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। पंजाब में फरीदकोट का तापमान 45.9, बिहार में डेहरी रोहतास का 44.6 डिग्री सेल्सियस रहा तो झारखंड में पलामू, गढ़वा और चतरा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। बिहार में अरवल, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पटना के डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने सभी सरकारी-निजी स्कूलों में पांचवी तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहीं, छह से आठवीं तक की कक्षाएं अब सुबह 10.30 बजे तक ही संचालित की जाएंगी। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पतालों की आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है।

नमक का घोल पीएं

दिल्ली में आरएमएल अस्पताल मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर और हीट स्ट्रोक नोडल आफिसर प्रो. डा. अजय चौहान ने लोगों को सलाह दी कि वे हाइड्रेटेड रहें, नमक वाले तरल पदार्थ लें, सीधे धूप में जाने से बचें और बाहर शारीरिक काम करते समय छायादार जगहों पर चले जाएं। दोपहर के सबसे गर्म समय में बाहर निकलने से बचना चाहिए, प्यास न लगने पर भी बार-बार नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी पीना चाहिए, हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए, और हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए ताजे फल और तरल पदार्थ लेने चाहिए। ज्यादा कैफीन, शराब और जोरदार शारीरिक कसरत से बचें।

उत्तराखंड में धधक रहे नौ जिलों के वन, जंगल की आग से फायर वाचर की मौत

वनाग्नि की 309 घटनाओं ने 257 .27 हेक्टेयर जंगल के क्षेत्र को लिया अपनी चपेट में

चारधाम यात्रा मार्ग के चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी के जंगल भी प्रभावित

जागरण संवाददाता, चमोली

उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। राज्य के 9 जिले वनाग्नि की चपेट में हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी व उत्तरकाशी के जंगलों में भी आग लगी है। हालांकि, चारधाम यात्रा निर्बाध है। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत व पिथौरागढ़ के जंगल भी जल रहे हैं। वन विभाग के सामने जंगलों में लगी आग पर नियंत्रण की चुनौती है।

बुधवार रात चमोली में बिरही क्षेत्र के जंगल में लगी आग की चपेट में आकर वन विभाग के फयार वाचर राजेंद्र सिंह की मौत हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वह बुरी तरह झुलस गया था। बदरीनाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेश दुबे ने कि राज्य में इस वर्ष आगजनी की 309 घटनाओं के कारण 257.27 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है।

चमोली में जंगलों की आग बुझाते फायरकर्मी। साभार : फायर विभाग

चमोली के बिरही क्षेत्र में जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिश में वन विभाग के फायर वाचर राजेंद्र सिंह लपटों की चपेट में आ गए और चट्टान से नीचे खाई में गिर गए। उनकी मौके पर ही उनकी मौत हो गई। चमोली जिले में बदरीनाथ हाईवे के समीप चीड़ का जंगल धू-धूकर जल रहा है। आग बुझाने के लिए वन विभाग ने बुधवार दोपहर बाद चमोली रेंज के 15 फायर वाचरों की टीम प्रभावित क्षेत्र में भेजी, जिसमें राजेंद्र सिंह भी शामिल थे।

पिछले कुछ दिनों से तामपान में आए उछाल और सूखे पत्तों, लकड़ियों के कारण जंगल में आग तेजी से फैल रही है। पौड़ी के जंगलों आगजनी की सर्वाधिक 39 घटनाएं हुई हैं, जिसमें अब तक 53.9 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा।

रुद्रप्रयाग जिले में 0.66 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा है। उत्तरकाशी में आग लगने की 12 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे 13.8 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। टिहरी में आगजनी की 18 घटनाओं में 12.70 हेक्टेयर जंगल को क्षति पहुंची है। चमोली जिले में 26 घटनाओं में 23 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा है।

अल्मोड़ा जिले के जंगलों में आगजनी की घटनाओं के बाद डीएम अंशुल सिंह के निर्देश पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध पांच प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। चंपावत जिले में बुधवार शाम जंगल में लगी आग मंदिर तक पहुंच गई, जिससे मंदिर के पास रखी लकड़ी की शटरिंग जलकर राख हो गई। पिथौरागढ़ में डीडीहाट, गंगोलीहाट और बेरीनाग वन प्रभाग के जंगल भी धू-धूकर जल रहे हैं।

वन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना के लिए लगाने पर एनजीटी सख्त

अंकुर अग्रवाल, जागरण, देहरादून: एक तरफ उत्तराखंड के जंगल भीषण गर्मी में धधक रहे हैं, आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, पहाड़ों में संकट गहराता जा रहा है और दूसरी तरफ वन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना के काम में लगा दी गई है। इस मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने तीखा रुख अपनाया है। एनजीटी की प्रधान पीठ ने उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हाफ) से पूछा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद वन विभाग के कर्मचारियों को गैर-वन कार्यों में क्यों लगाया गया। मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी। एनजीटी एक मामले में सुनवाई के बाद यह कार्यवाही की है। शुरुआत ऋषिकेश-देहरादून मार्ग स्थित बड़कोट वन रेंज में सूखी पत्तियां जलाने से हुए पर्यावरणीय नुकसान से हुई थी, लेकिन सुनवाई में मामला वन विभाग की कार्यप्रणाली व संसाधनों की तैनाती तक पहुंच गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि 25 मार्च को जारी राज्य सरकार के आदेश के तहत वन विभाग के कर्मचारियों को जनगणना कार्य में लगाया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 15 मई 2024 के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें साफ कहा गया था कि वनकर्मियों व वन विभाग के वाहनों का इस्तेमाल चुनाव, चारधाम यात्रा या अन्य गैर-वन गतिविधियों में नहीं किया जाना चाहिए।

डीजल की मांग में वृद्धि की वजह खुदरा पंपों की ओर बढ़ते थोक खरीदार

- सरकार ने कहा - फसल कटाई का मौसम होने की वजह से भी डीजल की मांग बढ़ी
- देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और एलपीजी की आपूर्ति भी सामान्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और एलपीजी की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। साथ ही कहा कि थोक डीजल उपभोक्ताओं के खुदरा पेट्रोल पंपों की ओर बढ़ते रुख के कारण देश में कुछ स्थानों पर ईंधन की मांग में बढ़ोतरी जरूर हुई है। थोक व खुदरा कीमतों में 40-42 रुपये प्रति लीटर का अंतर होने के कारण यह हालात पैदा हुए हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि कुछ पेट्रोल पंपों पर मांग में 20-30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके पीछे पहली वजह है कि फसल कटाई का मौसम होने से डीजल की मांग बढ़ना और दूसरे, थोक उपभोक्ता के खुदरा पंपों से डीजल लेना। इस कारण कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों में ईंधन की कमी जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप कारों और दोपहिया वाहनों को ईंधन प्रदान करते हैं। पेट्रोल पंपों पर ईंधन लागत से नीचे बेचा जा रहा है जबकि थोक आपूर्ति सामान्यतः बाजार मूल्य पर होती है। थोक खरीदार जैसे राज्य सड़क परिवहन की बसें और टेलीकाम टावर जो पावर जेनसेट्स में डीजल का उपयोग करते हैं, को ईंधन थोक आपूर्ति प्वाइंटों से खरीदना चाहिए। शर्मा ने नागरिकों से अपील की कि वे घबराहट में खरीदारी न करें। भारत के पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति है और रिफाइनरियां घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं। रिफाइनरियां प्रतिदिन 46,000-47,000 टन एलपीजी का उत्पादन कर रही हैं।

पश्चिम एशिया में सभी भारतीय समुद्री नाविक सुरक्षित

एएनआइ के अनुसार बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव मुकेश मंगल ने कहा है कि पश्चिम एशिया में फंसे सभी भारतीय समुद्री नाविक सुरक्षित हैं। क्षेत्र में चल रहे तनाव के बीच सरकार ने 3300 से अधिक भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। पिछले 72 घंटों में ही 99 लोग आए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में होर्मुज स्ट्रेट में 13 भारतीय झंडे वाले जहाज और एक भारतीय स्वामित्व वाला जहाज अभी भी हैं।

त्विषा की मौत के बाद 11 घंटे में सास गिरिबाला ने किए थे 30 काल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल

- दावा- पूर्व जज समेत कई सरकारी अधिकारियों से की बात, सीसीटीवी से छेड़छाड़ की आशंका
- पुलिस से पहले घर आया सीसीटीवी मेंटेनेंस मैकेनिक, डीवीआर जब्त, फुटेज में तिथि व समय गलत

नोएडा की 31 वर्षीय त्विषा शर्मा की मौत के बाद उसकी सास व रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पुलिस मामले में नई धाराएं जोड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल, काल डिटेल में है कि त्विषा की मौत के बाद के 11 घंटे के भीतर गिरिबाला ने करीब 30 लोगों को फोन किया। त्विषा के मायके वालों का आरोप है कि इनमें कई काल पूर्व न्यायिक अधिकारियों, प्रभावशाली लोगों और सीसीटीवी कैमरों के मेंटेनेंस करने वाले मैकेनिक को किए गए।

स्वजन का आरोप है कि पूर्व जज ने वारदात के बाद तत्काल पुलिस को सूचना देना जरूरी नहीं समझा। जबकि घर से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है। इसके विपरीत, उन्होंने पहले सीसीटीवी मेंटेनेंस करने वाले मैकेनिक को घर बुलाया। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी की डीवीआर जब्त कर लिया है। जांच में सामने आया कि त्विषा की मौत से पहले के सीसीटीवी फुटेज में तिथि और समय गलत दर्ज थे। ऐसे में साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। पूर्व जज से बातचीत करने नवदुनिया की टीम गुरुवार को उनके घर पहुंची। उनके घरेलू सहायक ने बताया कि वह घर में मौजूद नहीं हैं। हालांकि, उनका वाहन खड़ा था।

एसआइटी के सामने पेश नहीं हुई आरोपित सास : गिरिबाला को पूछताछ के लिए कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वह अब तक एसआइटी के सामने पेश नहीं हुई हैं। शुरुआत में उन्होंने बयान देने से इन्कार किया था और अब तक पुलिस को घर के सीसीटीवी सिस्टम का पासवर्ड तक नहीं दिया गया है। वह अगली बार भी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होती हैं तो पुलिस उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए अदालत जाएगी।

वहीं, त्विषा के पिता ने एक वीडियो जारी किया है, जिसे मौत से कुछ देर पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में त्विषा राधे-कृष्ण का जाप कर उस पर नृत्य करती दिखाई दे रही है। परिवार का कहना है कि इससे साफ है कि वह किसी मानसिक अवसाद में नहीं थी। वहीं, इंटरनेट मीडिया पर गिरिबाला का एक कथित आडियो भी प्रसारित हो रहा है।

त्विषा शर्मा। फाइल

गिरिबाला को उपभोक्ता आयोग से हटाने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • भोपाल : त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सास गिरिबाला सिंह को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद वे किसी भी न्यायिक संस्था में पदस्थ रहने के लिए पात्र हैं या अपात्र, इसकी छानबीन के लिए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर जांच प्रतिवेदन मांगा है।

समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई आज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : त्विषा के पति समर्थ सिंह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया है। मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। समर्थ ने जमानत आवेदन में मामले की सीबीआइ जांच की मांग भी की है। इससे पहले भोपाल की कोर्ट ने 18 मई को आरोपित पति समर्थ सिंह को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया था।

आइडीएफसी बैंक घोटाले में दाखिल की गई पहली चार्जशीट, 15 नामजद

जागरण संवाददाता, पंचकूला

- अब तक 504 करोड़ के हेरफेर का पता चला, बढ़ सकती है घोटाले की रकम
- बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मियों और शेल कंपनियों की मिलीभगत से गबन

हरियाणा के चर्चित आइडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में सीबीआइ ने गुरुवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें बताया गया है कि हरियाणा के सरकारी विभागों के खातों में लगभग 504 करोड़ के हेरफेर की जांच हो चुकी है। जांच अभी जारी है, जिसमें घोटाले की राशि बढ़ सकती है।

चार्जशीट में कुल 15 आरोपितों को नामजद किया गया है। इनमें आइडीएफसी फर्स्ट बैंक और एक निजी बैंक के छह बैंक अधिकारियों रिभव ऋषि, अभय कुमार, सीमा धीमान, प्रियंका, अनुज कौशल, हरियाणा सरकार के तीन कर्मचारियों अमित दीवान, नरेश कुमार और रणधीर सिंह, दो शेल कंपनियों व उनके तीन साझेदारों/निदेशकों और एक निजी व्यक्ति के नाम शामिल हैं। सभी आरोपित वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। आरोपितों ने कथित रूप से हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों के बैंक खातों से धनराशि को अवैध तरीके से निकालकर निजी खातों और शेल कंपनियों में भेजा। इस मामले में हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के अमित दीवान, विकास एवं पंचायत विभाग के नरेश कुमार तथा हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के रणधीर सिंह से जुड़े सरकारी कर्मियों की भूमिका भी सामने आई है। ईडी का दावा है कि रिभव पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। जांच में सामने आया कि उसने कर्मचारियों, ड्राइवरों और रिश्तेदारों के नाम पर कई शेल कंपनियां बनाई थीं, जिनमें कैपको फिनटेक सर्विसेज, आरएस ट्रेडर्स और एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

सेना को सामान की आपूर्ति करने वाली कंपनी के ठिकानों पर सीबीआइ ने मारे छापे

जागरण संवाददाता, कानपुर

- सैन्य अफसर के साथ मिलकर ईस्टर्न ग्लोबल ने गलत ढंग से लिए सप्लाई के ठेके
- उद्यमी के बंगले से जब्त किए दस्तावेज, कर्नल की हो चुकी है गिरफ्तारी

रक्षा प्रतिष्ठानों को सामग्री आपूर्ति करने वाली कंपनी मेसर्स ईस्टर्न ग्लोबल लिमिटेड के संचालकों ने सैन्य अधिकारी के साथ मिलकर गलत ढंग से ठेके लिए। आरोप है कि कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए निविदा प्रक्रिया में हेरफेर, घटिया सामान की खरीद को मंजूरी देकर अनियमित तरीके से बिलों के भुगतान किए गए। मामले में सीबीआइ ने आरोपित एक कर्नल, उद्यमी समेत पांच नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कर्नल को दो दिन पहले कोलकाता से गिरफ्तार किया जा चुका है। बुधवार को कंपनी के ठिकाने पर छापेमारी कर दस्तावेज व इलेक्ट्रानिक साक्ष्य जब्त कर टीम साथ ले गई। उधर, दिल्ली की विशेष अदालत ने कर्नल हिमांशु बाली को 25 मई तक पांच दिन की सीबीआइ हिरासत में भेज दिया।

प्रतीकात्मक

रूमा औद्योगिक क्षेत्र में ईस्टर्न ग्लोबल लिमिटेड बुलेटप्रूफ जैकेट और टेक्निकल फाइबर से संबंधित उत्पादों का निर्माण करती है। कंपनी का बंगाल के 24 परगना जिले में गोदाम भी है। 2021-22 तक आठ करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनी वर्ष 2022-23 में 17 करोड़, 2023-24 में 35 करोड़ व 2025-26 में 41 करोड़ पर पहुंच गई। अब सीबीआइ की एंटी करप्शन शाखा ने आर्मी आर्डिनेंस कार्प्स, ईस्टर्न कमांड, कोलकाता में तैनात कर्नल हिमांशु बाली, कैंट निवासी कारोबारी अक्षत अग्रवाल, उनके पिता मयंक अग्रवाल, आशुतोष शुक्ला, नरेश पाल पर आपराधिक षड्यंत्र रचने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में रिश्वत लेने व देने, वाणिज्यिक संगठनों द्वारा भ्रष्टाचार व अपराध दुष्प्रेरण के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

आरोप है कि अक्षत व उनके पिता लंबे समय से कर्नल हिमांशु बाली के संपर्क में थे। सीबीआइ का दावा है कि मार्च व अप्रैल 2026 के दौरान निविदा को लेकर कथित साठगांठ हुई थी। 22 अप्रैल 2026 को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में आधिकारिक कार्य समय के बाद कर्नल बाली व अक्षत की व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी।

721 साल बाद धार के भोजशाला में शुक्रवार को गूंजेंगे मां वाग्देवी के जयकारे

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार

- निर्णय के बाद पहले शुक्रवार को होगी महाआरती व विशेष पूजा
- मस्जिद पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, शहर में 1500 से ज्यादा जवान तैनात

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से मिले 365 दिन निर्बाध पूजा-अर्चना के अधिकार के बाद पहले शुक्रवार को धार नगर स्थित भोजशाला में मां वाग्देवी की महाआरती और विशेष पूजन की तैयारी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मंदिर पक्ष सुबह नौ बजे भोजशाला में महाआरती करेगा, जबकि दोपहर 12 बजे बड़ी संख्या में श्रद्धालु ज्योति मंदिर से भोजशाला दर्शन के लिए रवाना होंगे। बता दें कि 721 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद यह पहला अवसर होगा, जब शुक्रवार को भोजशाला परिसर मां वाग्देवी के जयकारों से गूंजेगा। अब तक प्रत्येक शुक्रवार को नमाज होती थी।

इधर, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है। शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है। वहीं, धार में जिला व पुलिस प्रशासन ने शहर में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था कर ली है। धार के एसपी सचिन शर्मा का कहना है कि हाई र्ट के आदेश का पालन करवाया जाएगा। शहर में 1500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। बता दें कि भोजशाला परिसर से सटे कमाल मौला दरगाह क्षेत्र में शुक्रवार को उर्स का आयोजन होगा। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी के पदाधिकारियों के अनुसार, उर्स को लेकर प्रशासन को पूर्व में सूचना दे दी गई है।

भोजशाला परिसर का हवाई चित्र। फाइल

'काकरोच जनता पार्टी' का एक्स अकाउंट ब्लाक, संस्थापक ने बनाया नया अकाउंट

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करने वाले डिजिटल राजनीतिक व्यंग्यात्मक समूह 'काकरोच जनता पार्टी' के एक्स अकाउंट को गुरुवार को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद इस ग्रुप के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 'काकरोच डांट डाई टैग लाइन के साथ 'काकरोच इज बैक' नाम से नया एक्स अकांउट शुरू किया है। दरअसल, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने पिछले हफ्ते एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि कुछ युवा काकरोच जैसे होते हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे मीडिया, इंटरनेट मीडिया या आरटीआइ एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। हालांकि अगले दिन प्रधान न्यायाधीश ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन सफाई के बावजूद कई यूजर्स ने बेरोजगारी और सिस्टम को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसी माहौल में 'काकरोच जनता पार्टी' नाम से ग्रुप बनाया गया था। गुरुवार को इसका एक्स अकाउंट ब्लाक कर दिया गया, लेकिन इसका इंस्टाग्राम पेज अभी भी एक्टिव है और इसके एक करोड़ 56 लाख फालोअर फालोअर हैं। काकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने विपक्षी कांग्रेस के एक करोड़ 33 लाख फालोअर को भी पीछे छोड़ दिया है।

'काकरोच जनता पार्टी' नाम के लिए तीन ट्रेडमार्क आवेदन

'काकरोच जनता पार्टी' नाम पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तीन अलग-अलग ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए गए हैं। रिकार्ड के अनुसार ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री पोर्टल पर दायर आवेदनों में राजनीतिक और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने की श्रेणी के तहत ट्रेडमार्क पंजीकरण की मांग की गई है। अजीम आदमभाई जाम और अखंड स्वरूप ने अलग-अलग आवेदन दायर किए हैं।

1 की मौत हो गई अनगढ़ इलाके में गुरुवार को घर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके से। कई दीवारें व खिड़कियों के शीशे टूट गए और मलबा सड़क तक फैल गया। धमाके में मकान मालिक की पत्नी की मौत हो गई।

न्यूज गैलरी

'वसीयत का मूल उद्देश्य वारिस के सामान्य क्रम को बदलन'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कानूनी वारिसों और वसीयत के एक मामले में अहम टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि वसीयत का मूल उद्देश्य ही उत्तराधिकार के सामान्य क्रम को बदलना होता है। केवल स्वाभाविक वारिसों को विरासत से बाहर करना अपने आप में वसीयत को अमान्य करने के लिए संदिग्ध परिस्थिति नहीं मानी जा सकती। पीठ ने दिवंगत बी शीना नैरी की पत्नी और बच्चों की ओर से दायर एक अपील को खारिज कर दिया। इसमें नैरी की पत्नी और बच्चों ने उस वसीयत की वैधता को चुनौती दी थी, जिसमें नैरी ने कर्नाटक स्थित अपनी संपत्तियां अपनी बहन लक्ष्मी को दे दी थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट, अपीलीय अदालत और कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जैसे फैसलों को बरकरार रखा, जिन्होंने वसीयत को सही माना था। (प्रेट्र)

आध्यात्मिक नेताओं पर टिप्पणी में राकांपा प्रवक्ता गिरफ्तार

पुणे: महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के कुछ आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में राकांपा (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता विकास लवांडे को गुरुवार को पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया। लवांडे ने अदालत से 20 मई तक अंतरिम सुरक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सुबूत न होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। लवांडे के खिलाफ वारकरी संप्रदाय के कुछ आध्यात्मिक नेताओं को निशाना बनाने को लेकर पुणे के वाघोली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। (प्रेट्र)

मुंबई साइबर पुलिस ने फ्रीज किए पांच महीने में ठगे 101 करोड़

मुंबई: साइबर ठगी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता में मुंबई साइबर पुलिस ने 1930 साइबर हेल्पलाइन और अपराध शाखा के समन्वय से जनवरी और मई के बीच आनलाइन ठगी में खोए गए 101.39 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को फ्रीज कर सुरक्षित कर लिया। 17 मई 2022 को मुंबई पुलिस द्वारा लांच साइबर हेल्पलाइन डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली के रूप में उभरी है। हेल्पलाइन के अधिकारी तुरंत देश भर के बैंकों, डिजिटल वालेट, व्यापारियों और भुगतान गेटवे के नोडल अधिकारियों से समन्वय करते हैं। यह त्वरित समन्वय ठगों द्वारा धन हस्तांतरित करने या निकालने से पहले संदिग्ध खातों को फ्रीज में मदद करता है। (आइएएनएस)

यदि आरोपित को आपत्ति नहीं तो कोर्ट चला सकते हैं देशद्रोह का मुकदमा : सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने यह व्यवस्था 17 साल से जेल में बंद एक आरोपित की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी

आरोपित की अपील मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है, फैसले की उम्मीद में उसने लगाई थी गुहार

नई दिल्ली, प्रेट्र : देशद्रोह कानून (धारा 124ए) पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और मानवीय फैसला सुनाया है। इसने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपित को कोई आपत्ति न हो, तो अदालतें देशद्रोह से जुड़े मामलों की सुनवाई और ट्रायल को आगे बढ़ा सकती हैं।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह व्यवस्था 17 साल से जेल में बंद एक आरोपित की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। इस आरोपित की अपील मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है, और उसने गुहार लगाई थी कि वह अपना फैसला चाहता है ताकि इस अनिश्चितता से मुक्ति मिल सके।

सलाखों के पीछे बीते 17 साल का दर्द : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित के इस दर्द को समझा और कहा कि जहां खुद आरोपित को धारा 124ए के तहत चल रही अपील या ट्रायल से कोई आपत्ति नहीं है, वहां अदालतों के लिए मामले का गुण-दोष (मेरिट) के आधार पर फैसला करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस याचिकाकर्ता की अपील पर जल्द से जल्द कानून के मुताबिक फैसला करे।

औपनिवेशिक दौर के कानून पर पहले लगी थी रोक : गौरतलब है कि 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश के जरिये इस औपनिवेशिक कानून पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार द्वारा कानून की समीक्षा किए जाने तक नई एफआइआर दर्ज करने और लंबित मामलों की कार्यवाही पर अंतरिम रोक थी। जेल में बंद लोगों को जमानत के लिए कोर्ट जाने की छूट दी गई थी।

1890 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज दबाने के लिए बनाए गए इस कानून की लंबे समय से आलोचना हो रही थी। एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी समेत कई दिग्गजों ने इसके दुरुपयोग के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के नए रुख से उन कैदियों को बड़ी राहत मिलेगी जो सालों से सिर्फ इसलिए जेल में हैं क्योंकि उनके मामलों पर सुनवाई रुकी हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

53 एफआइआर नहीं होगी एक, कहा-पीड़ित क्यों भुगतें

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने 49 करोड़ के निवेश घोटाले से जुड़ी विभिन्न राज्यों में दर्ज 53 एफआइआर को एक साथ मिलाने की आरोपितों की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय प्रणाली को आरोपितों की सुविधा के बजाय पीड़ितों के अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पीठ ने आरोपित उपेंद्र नाथ मिश्रा और काली प्रसाद मिश्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी की दलीलों से सहमति नहीं जताई। कोर्ट ने पूछा, ऐसा कर दिया जाए तो इस सूरत में धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों के अधिकारों का क्या होगा? साथ ही उन्होंने कहा- क्या यह उचित है कि पीड़ितों को अपराध के आरोपित की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों से एक स्थान पर आने के लिए कहा जाए।

जजों पर काम का बोझ जाने बगैर त्वरित सुनवाई का नहीं दे सकते निर्देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि एक मामले को प्राथमिकता देने से दूसरे मामले को खामियाजा भुगतना पड़ता है

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक मामले की जल्दी सुनवाई का निर्देश देने की मांग पर विचार करने से इन्कार कर दिया। कहा कि वह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर काम के बोझ को ध्यान में रखे बगैर सुनवाई की समय सीमा तय करके उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाल सकता।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के भीतर एक मामले की सुनवाई करने के लिए नियमित मामलों की सुनवाई खत्म होने के बाद शाम 7.10 बजे तक बैठना पड़ा। आखिरकार उन्होंने आदेश पारित करने को यह कहते हुए टाल दिया कि वह भूखे, थके हुए और फैसला लिखवाने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ हैं।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जैसा कि इस जज ने लिखा था, शायद सही ही लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का फैसला करने का निर्देश दिया था। अब शाम के 6.50 या 7.10 बज रहे हैं। उन्होंने समय का जिक्र किया। लिखा कि मैंने अपना लंच भी छोड़ दिया, अब मैं पूरी तरह से थका हुआ और निढाल हूं। मैं इस मामले को आगे नहीं ले जा पाऊंगा।

सीजेआइ ने कहा कि उन्होंने न्यायिक आदेश में इसका जिक्र किया, जिसके लिए वास्तव में हमारी ओर से भी कुछ आत्ममंथन की जरूरत है। उन्होंने यह भी जिक्र किया था कि उनके सामने 200 से ज्यादा नए मामले लंबित थे। सीजेआइ ने कहा कि यहां से कोई आदेश पारित करना, भले ही उसमें अनुरोध शब्द का प्रयोग किया गया हो, बहुत मुश्किल हो जाता है।

इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत, जोयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2021 के केस में जल्द फैसले का निर्देश मांगा गया था। सीजेआइ ने कहा कि अगर कोर्ट किसी हालिया मामले की सुनवाई तेज करता है तो इसका खामियाजा किसी पुराने केस को भुगतना पड़ेगा।

वह पुराना मामला किसी ऐसे गरीब वादी का हो सकता है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त संसाधन न हों। अंत में शीर्ष अदालत ने जल्दी सुनवाई की याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट के समक्ष मांग रखने की छूट दी।

कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए संकट बना कैनाइन डिस्टेंपर वायरस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल

- कुत्तों से फैलने वाली बीमारी पांच बाघों को बना चुकी है शिकार
- एनटीसीए की चेतावनी के बाद कुत्तों के टीकाकरण का अभियान तेज

मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) संकट बन गया है। इस वायरस से बाघिन और तीन शावकों का पूरा कुनबा खत्म हो चुका है। एक अन्य बाघ की पिछले दिनों मौत हो गई। अब तक पांच बाघों को अपना शिकार बना चुके कुत्तों से फैलने वाले इस वायरस ने कान्हा पार्क प्रबंधन की ही नहीं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की चिंता भी बढ़ा दी है। ऐसे में एनटीसीए ने एडवाइजरी जारी कर कुत्तों के टीकाकरण को कहा है।

बता दें कि इस वायरस से बचाव के लिए प्रतिवर्ष जंगल व समीप के गांवों में विचरण करने वाले कुत्तों का टीकाकरण किया जाता रहा है। ऐसे में एनटीसीए की चेतावनी के बाद अभयारण्यों के आसपास कुत्तों के टीकाकरण का अभियान तेज हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक ने डा. समीता राजौरा ने बताया कि बाघों में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम के लिए उपाय किए गए हैं। एहतियात बरतते हुए कुत्तों को टाइगर रिजर्व सीमा से दूर रखने का प्रयास किए जा रहे हैं। कुत्तों का टीकाकरण भी कराने पर जोर है। अन्य टाइगर रिजर्व में भी सतर्कता बरती जा रही है। उल्लेखनीय है कि जनवरी से लेकर अब तक साढ़े चार माह में मध्य प्रदेश में वैसे भी 33 बाघों की मौत हो चुकी है। हालांकि, बाघों की मौत के कई अन्य कारण जैसे शिकार व आपसी संघर्ष भी शामिल हैं।

पैरोल तोड़कर अमिताभ और आमिर की फिल्मों में काम करने वाला 12 साल बाद गिरफ्तार

अहमदाबाद, प्रेट्र : हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति ने 2014 में पैरोल तोड़कर अपनी पहचान बदल ली और बालीवुड फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू कर दीं। उसने अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे बड़े अभिनेताओं की फिल्मों में काम किया। उसे 12 साल बाद अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच ने बुधवार को अहमदाबाद के एक मेट्रो स्टेशन के पास से दोषी हेमंत मोदी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ 2005 में अहमदाबाद में हत्या और दंगा भड़काने का मामला दर्ज किया गया था। 2014 में गुजरात हाई कोर्ट ने उसे 30 दिन की पैरोल दी थी। हालांकि, आत्मसमर्पण न करने पर हाई कोर्ट ने उसी वर्ष जुलाई में उसे पैरोल तोड़ने वाला घोषित कर दिया था। क्राइम ब्रांच द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

हेमंत मोदी।

2014 में गुजरात हाई कोर्ट ने उसे 30 दिन की दी थी पैरोल, इसके बाद वह हो गया था फरार

पुलिस के अनुसार, शहर के पार्श्वनाथ टाउनशिप के पास एक चाल के रास्ते में बनाई गई सीढ़ी को लेकर विवाद हुआ था। 15 जून, 2005 को हेमंत मोदी और उसके भाई सहित कई लोगों का अजय पटेल और उसके दोस्त नरेंद्र कांबले के साथ विवाद हुआ था। इसमें कांबले की मौत हो गई थी। अगस्त 2008 में हेमंत मोदी सहित सभी दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह मेहसाना जिला जेल में सजा काट रहा था। पैरोल तोड़ने के बाद उसने अपना नाम बदल लिया और सहायक अभिनेता के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें हिंदी और गुजराती फिल्मों, वेब सीरीज में विभिन्न भूमिकाएं शामिल हैं।

अपनी फरारी के दौरान उसने अमिताभ बच्चन और आमिर खान के साथ 'ठग्स आफ हिंदुस्तान' और रणवीर सिंह के साथ 'जयेशभाई जोरदार' जैसी प्रमुख बालीवुड फिल्मों में काम किया। फिल्मों के अतिरिक्त वह रंगमंच में भी सक्रिय रहा। उसने 'युगपुरुष' और 'गांधी विरुद्ध गोडसे' जैसे नाटकों में अभिनय किया। पुलिस के अनुसार, हेमंत मोदी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कई ठिकाने बदले। उसने अपना नाम भी बदल लिया। 2014 और 2015 के बीच वह गुजरात के पाटन जिले में रहा और बाद में ट्विंकल दवे नाम से अहमदाबाद चला गया। वह 2017 तक पेइंग गेस्ट के रूप में रहता था और शहर की एक निजी कंपनी में काम करता था।

लैंडिंग के दौरान विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया

नई दिल्ली, प्रेट्र : 181 यात्रियों को लेकर जा रहे एअर इंडिया के एक विमान का गुरुवार सुबह बेंगलुरु हवाईअड्डे पर उतरते समय पिछला हिस्सा जमीन से टकरा (टेलस्ट्राइक) गया। एयरलाइन दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान एआइ2651 का संचालन कर रहा था। टेलस्ट्राइक तब होता है, जब टेक-आफ या लैंडिंग के दौरान विमान का पिछला हिस्सा जमीन को छूता है।

घटना के बाद बेंगलुरु से दिल्ली की वापसी उड़ान एआइ2652 रद कर दी गई। एअर इंडिया ने कहा कि प्रभावित यात्रियों को समायोजित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। विस्तृत निरीक्षण के लिए विमान को रोक दिया गया। प्रवक्ता ने कहा, नियामक अधिकारियों के समन्वय से स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार घटना की जांच की जाएगी।

देशभर की 120 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरीं, 31 हिमाचल की

जागरण संवाददाता, सोलन

- सकेंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जारी किया ड्रग अलर्ट, सैंपल फेल होने की दर में आई कमी

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की ओर से अप्रैल के जारी ड्रग अलर्ट में देशभर में बनी 120 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। एक दवा नकली पाई गई है। हिमाचल में बनी 31 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे। उत्तराखंड की 24 और गुजरात की 20 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश के राज्य दवा नियंत्रक डा. मनीष कपूर का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लागू किए रिवाइज्ड शेड्यूल के तहत अब दवा उत्पादन में बदलाव किए गए हैं। दवा उत्पादन के दौरान सख्ती को और अधिक बढ़ाया है। हमारा प्रयास है कि दवा सैंपल फेल के आंकड़े पूरी तरह कम हो जाएं। जो भी दवाएं फेल पाई जाती हैं, उनकी सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफार्म पर सार्वजनिक की जाती है, ताकि लोग इनका उपयोग न करें। मानकों पर खरी नहीं उतरीं 120 दवाओं में अधिकतर कफ सिरप, इंजेक्शन, सिरदर्द, दिल के रोग से संबंधित हैं। इनमें दिल, मिर्गी, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। कुछ पाउडर, आयरन, मेहंदी व विटामिन की गोलियां भी गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाई गईं।

हिमाचल, उत्तराखंड व गुजरात के अलावा तेलंगाना के सात, सिक्किम के पांच, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र से चार-चार, पंजाब, जम्मू कश्मीर व तमिलनाडु से तीन-तीन, पुडुचेरी से दो और बिहार व बंगाल से एक-एक दवा का सैंपल फेल हुआ है।

लापरवाही के सबसे गंभीर रूपों में से एक

प्रथम पृष्ठ से शेष

18 मई के आदेश में एनसीडीआरसी ने कहा, "हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह लापरवाही के सबसे गंभीर रूपों में से एक है। ऐसे बहुत ही कम मामले अदालतों और न्यायाधिकरणों के सामने आते हैं।" अभियोजन पक्ष के अनुसार, 56 वर्षीय शांति देवी ने अप्रैल, 2012 में पेट में दर्द होने पर डाक्टर से संपर्क किया था और दाईं किडनी में गंभीर हाइड्रोनेफ्रोसिस का पता चला था। सर्जरी से पहले की मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि दाईं किडनी खराब है। छह मई, 2012 को दाईं किडनी निकालने के लिए सर्जरी की गई। इसके बाद जून, 2012 में रेडियोलाजिकल जांच और सीटी स्कैन से पता चला कि दाईं किडनी शरीरी में मौजूद है, जबकि स्वस्थ बाईं किडनी गायब। यह उजागर होने के बाद परिवार ने डाक्टर के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की थी।

'आधुनिक इतिहास' की जगह पूछा था 'प्राचीन इतिहास' का सवाल

संग्राम सिंह ● जागरण

- बीएचयू की सेमेस्टर परीक्षा में 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' पर विवादित सवाल पूछने पर प्रश्न पत्र तैयार करने वाली प्रो. सुतपा दास से सफाई मांगी
- प्रश्न-पत्र माडरेशन प्रक्रिया में भी गंभीर चूक, सवाल में पहले से ही यह निष्कर्ष मान लिया गया कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने बाधा डाली

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के सामाजिक विज्ञान संकाय के इतिहास विभाग में एमए चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान एक प्रश्नपत्र में पूछे गए विवादित और नकारात्मक प्रवृत्ति के सवाल को लेकर प्रशासनिक और अकादमिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है। पाठ्यक्रम से इतर और एकतरफा दृष्टिकोण से पूछे गए सवाल को लेकर विवि प्रशासन ने प्रश्न-पत्र तैयार करने वाली इतिहास विभाग की प्रो. सुतपा दास से स्पष्टीकरण तलब किया है, जिसका उन्होंने जवाब भी दाखिल कर दिया है। पूरा मामला न केवल सवाल की भाषा, बल्कि विश्वविद्यालय की प्रश्न-पत्र माडरेशन प्रक्रिया में गंभीर चूक से भी जुड़ा है।

एमए इतिहास के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता शब्द से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए कि किस प्रकार ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में बाधा डाली? इतिहास विभाग में यह प्रश्नपत्र 'आधुनिक भारतीय इतिहास में महिला-1950 तक' विषय का था। इसका पाठ्यक्रम मुख्य रूप से 19वीं-20वीं शताब्दी के कालखंड पर आधारित है। लेकिन, परीक्षा में इसे आधुनिक काल के बजाय प्राचीन भारतीय इतिहास से जोड़कर पूछा गया।

आलोचकों का मानना है कि प्राचीन भारत (प्रारंभ से लेकर 10वीं या 12वीं शताब्दी-राजपूत काल तक) को लेकर पूछे गए सवाल में पहले से ही निष्कर्ष मान लिया गया कि 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने बाधा डाली।' यह छात्रों पर खास विचारधारा थोपने जैसा है, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्य इसके विपरीत वैदिक काल में स्त्रियों की सुदृढ़ स्थिति दर्शाते हैं, जहां मैत्रेयी, लोपमुद्रा और घोषा जैसी विदुषी महिलाओं के प्रत्यक्ष उदाहरण मिलते हैं। हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डा. श्रीप्रकाश शुक्ल ने कहा कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर सवाल प्रश्नवाचक (टिप्पणी या आलोचनात्मक मूल्यांकन की मांग करने वाले) होने चाहिए, न कि पहले से ही निष्कर्ष थोपने वाले। विवि प्रशासन प्रश्न-पत्र तैयार करने की त्रिस्तरीय व्यवस्था के बाद भी हुई चूक की समीक्षा कर रहा है।

शिक्षा संस्थानों को विभाजन की राजनीति से रखें दूर

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीएचयू में कोई प्रश्नपत्र आ गया है जिसका सवाल भी बहुत टेढ़ा-मेढ़ा है। बीएचयू जैसा संस्थान जो हमारे पूजनीय शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय ने बनाई उस संस्थान में कैसे-कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है। बदनामी भी यही कराते हैं फिर सवाल भी हमसे पूछा जाता है। वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि शिक्षा संस्थानों को नफरत और विभाजन की राजनीति से दूर रखा जाए। बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में "ब्राह्मणवादी पितृसत्ता" जैसे शब्दों को जिस प्रकार प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसने पूरे समाज को सोचने को विवश किया है। ऐसी चीजें समाज में वैचारिक टकराव और जातीय विभाजन को बढ़ावा देती है।

जागरण विशेष
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस

जैव विविधता का प्राचीन संकेतक खतरे में, बचाने को चली मुहिम

इंटरनेशनल यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर की रेड लिस्ट में शामिल है डायनोसार काल का हिमालयन सैलामेंडर

मोहन झा ● जागरण

सिलीगुड़ी: जैव विविधता का प्राचीन संकेतक हिमालयन सैलामेंडर का अस्तित्व खतरे में है। डायनोसार के विलुप्त होने के बाद भी उस काल का यह जीव बचा रहा, मगर अनियोजित विकास की अंधी दौड़ ने इसके अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। दार्जिलिंग में विज्ञानी, वन विभाग, शोधकर्ता और ग्रीन आस्कर विजेता बरखा सुब्बा के साथ ही अनेक स्थानीय लोग मिलकर इस दुर्लभ जीव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे स्थानीय लोग 'गोरा' या 'पानी कुकुर' कहते हैं।

इंटरनेशनल यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर की रेड लिस्ट में विलुप्तप्राय श्रेणी में शामिल हिमालयन सैलामेंडर आज देश में केवल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में ही बचा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी मौजूदगी साफ जल, स्वस्थ जंगल और संतुलित पर्यावरण का संकेत होती है। ग्रीन आस्कर विजेता व शोधकर्ता बरखा सुब्बा कहती हैं कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन ने इसका प्राकृतिक संसार छोटा कर दिया है। चाय बागानों में रासायनिक कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग और पहाड़ों में फैलता कंक्रीट भी इसके लिए खतरा बने। कभी दार्जिलिंग के लगभग 80 स्थलों पर दिखाई देने वाला सैलामेंडर अब केवल 15 स्थानों तक सिमट गया है। मई से अगस्त के प्रजनन काल में यह उथले जलाशयों की ओर आता है और इसी दौरान सड़क दुर्घटनाओं का भी शिकार होता है। अब इसे बचाने को नामथिंग पोखरी और पोखरीटार जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक नमी और घास को सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है। वन विभाग जलधाराओं को प्राकृतिक रूप में बनाए रखने और सड़कों की ओर बहते पानी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि प्रजनन काल में सैलामेंडर सुरक्षित रह सकें। जिन इलाकों में यह जीव पाया जाता है, वहां कंक्रीट निर्माण पर रोक लगाई गई है। यहां बता दें कि सुब्बा को हिमालयन सैलामेंडर और उसके वेटलैंड संरक्षण के लिए ही 2026 का व्हिटली अवार्ड (ग्रीन आस्कर) से सम्मानित किया गया है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

80 से ज्यादा स्थलों पर दिखाई देने वाला सैलामेंडर अब 15 स्थानों तक सिमट गया

2006 से सैलामेंडर के सफल प्रजनन को चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम

जैविक संरचना और पुनर्जीवन क्षमता पर भी अध्ययन

दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलाजिकल पार्क में सैलामेंडर के सफल प्रजनन पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विज्ञानी इसकी जैविक संरचना व पुनर्जीवन क्षमता पर भी अध्ययन कर रहे हैं। सैलामेंडर अपने क्षतिग्रस्त अंगों व पूंछ को दोबारा विकसित कर सकता है।

सात प्रजनन स्थलों को बहाल रखने की कोशिश

फेडरेशन आफ सोसायटीज फार एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन में सलाहकार के तौर पर सुब्बा कार्य करती हैं। उनके नेतृत्व में इस संस्था ने पोखरीटार जैव विविधता विरासत क्षेत्र में हिमालयन सैलामेंडर के लिए सात प्रजनन स्थलों को बहाल रखने की कोशिश की है।

विलुप्तप्राय हिमालयन सैलामेंडर ● वन विभाग

...तो ही पहाड़ों का जल व जंगल भी सुरक्षित रहेंगे

सुब्बा बताती हैं कि बचाव अभियान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ग्रामीणों और चाय बागान प्रबंधकों को रासायनिक कीटनाशकों के सीमित उपयोग और जल स्रोतों को संरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि यह छोटा जीव पूरे पहाड़ की सेहत का संकेतक है। जब सैलामेंडर सुरक्षित रहेगा, तब पहाड़ों का जल और जंगल भी सुरक्षित रहेंगे।

दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चल रही मुहिम एक गहरी सीख भी देती है। सीख यह कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन संभव है, यदि समाज संवेदनशील होकर प्रकृति के साथ चलना सीख ले। हिमालयन सैलामेंडर को बचाने की यह कोशिश उस भरोसे को भी मजबूत करती है कि इंसान अपनी गलतियों को समझकर सुधार कर सकता है। आने वाले समय में यही समझ जैव विविधता और पृथ्वी दोनों को सुरक्षित रखने की बहुत बड़ी ताकत बनेगी।

बरखा सुब्बा, शोधार्थी और ग्रीन आस्कर विजेता

यह प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत का बेहतरीन इंडिकेटर है। वन विभाग ने पंचपोखरी के पांच हेक्टेयर क्षेत्र को सैलामेंडर अभयारण्य घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। कर्सियांग से 15 किलोमीटर दूर पंचपोखरी, विश्व धरोहर पोखरीटार जैव विविधता क्षेत्र और नामथिंग पोखरी में इसकी अच्छी आबादी पाई गई है। नामथिंग पोखरी को राज्य सरकार ने जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है।

देवेश पांडे, डीएफओ, कर्सियांग फारेस्ट डिवीजन

झारखंड में 27 माओवादियों का अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची

- सरेंडर करने वाले माओवादी कमांडरों में छह पर घोषित था कुल 28 लाख का इनाम

झारखंड पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को आपरेशन नवजीवन के तहत एक साथ 27 माओवादियों ने झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यह झारखंड के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। जिन 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनमें पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में सक्रिय रहे भाकपा माओवादी के 25 माओवादी व गुमला-सिमडेगा में सक्रिय रहे माओवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के दो माओवादी शामिल हैं। इनमें छह इनामी माओवादी भी शामिल हैं, जिनपर कुल 28 लाख रुपये का इनाम घोषित था। वहीं, जेजेएमपी के दो माओवादियों पर गुमला व सिमडेगा में कुल 14 मामले दर्ज हैं। माओवादियों ने कुल 16 आधुनिक हथियार व 2,857 कारतूस पुलिस को सौंपे हैं। कार्यक्रम में डीजीपी तदाशा मिश्रा व अन्य वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ व घोषित इनाम की राशि भेंटकर माओवादियों का स्वागत किया।

छग में सरकारी जमीन पर चर्च निर्माण के विरोध में ग्रामीण लामबंद

नईदुनिया, जशपुरनगर: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले में सरकारी जमीन पर अवैध चर्च निर्माण के विरोध में ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमीन का सीमांकन कर निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में ग्राम सभा में भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि विवादित जमीन का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाए। उनका कहना है कि गांव में राशन दुकान और सामुदायिक भवन नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपर कलेक्टर प्रदीप साहू ने ग्रामीणों को जमीन का सीमांकन कराने का आश्वासन दिया है।

दैनिक जागरण

विवेक से ही उचित-अनुचित का भेद संभव है

पाक में पलते आतंकी

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत के लिए खतरा बने एक और आतंकी सरगना हमजा बुरहान का मारा जाना यही बताता है कि ऐसे आतंकियों को ठिकाने लगाने वाले अज्ञात बंदूकधारी अपने काम पर लगे हुए हैं। पुलवामा का रहने वाला हमजा पाकिस्तान पढ़ने के लिए गया था, लेकिन वहां जाकर वह आतंकी संगठन अल बद्र का गुर्गा बन गया और कश्मीरी युवाओं को आतंक के रास्ते पर चलने के लिए उकसाने लगा। पुलवामा आतंकी हमले में उसका भी हाथ था। हालांकि वह अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था, लेकिन फिर भी अज्ञात बंदूकधारियों की निगाह से बच नहीं पाया। प्रश्न यह नहीं है कि इन अज्ञात बंदूकधारियों के पीछे कौन है? प्रश्न यह है कि आखिर पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बने आतंकियों को पालने-पोसने से कब बाज आएगा? चूंकि वह बाज नहीं आ रहा है, इसलिए वहां पल रहे आतंकियों का येन-केन-प्रकारेण खात्मा ही भारत के हित में है। जब सीधी अंगुली से घी न निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी ही पड़ती है और आतंकियों के खात्मे में तो साम-दाम-दंड-भेद यानी कोई भी जतन करने में हर्ज नहीं। यह अच्छा है कि भारत में आतंकी हमले कराने अथवा कश्मीरी युवाओं को भड़काने वाले आतंकियों के खात्मे का सिलसिला न केवल कायम है, बल्कि वह तेज होता हुआ भी दिख रहा है। यह इतना तेज होना चाहिए कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के साथ-साथ वहां के सत्ता प्रतिष्ठान को भी यह संदेश जाए कि भारत को क्षति पहुंचाने वाले सुरक्षित बचने वाले नहीं हैं। और भी अच्छा यह होगा कि भारत के लिए खतरा बने आतंकियों को पालने-पोसने और उन्हें हर तरह की मदद देने वालों तक भी अज्ञात बंदूकधारी पहुंचें।

पिछले पांच-छह वर्षों से अब तक अज्ञात बंदूकधारियों की ओर से कम से कम दो दर्जन ऐसे आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है, जिन्होंने भारत में आतंकी हमले कराए। इनमें जैश, लश्कर के कई आतंकी सरगना हैं। ऐसे शेष आतंकियों की लंबी सूची है। इनमें मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगना तो हैं ही, दाऊद इब्राहिम भी है। भारत विरोधी आतंकियों की लंबी सूची यही बताती है कि पाकिस्तान का सत्ता प्रतिष्ठान और विशेष रूप से उसकी खुफिया एजेंसी आइएसआइ इन आतंकियों को बिना किसी शर्म-संकोच पाल रही है, लेकिन अज्ञात बंदूकधारियों से वे लाहौर से लेकर पेशावर तक कहीं भी नहीं बच पा रहे हैं। उन्हें बचना भी नहीं चाहिए। पता नहीं ढीठ पाकिस्तान के लिए यह कितनी चिंता का विषय है कि उसके यहां पलते आतंकियों को कौन मार रहा है, लेकिन कम से कम भारत को इसे लेकर सतर्क रहना चाहिए कि पहलगाम हमले के बाद छेड़े गए आपरेशन सिंदूर में पस्त होने के बाद भी वह भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने में लगा है।

अकादमिक शुचिता

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में शोध कार्यों की गुणवत्ता और अकादमिक शुचिता का सवालों के घेरे में आना संस्थान की प्रतिष्ठा को आहत कर रहा है। चिकित्सा विज्ञान, प्रदूषण, प्रसवोत्तर रक्तस्राव जैसे संवेदनशील और जनहित से जुड़े विषयों पर गलत तथ्य और पुराने शोध की नकल कर जिस प्रकार बौद्धिक चोरी का कुत्सित प्रयास किया गया, वह इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं अध्ययन और शोध कार्य में गुणवत्ता से समझौता हो रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध पत्रों के परीक्षण के लिए शोध गंगा जैसा प्रकल्प गठित किया है। वर्ष 2013 से अब तक विश्वविद्यालय के कुल 60 शोध पत्रों में अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि शोध कार्य में प्राध्यापकों का बड़ा योगदान होता है। उनके निर्देश के अनुरूप ही शोधार्थी अपना प्रबंध तैयार करते हैं। किसी भी संस्थान में

> अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में बीएचयू के शोध कार्यों का प्रकाशन निरस्त होने से विश्वविद्यालय की साख प्रभावित हुई है

यह कार्य कई चरणों में होता है। अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में बीएचयू के रिसर्च के प्रकाशन के निरस्त होने से वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालय की साख और रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चाहे कोई तकनीकी त्रुटि हो या जानबूझ कर बौद्धिक चोरी की गई हो, इस पर पूर्ण विराम आवश्यक है। कुछ लोगों की लापरवाही या अक्षमता से देश के इतने प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान की गरिमा आहत हो, यह ठीक नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि फिर ऐसा कोई खेदजनक प्रसंग न हो। इससे देश के शैक्षिक स्तर में भी गिरावट आने की आशंका रहती है, लिहाजा इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

केवल किफायत से नहीं चलेगा काम

तरुण गुप्त

छिटपुट सुधारों और सीमित गति वाली प्रगति का दौर अब बीत चुका है। अब व्यापक सुधार करने, सक्षम प्रदर्शन और गहन रूपांतरण का समय है

किसी भी संस्कृति और समय में मितव्ययिता की महत्ता रहती है। 'पैसा बचाना भी पैसा कमाने के बराबर है' से लेकर 'फिजूलखर्ची से तो कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाता है' जैसी कहावतें भी मितव्ययिता को ही सराहती हैं। अतीत में भी ऐसे अवसर आए हैं, जब सत्ता में बैठे लोगों ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता प्रदर्शित की है, किंतु प्रायः ऐसे प्रयासों की प्रकृति प्रतीकात्मक ही रही है। हम यही आशा करते हैं कि इस बार किफायत के ये प्रयास दिखावटी न होकर अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित करेंगे।

भले ही किफायत बरतना कितना ही सराहनीय क्यों न हो, लेकिन उससे एक सीमित दायरे में ही लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे केवल खर्चों में कटौती करके ही कोई संस्थान शीर्ष पर नहीं पहुंच सकता, इसके साथ ही उसे अपनी आय बढ़ाने के भी उपाय करने होंगे। भारत के संदर्भ में देखें तो यह किसी से छिपा नहीं रहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए विनिवेश के साथ ही भूमि के मौद्रीकरण को लेकर भी हमारा प्रदर्शन लचर रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के पास लाखों एकड़ भूमि अनुत्पादक पड़ी है, जिसकी कीमत का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। केवल रक्षा और रेल मंत्रालय की ही बात करें तो उनके पास 15 से 18 लाख एकड़ से अधिक भूमि का भंडार है। इस जमीन का एक अच्छा-खासा हिस्सा शहरी क्षेत्रों में है। इस अनुत्पादक भूमि को मुक्त कर उत्पादक बनाने की दिशा में अविलंब प्रयास करने होंगे। यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि नेताओं एवं नौकरशाहों के आवास की व्यवस्था औपनिवेशिक काल की विशाल संपत्तियों पर है। यह अतीत का ही एक अवशेष है। किसी टियर-2 शहर में एक जिला कलेक्टर का सौ करोड़ रुपये के औपनिवेशिक काल के बंगले में रहना गैर-निष्पादित आस्ति यानी एनपीए से कम नहीं। इसे देखते हुए प्रशासकों को आधुनिक बहुमंजिला परिसरों में रखने के उपाय न केवल किफायती, बल्कि वाणिज्यिक उपयोग, मनोरंजन और किफायती आवास की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। इससे रखरखाव और सुरक्षा के खर्चों में भी भारी बचत होगी। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) को इस आमूलचूल बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने ही चाहिए।

निःसंदेह पिछले 12 वर्षों में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और बिजली उत्पादन जैसे बुनियादी ढांचे में जबरदस्त प्रगति हुई है। फिर भी, इसे और चार गुना बढ़ाने की आवश्यकता है, जहां पूंजी को उत्पादक गतिविधियों में लगाने के अवसर विद्यमान हैं। इस क्रम में भूमि, श्रम और पूंजी से जुड़े अगली पीढ़ी के सुधार प्रतीक्षित हैं। यह भी स्मरण रहे कि कारोबारी सुगमता और जीवन की सुगमता अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए स्वच्छता के स्तर, शहरी नियोजन और नगर निकायों के शासन में ठोस सुधार सामाजिक-आर्थिक वातावरण के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हैं। संरचनात्मक न्यायिक सुधार किसी बड़े निवेशक सम्मेलन की तुलना में उद्यमशीलता की भावना को कहीं अधिक बढ़ाने का काम करेंगे। इससे हर स्तर पर निवेश को संबल मिलेगा।

अवधेश राजपूत

भारतीय बाजार के बफेट संकेतक यानी जीडीपी के अनुपात में समग्र शेयर बाजार पूंजीकरण पैमाने को देखें तो कई विकसित व तुलनात्मक अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष भारत कहीं बेहतर स्थिति में है, लेकिन पिछले डेढ़ साल से विदेशी निवेशकों की बिकवाली पर विराम नहीं लग पा रहा है। इस दिशा में कुछ उपायों जैसे कि सीमांत दरों पर लाभांश कराधान (डिविडेंड टैक्स) और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) से इंडेक्सेशन को वापस लेने पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य भारतीय इक्विटी बाजारों को अधिक आकर्षक बनाना है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि स्वयं को अधिक समृद्ध महसूस करने पर ही निवेशक उपभोग को उन्मुख होते हैं।

स्थलों की विविधता एवं व्यापकता को देखते हुए पर्यटन एक दमदार आर्थिक इंजन बनने की क्षमता रखता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में भारत का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत पर अटका हुआ है। रोजगार आधारित विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र बेजोड़ है, जहां प्रत्येक 10 लाख रुपये का निवेश औसतन 45 नौकरियां सृजित करता है, जो विनिर्माण की तुलना में तीन गुना और इन्फ्रास्ट्रक्चर की तुलना में छह गुना अधिक है। नागरिकों से विदेशी सैर-सपाटे पर संयम की अपील में भले ही कितनी ही भली मंशा क्यों न निहित हो, किंतु घरेलू पर्यटन को आकर्षक बनाना कहीं अधिक प्रभावी होगा। इससे भारी विदेशी पर्यटन घाटे को पाटने में भी मदद मिलेगी, जिस पर भारतीय सालाना 15 से 20 अरब डालर खर्च करते हैं।

इस क्रम में शिक्षा संभवतः सबसे बड़ा परिवर्तनकारी कारक है। हमें तत्काल मांग और आपूर्ति के गंभीर असंतुलन को दूर करने, गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा में निवेश करने और उच्च शिक्षा में सीटों के विस्तार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली में कमियों और बड़े पैमाने पर पेपर लीक को लेकर संस्थागत विश्वसनीयता बहाल करने के लिए उपाय करने होंगे। विदेशी छात्रों को आकर्षित करने से जहां मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, वहीं भारतीय छात्रों को देश में ही रोकने से प्रतिभा और पूंजी के पलायन पर रोक लगती है। बहुप्रचारित जनसांख्यिकीय लाभांश तभी बेहतर परिणाम देगा जब इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही यह किसी भी विकसित समाज के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

ये सभी उपाय सहकारी संघवाद से ही संभव हो सकते हैं। केंद्र और लगभग 70 प्रतिशत राज्यों में एक ही दल या गठबंधन वाली शासन व्यवस्था के दौर में इसके लिए आवश्यक ढांचागत परिवर्तन में कोई वैचारिक या प्रक्रियात्मक बाधा नहीं आनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने सही कहा कि 2020 का दशक व्यवधानों से भरा रहा है। शुरुआत महामारी से हुई। उसके बाद से कई सशस्त्र वैश्विक संघर्ष जारी हैं। इसी बीच संरक्षणवाद की वापसी ने काफी समय से कायम पुरानी व्यवस्था को उलट दिया। हर संकट में अवसर छिपा होता है तो क्या यह ऐतिहासिक पड़ाव परिवर्तन की अग्नि को प्रज्वलित कर सकता है? छिटपुट सुधारों और सीमित गति वाली प्रगति का दौर बीत चुका है। अब व्यापक सुधार करने, सक्षम प्रदर्शन और गहन रूपांतरण का समय है।

(लेखक दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक हैं)
response@jagran.com

कोचिंग संस्कृति की चपेट में शिक्षा

मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा नीट के पेपर लीक कांड ने सभी को दुखी और चिंतित किया है। नीट पेपर लीक कांड ने बताया कि किस तरह पैसा, बढ़ते लालच और अयोग्य होकर भी योग्य छात्रों की सीट छीनने की चाहत के त्रिकोण ने ऐसी घटनाओं को जन्म दिया है। इसी त्रिकोण ने मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ लिपिक पद की परीक्षाओं तक के लिए भी देश भर में कोचिंग का जाल खड़ा कर दिया है। देश में अनेक कोचिंग हब बन गए हैं। आनलाइन-आफलाइन के कोचिंग तंत्र विकसित हो गए हैं और कोचिंग व्यवसाय एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। यह इंडस्ट्री अब अत्यंत समर्थ और शक्तिवान हो गई है। इसका टर्नओवर छह मिलियन डालर का हो गया है। आने वाले वर्षों में इसके 17 मिलियन डालर हो जाने की संभावना है। इस इंडस्ट्री में प्रतिवर्ष लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा रही है। जिस व्यवसाय में अपार धन निहित हो, वह किसी भी सिस्टम में छेद कर पेपर लीक करा सकता है। नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार कुछ लोग कोचिंग व्यवसाय से भी जुड़े हैं।

वास्तव में हर सिस्टम में ऐसे लोग होते हैं, जिनमें लालच अपना फन छुपाए प्रवेश कर जाता है। इसीलिए हाल में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक को एक सामाजिक बुराई कहा। ऐसी सामाजिक बुराई के खिलाफ सरकार और समाज, दोनों को साथ आकर काम करना होगा। सरकार अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने में तो लगी ही है, लोगों को भी खुद एक नैतिक समाज में तब्दील होना होगा। मेडिकल कालेजों की सीट में हेराफेरी में अनेक स्तरों पर कमीशनखोर एजेंट्स, कंसलटेंट नुमा दलालों और पेपर लीक करने वालों का जाल फैला हुआ है। यह बड़े शहरों से लेकर कस्बों तक फैल गया है। 1980 के दशक में जब हम स्कूली छात्र थे तो कोचिंग संस्थानों का जाल इतना नहीं फैला था। तब सरकारी स्कूल बेहतर स्थिति में थे और कमजोर छात्रों के लिए ही कोचिंग आवश्यक मानी जाती थी।

बद्री नारायण

नव उदार आर्थिकी आने पर जब बाजार आक्रामक हुआ तो उसने शिक्षा और परीक्षा को भी अपनी चपेट में ले लिया

नीट मामले में कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई। फाइल

1990 के दशक के बाद सरकारी स्कूल व्यवस्था कई जगह पर कमजोर हुई। इसका लाभ शिक्षा को व्यवसाय मानने वालों ने उठाया। यह वही दौर था जब भारत में मध्य वर्ग का कई गुना विस्तार हुआ। नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के आने के बाद जब बाजार आक्रामक हुआ तो उसने शिक्षा और परीक्षा को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसी समस्या को देखते हुए मोदी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई, उसमें शिक्षा मंत्रालय का सबसे ज्यादा जोर शिक्षा के माध्यम से ऐसा नैतिक मानस सृजित करना है, जो परंपरा से जुड़ा हुआ आधुनिक नवाचारी नागरिक हो।

शिक्षा मंत्रालय ने इस बार जैसे ही नीट पेपर लीक की खबर आई, उसे निरस्त किया और जांच सीबीआइ को सौंप दी। इसके साथ ही परेशान छात्रों के लिए आर्थिक एवं व्यवस्थागत सहयोग की कई घोषणाएं कीं। शिक्षा मंत्रालय का यह कदम योग्य छात्रों के हक पर अयोग्य एवं अनैतिक शक्तियों के कब्जा करने की रणनीति के खिलाफ सख्त पहल के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

पिछली बार जब ऐसी घटना हुई थी तो शिक्षा मंत्रालय ने कई सुधारात्मक कदम उठाए थे। पेपर लीक में लिप्त पाए गए लोगों को कठोर सजा देने के लिए सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन आफ अनफेयर मीन्स एक्ट बनाया और ऐसे मामलों से निजात पाने के लिए राधाकृष्णन कमेटी का गठन किया। एनटीए ने इस कमेटी की कुछ सिफारिशों को लागू भी किया है। इस कमेटी के सुझावों के अनुसार शिक्षा मंत्री ने अगले साल से नीट-यूजी, पीजी परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में कराने की घोषणा की है। इससे एक लाभ यह होगा कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रक्रिया काफी कुछ डिजिटल मोड में आ जाएगी। यह ठीक है कि इस मोड में परीक्षा कई दिन और कई सेट प्रश्नपत्रों के साथ करानी होगी और परीक्षा के मूल्यांकन हेतु संतुलित नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनानी होगी।

एक तरफ एनटीए अपनी व्यवस्था चाक चौबंद बनाने में लगा है, दूसरी तरफ छात्र पुनः परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच विरोधी दलों ने सरकार पर आक्रमण तेज कर दिया है, लेकिन पेपर लीक जैसे मुद्दे कभी भी राजनीतिक नहीं होते। ये बड़े अर्थों में सामाजिक मुद्दे भी होते है। पेपर लीक से निजात पाने के लिए हम सबको अपने अंदर झांककर खुद को सुधारते रहने होगा। आखिर पैसा देकर पेपर लीक कराने और लीक पेपर खरीदने वाले इसी समाज के लोग ही हैं। यह समय आरोप-प्रत्यारोप करने का नहीं। विकास के बड़े लक्ष्य पाने एवं देश के नव उत्थान का है। यह ठीक है कि नीट निरस्त होने से छात्रों और अभिभावकों के तनाव का क्षण लंबा हो गया, पर पुनः परीक्षा अयोग्य एवं भ्रष्ट शक्तियों के कब्जे की साजिश को रोकने की कोशिश है। यह वह प्रक्रिया है, जिससे गुजरकर ही नीट के प्रतिभागी छात्र एक नई सुबह तक पहुंच पाएंगे।

(लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई के कुलपति हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

सत्यमेव जयते

सत्य की सदैव विजय होती है और झूठ को एक न एक दिन पराजित होना पड़ता है। झूठ थोड़ी देर के लिए सुख जरूर दे सकता है, लेकिन अंततः उसे सत्य के समक्ष नतमस्तक होना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम को अनेकानेक झूठ के सहारे हतोत्साहित करने का काम किया गया, लेकिन अंत में हर झूठ उनके आगे पराजित हुआ। पहले झूठ के शिकार तो अयोध्या में ही हुए। कैकेयी ने किस प्रकार उन्हें वनवास के लिए राजा दशरथ को बाध्य किया। वे वनवास के लिए निकले तो सिर्फ तीन लोग ही थे। वन में मारीच हिरन वेश में श्रीराम को दूर तक ले गया तथा झूठ का सहारा लेकर लक्ष्मण को सीता जी से विलग कर दिया और रावण ने सीता का अपहरण किया, लेकिन श्रीराम हिम्मत नहीं हारे।

महाभारत में भी धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ छल-छद्म किया। दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित करना चाहा, लेकिन उसकी कुत्सित मंशा को श्रीकृष्ण ने ध्वस्त कर दिया। अंततः कौरवों एवं पांडवों का युद्ध हुआ। दुर्योधन की तरफ एक से एक ताकतवर योद्धा थे। यहां तक भीष्म पितामह भी कौरव सेना के साथ ही थे, लेकिन सत्य के प्रतीक श्रीकृष्ण पांडवों के सत्य के रथ के सारथी बने और उनके मार्गदर्शन में ही दुर्योधन एवं अनीति के रास्ते पर चल रहे उसके पूरे खेमे को खत्म कर दिया गया। इसी तरह झूठे हिरण्यकश्यप को अपने ही पुत्र प्रह्लाद के चलते पराजित होना पड़ा था।

इसलिए हमेशा सत्य के सहारे ही रहना चाहिए। एक झूठ बोलने से हमारे सैकड़ों पुण्य कर्म नष्ट होते हैं, जबकि सत्य के सहारे रहने पर मन हमेशा सशक्त रहता है, वहीं झूठे व्यक्ति का मन हमेशा भय में रहता है। मन हमेशा डरा-डरा रहने लगे तो हर काम में असफलता मिलती है।

सलिल पाण्डेय

म्यूआन की गुत्थी सुलझाने के करीब विज्ञान

प्रदीप

> **म्यूआन इलेक्ट्रान की तरह होता है, परंतु उससे दो सौ गुना भारी होता है। इसका जीवनकाल बहुत अल्प होता है**

ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम कणों की दुनिया में म्यूआन को एक लंबे अर्से से एक विचित्र और रहस्यमय कण माना जाता रहा है। दशकों से विज्ञानियों को लग रहा था कि यह सूक्ष्म उप-परमाण्विक कण शायद भौतिकी के स्थापित सिद्धांतों को चुनौती देने वाला है। दरअसल, इसके चुंबकीय व्यवहार में दिखने वाली एक छोटी-सी विसंगति ने विज्ञानियों को यह सोचने पर विवश कर दिया था कि कहीं प्रकृति में कोई नई शक्ति या अज्ञात कण विद्यमान तो नहीं है। लेकिन 'नेचर' में प्रकाशित एक अध्ययन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विज्ञान म्यूआन की गुत्थी को काफी हद तक सुलझाने के करीब पहुंच गया है।

म्यूआन इलेक्ट्रान जैसा होता है, लेकिन उससे लगभग 200 गुना भारी होता है। इसका जीवनकाल बहुत छोटा होता है और यह कुछ ही क्षणों में दूसरे कणों में परिवर्तित हो जाता है। फिर भी कण भौतिकी के क्षेत्र में इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका अध्ययन करने से हमें पदार्थ और ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों के बारे में जानने में मदद मिलती है।

म्यूआन को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सिद्धांत और प्रयोग दोनों से मापा जाता है। दिक्कत यह थी कि पिछले कई दशकों से प्रयोगों से हासिल मान और कण भौतिकी के 'मानक माडल' द्वारा की गई भविष्यवाणियां पूरी तरह मेल नहीं खा रही थीं। इसी अंतर को ''म्यूआन जी 2 विसंगति'' कहा गया। आगे चलकर यह विसंगति आधुनिक भौतिकी की सबसे चर्चित गुत्थियों में बदल गई। सर्न, ब्रुकहेवन नेशनल लैब और बाद में फर्मी लैब में हुए प्रयोगों ने इस विसंगति को और ज्यादा सटीकता से मापा। 2021 में फर्मी लैब के परिणामों ने वैज्ञानिक समुदाय में भारी उत्साह पैदा कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह विसंगति वास्तव में किसी 'नई भौतिकी' का संकेत हो सकती है।

इसकी व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत सामने आए। कुछ विज्ञानियों ने नए कणों की संभावना जताई, जबकि कुछ ने इसे 'पांचवीं मूलभूत शक्ति' का संकेत माना। अगर यह सही साबित होता, तो यह खोज आइंस्टाइन के सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत के बाद आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक होती। लेकिन हालिया अध्ययन ने तस्वीर को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के भौतिकविद जोल्टन फोडोर और उनके दल ने सुपरकंप्यूटरों की मदद से अब तक की सबसे सूक्ष्म गणनाएं कीं। नई गणनाओं ने दिखाया कि पहले दिखने वाली विसंगति शायद पुरानी गणनाओं की त्रुटियों की वजह से थी। बहरहाल, हालिया अध्ययन ने विज्ञान की एक बड़ी विशेषता को उजागर किया है: विज्ञान अपने ही सिद्धांतों की कठोर परीक्षा लेने से पीछे नहीं हटता।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

राजनीति में मर्यादा को हो पालन

'आदत से लाचार राहुल' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में सही रेखांकित किया गया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस नेत्री एवं अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से सीखना चाहिए कि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की कड़ी से कड़ी आलोचना कैसे की जा सकती है? दरअसल भाषा की मर्यादा के माध्यम से ही अपनी बातों को जनमानस में उचित तरीके से संप्रेषित किया जा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रत्युत्तर में भी सधी हुई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे कि राहुल गांधी को राहु के साथ जोड़ना। राजनीति सिद्धांतों और नीतियों पर आधारित होती है। इसमें सरकार की नीतियों की आलोचना को महत्व मिलना चाहिए। सरकार के काम में खामियों को भी जनता के सामने लाना बेहद जरूरी है। इसके लिए भाषा या व्यवहार की मर्यादा लांघने की जरूरत नहीं है। आखिर राजनीति दो शीर्षस्थ राजनेताओं के लिए जंग का अखाड़ा नहीं है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

राजनीतिक विमर्श में उत्तरदायित्व

राजनीतिक विमर्श में तथ्यहीन, अनुमान आधारित और भ्रामक बयानबाजी का बढ़ता चलन लोकतांत्रिक वातावरण को दूषित कर रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा अवश्य है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रमाण के ऐसे आरोप, दावे या आशंकाएं सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करे जिनसे समाज में भ्रम, अविश्वास और वैचारिक प्रदूषण फैले। अब समय आ गया है कि राजनीतिक बयानबाजी को भी उत्तरदायित्व और प्रमाणिकता के दायरे में लाया जाए। जो व्यक्ति सार्वजनिक मंच से कोई गंभीर आरोप या दावा करता है, उस पर उसे सिद्ध करने का दायित्व भी होना चाहिए। यदि वह अपने कथन के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत न कर सके, तो उसके लिए दंडात्मक प्रविधान होना चाहिए, ताकि सार्वजनिक जीवन में संयम और सत्यनिष्ठा बनी रहे। आज स्थिति यह बनती जा रही है कि तथ्यों से अधिक सनसनी और प्रचार को महत्व दिया जा रहा है। इससे जनता के मन में संशय, असंतोष और संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा होता है। लोकतंत्र स्वस्थ बहस और आलोचना से मजबूत होता है, लेकिन निराधार आरोपों और असत्य प्रचार से कमजोर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व को भी समान महत्व दिया जाए।

मानसिंह चुंडावत, मंदसौर, मध्य प्रदेश

मेलबाक्स

बेटियों की मौत का जिम्मेदार कौन

पिछले दिनों भोपाल की ट्विशा शर्मा और ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर की ससुराल में हुई मौतों ने पूरे देश में हलचल मचा दी। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौतों को ससुराल और मायका पक्ष, अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से दहेज मांगना, घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना इत्यादि सब गलत है। इन दोनों घटनाओं ने देश में लड़कियों के माता-पिता के लिए बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। जब माता-पिता को यह बात पता होती है कि उनकी बेटी को ससुराल वाले तंग करते हैं, मारते पीटते हैं, तो वे क्यों अपनी बेटी को वापस घर नहीं ले आते? जब दहेज की मांग शादी से पहले और बाद में भी निरंतर की जाती है, तो क्यों माता-पिता दहेज देते हैं। कई बार तो कर्ज लेकर वे ससुराल पक्ष की मांगे पूरी करते हैं। क्यों वे अपनी हैसियत से बाहर जाकर शादी में पैसा खर्च करते हैं? क्या लड़की के माता-पिता का कोई कसूर नहीं जो अपनी बेटियों को ससुराल में अत्याचार सहने के लिए छोड़ देते हैं? या अपनी इज्जत और समाज की परंपराओं की दुहाई देकर बेटियों को गलत सहने पर मजबूर करते हैं। बदलते परिवेश में माता-पिता की यह जिम्मेदारी बन चुकी है कि वे अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि वह गलत शादी को इसलिए न निभाए कि वह मां-बाप पर बोझ बन जाएगी। उसे निर्भय और बेबाक बनाएं जिससे ससुराल में होने वाले शोषण के खिलाफ तुरंत आवाज उठा सके।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली।

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

5.72 लाख पद रिक्त हैं वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में जहां स्वीकृत पदों की संख्या 45.46 लाख है। वहीं वर्ष 2024-25 में माध्यमिक स्कूलों में स्वीकृत पदों की संख्या 24.29 लाख है जिनमें से लगभग चार लाख पद रिक्त हैं।

आजकल

सरकारी स्कूलों में व्यवस्थागत सुधार

शिक्षा व्यवस्था राष्ट्र की नींव होती है। भारत जिस प्रकार कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार यह सरकारी स्कूल या शिक्षा प्रधान भी है। गांव-देहात में रहने वाले करोड़ों बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। उनके पास न तो आर्थिक संपन्नता है और न ही ऐसे दूसरे संसाधन हैं कि वे निजी स्कूलों का रुख कर सकें। प्रत्येक बच्चे तक समुचित शिक्षा की पहुंच के बिना विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। लिहाजा सरकारी स्कूलों में भी बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए

डा. वेदप्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

विगत दिनों सरकारी स्कूलों से संबंधित दो महत्वपूर्ण समाचार सामने आए। पहला समाचार शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की 349 वीं और 363 वीं रिपोर्ट से संबंधित था, जिसमें शिक्षकों के खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की बार-बार सिफारिश की गई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्कूलों के स्वीकृत 45.46 लाख पदों में से 5.72 लाख पद रिक्त हैं। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में माध्यमिक स्कूलों के स्वीकृत 24.29 लाख पदों में से लगभग चार लाख पद रिक्त हैं। अनेक स्थानों पर अतिथि व संविदा शिक्षक काम कर रहे हैं। गौरतलब यह भी है कि केंद्र सरकार राज्यों को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 41,249 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यों को आवंटित कर चुका है। क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट और बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो फिर इसके जिम्मेदार राज्यों और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?

दूसरा समाचार नीति आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है, जिसके अनुसार विगत दो दशकों में सरकारी स्कूलों में दाखिले में 22 प्रतिशत की गिरावट आई है। वर्ष 2005 में जहां 71 प्रतिशत दाखिले सरकारी स्कूलों में होते थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा घटकर 49 प्रतिशत रह गया है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि अब सभी माध्यमिक संस्थानों में प्राइवेट स्कूलों की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत हो गई है जो निजी शिक्षा की ओर अभिभावकों के झुकाव को दर्शाता है। उपरोक्त दोनों समाचार जहां एक ओर सरकारी स्कूलों की बदहाली को व्यक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य स्तर पर शासन-प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करते हैं।

देश में लगभग एक लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। क्या यह स्थिति चिंताजनक नहीं है? सर्वविदित यह भी है कि देश में अनेक सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां आज भी शौचालय, पीने का पानी, विद्यार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, भवन एवं स्कूल तक जाने का रास्ता जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। सत्य यह भी है कि सरकारी स्कूलों के लाखों शिक्षक समय-समय पर मतदान, मतदाता सूची पुनरीक्षण, जनगणना एवं विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों एवं अभियानों में लगा दिए जाते हैं। क्या ऐसे में उनकी अध्ययन-अध्यापन की गतिविधियां प्रभावित नहीं होती हैं?

पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति : शैक्षिक सत्र शुरू हुए एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पाठ्य पुस्तकों की मांग और आपूर्ति के हिसाब से एनसीईआरटी की अब तक केवल आधी पुस्तकें ही छपी हैं। यद्यपि एनसीईआरटी ने नए पाठ्यक्रम ढांचे को बहुत पहले मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत कक्षा तीन से नौ तक की संशोधित पाठ्य पुस्तकें सही समय पर आ जानी चाहिए थी। लेकिन अब तक आधी पुस्तकें ही छाप पाना समुचित योजना और कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। दूसरी ओर निजी स्कूलों में निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकों पर निर्भरता बढ़ रही है। वहां कोई ऐसा प्रशासनिक आदेश लागू नहीं होता कि निजी स्कूल भी एनसीईआरटी की पुस्तकों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे।

शिक्षा मंत्रालय लगातार कौशल विकास, तकनीक आधारित शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं गुणवत्ता आदि के लिए प्रयासरत है। लेकिन ऐसे विद्यालय जहां न तो मूलभूत सुविधाएं हैं और न ही शिक्षकों की समुचित संख्या है, क्या वहां पर उपरोक्त प्रयास अथवा विचार लागू हो पाना संभव है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गुणवत्तापूर्ण, शिक्षा समावेशी, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ड्रापआउट बच्चों की संख्या कम करना एवं तकनीक के उपयोग पर जोर देने जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण प्रविधान हैं, लेकिन वह धरातल से बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा एवं स्कूलों को लेकर बाल्यावस्था विकास, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा, उच्चतर गुणवत्ता का बुनियादी ढांचा, शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरना, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात सुनिश्चित करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान देना जैसे दर्जनों विचार और प्रविधान हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति पूर्ववत है।

छत्तीसगढ़ के पांच हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। उत्तराखंड के 1,655 विद्यालयों में छात्रों के लिए शौचालय नहीं हैं। क्या ऐसे में उन्नत शिक्षा की बात केवल जुमला नहीं है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। आज भी देश के आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार में साक्षरता की अनुमानित दर 70 से 75 प्रतिशत ही है।

स्कूली शिक्षा की तस्वीर बदलने अथवा उसमें सुधारों की दृष्टि से केंद्र सरकार की ओर से पीएम श्री स्कूल, समग्र शिक्षा, प्रेरणा, उल्लास, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, विद्यांजलि, दीक्षा जैसी विभिन्न योजनाएं आरंभ की गई हैं, लेकिन क्या ये योजनाएं दूरदराज क्षेत्रों में पहुंच पा रही हैं? सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए वहां व्यापक स्तर पर आमूलचूल परिवर्तनों और सतत निगरानी की आवश्यकता है। धरातल पर उतरकर यथार्थ को समझना होगा। देश के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल समस्याओं से ग्रसित हैं। इन स्कूलों में भी सुधारों के व्यापक पैमाने बनाकर निरंतर काम करना होगा।

देश के सभी गांवों और दूरदराज क्षेत्रों में हर बच्चे के लिए सुगम और सरल बने स्कूली शिक्षा। फाइल

अंकों की प्रतिस्पर्धा से सीखने की दिशा में बदलाव

आदित्य कुमार
शिक्षा मामलों के जानकार

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा को लंबे समय से सफलता का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता रहा है। विद्यार्थियों की क्षमता, बुद्धिमत्ता और भविष्य का आकलन मुख्य रूप से परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। परिणामस्वरूप शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के बजाय अधिक अंक हासिल करना बनता जा रहा है। आज स्कूलों में पढ़ाई से अधिक परीक्षा की तैयारी पर जोर दिया जाता है। ऐसे में स्कूली परीक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता एक गंभीर राष्ट्रीय विषय बन चुका है। देखा जाए तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी रटंत प्रवृत्ति है। वस्तुतः विद्यार्थी विषय को समझने के बजाय उत्तर याद करने में अधिक समय लगाते हैं। परीक्षा समाप्त होते ही सीखा गया अधिकांश पाठ भूल जाता है। यह प्रणाली बच्चों की रचनात्मकता, जिज्ञासा और स्वतंत्र सोच को सीमित कर देती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व विकास और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना होना चाहिए।

चिंताजनक यह कि परीक्षाओं का बढ़ता दबाव विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को भी दुष्प्रभावित कर रहा है। बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान अनेक छात्र तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। असफलता का भय बच्चों में आत्मविश्वास की कमी पैदा करता है। कई बार समाज और अभिभावकों की अत्यधिक अपेक्षाएं भी विद्यार्थियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ा देती हैं। शिक्षा का वातावरण प्रेरणादायक होने के बजाय भयपूर्ण बनता जा रहा है।

वर्तमान परीक्षा व्यवस्था सभी विद्यार्थियों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन नहीं कर पाती। हर छात्र की रुचि और क्षमता अलग होती है, लेकिन एक समान लिखित परीक्षा से सभी को मापना उचित नहीं कहा जा सकता। कला, खेल, संगीत, नेतृत्व क्षमता और व्यावहारिक कौशल जैसे क्षेत्रों को पर्याप्त महत्व नहीं मिल पाता। इससे अनेक प्रतिभाएं उभरने से पहले ही दब जाती हैं। वस्तुतः हमें विविधता का भी सम्मान करना चाहिए। जिस बच्चे में जो प्रतिभा है, उसकी समय पर पहचान करते हुए उसे उसी ओर आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए।

नई शिक्षा नीति 2020 ने परीक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इसमें रटंत शिक्षा के स्थान पर अवधारणात्मक समझ और कौशल आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है। नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षार्थी नहीं, बल्कि विचारशील और सक्षम नागरिक बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक व्यावहारिक और विद्यार्थी-केंद्रित बनाया जाना चाहिए। वार्षिक परीक्षा के साथ-साथ सतत एवं समग्र मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। परियोजना कार्य, प्रयोगात्मक गतिविधियां, मौखिक प्रस्तुति और कक्षा सहभागिता को भी मूल्यांकन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों पर एक दिन की परीक्षा का दबाव कम होगा और उनकी वास्तविक क्षमता सामने आ सकेगी। तकनीक भी परीक्षा सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। डिजिटल मूल्यांकन, आनलाइन परीक्षण और व्यक्तिगत प्रगति रिपोर्ट शिक्षा को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना सकते हैं। साथ ही विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों की व्यवस्था भी आवश्यक है।

अंततः शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक तैयार करना है। जब परीक्षा व्यवस्था ज्ञान, समझ, कौशल और रचनात्मकता आदि को महत्व देगी, तभी शिक्षा वास्तव में समाज और राष्ट्र के विकास का सशक्त माध्यम बन सकती है।

खरी-खरी

मई में मेलोनी और मितव्ययिता की तपिश

विनोद कुमार विक्की

कभी दूरदर्शन पर मासूमियत से पूछा जाता था, 'मेलोडी इतनी चाकलेटी क्यों है?' और जवाब मिलता था, 'मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ!'

अब जमाना बदल गया है। अब जवाब कुछ यूं है, 'सेल्फी देखो, खुद समझ जाओ!'

मई में देश में 'ट्रिपल एम' की चर्चा परवान पर है- मोदी, मेलोनी और मेलोडी। वैसे 'म' से मैत्री और मितव्ययिता भी चलन में है। राजनीति अब सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रही, उसमें चाकलेट का फ्लेवर भी घुल चुका है।

बंगाल में दस रुपये की झालमुड़ी खरीद कर मितव्ययिता का शंखनाद किया गया जिससे आलोचकों की जीभ पर मिर्ची और झाल का स्वाद प्राप्त हुआ। जबकि समर्थकों ने इसे सादगी का प्रतीक बताया, मानो देशहित अब थाली में नहीं, ठेले पर परोसा जा रहा हो।

उधर, इटली में चाकलेट का कूटनीतिक आदान-प्रदान हुआ। महंगे तोहफों के इस दौर में सस्ती मेलोडी ने जो कमाल किया, वह किसी 'इकोनमिक रिफार्म' से कम नहीं। एक पैकेट चाकलेट और एक मुस्कुराती सेल्फी, बस हो गई मित्रता की मिठास सील! हालांकि, इस मिठास प्रकरण से कुछ लोगों का 'शुगर लेवल' अचानक बढ़ गया है।

आलोचकों की मानें तो जनता को सार्वजनिक वाहन से चलने और विदेशी यात्रा न करने की सीख देने वाले खुद आसमान नाप रहे हैं! सादगी का उपदेश जमीन पर और उसका प्रदर्शन हवाई यात्रा के साथ! वस्तुतः सादगी भी इन दिनों 'इवेंट मैनेजमेंट' का हिस्सा बन चुकी है। आलोचकों को शिकायत रहती है कि उनके द्वारा हर काम उल्टा-पुल्टा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर फरवरी में मनाया जाने वाला 'चाकलेट डे' मई में मनाया गया!

मैत्री और मितव्ययिता का यह नया माडल बड़ा दिलचस्प है, जहां दस रुपये की झालमुड़ी और मेलोडी मिलन को समर्थक मितव्ययिता के चश्मे से देखते हैं तो विरोधी आलोचना के लेंस से। बहरहाल, मई की तपिश में 'म' से मोदी, मेलोनी, मैत्री, मेलोडी और मितव्ययिता सुर्खियों में है।

X पोस्ट

काकरोच पार्टी की इंटरनेट मीडिया पर लोकप्रियता को तूफान बनाने वाले विद्वानों को चेता दें कि किसान आंदोलन के नेता चढ़ूनी जी को करीब ग्यारह सौ वोट मिले थे और किसान नेता राकेश टिकैत जी के अपने बूथ से भाजपा जीती थी। बाकी जिसे जितना झाड़ पर चढ़ाना है, चढ़ा लीजिए।

सी फेयरर@World_neptuner

एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इंटरनेट मीडिया पर लाइक और रीपोस्ट कर खुद को एक सजग नागरिक समझने की भूल कर बैठता है। यही भ्रम विपक्षी पार्टियों के कई दिग्गजों ने भी पाल रखा है। दुष्यंत कुमार होते तो कहते : तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अब देख रहा हूं कि 'काकरोच' एक बड़े वर्ग का 'चौकीदार' हो गया है।

राहुल पंडिता@rahulpandita

पीएम मोदी ने मेलोडी टाफी गिफ्ट क्या की, लोग उस पारले कंपनी के शेयर खरीदने दौड़ पड़े, जिसका मेलोडी से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं था। यही सब देखकर समझ आ जाता है कि आज का ट्रेंड किसी विचार से नहीं, एक सामूहिक उत्तेजना से चलता है।

अतुल कुमार राय@AuthorAtul

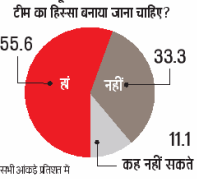

झारखंड डायरी

सरना धर्म कोड पर हेमंत की सधी चाल

प्रदीप सिंह
संपादकीय प्रभारी, जमशेदपुर

झारखंड की राजनीति में एक बार फिर आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड का मुद्दा गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को नए सिरे से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाकर राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर बड़ा संदेश दिया है। यह केवल एक प्रशासनिक मांग नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। झारखंड विधानसभा में सर्वसम्मति से अलग सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मांग को लागू करने की अपील भी कर चुके हैं। ऐसे समय में जब भाजपा आदिवासी इलाकों में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए सक्रिय दिख रही है। हेमंत ने इस मुद्दे को एक ऐसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, जो भाजपा के अभियान को कठिन बना सकता है।

भारत की जनगणना में धर्म के कालम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन जैसे विकल्प मौजूद हैं। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में रहने वाले आदिवासी समुदाय लंबे समय से सरना धर्म को अलग कोड के रूप में मान्यता देने की मांग करते रहे हैं। आदिवासी संगठनों का तर्क है कि उन्हें हिंदू या अन्य धर्मों के अंतर्गत दिखाना उनकी मूल सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करता है। वे प्रकृति, जल, जंगल और जमीन की पूजा करते हैं। उनकी परंपराएं और सामाजिक व्यवस्था अलग है। ऐसे में जनगणना में अलग धर्म कोड उनकी वास्तविक संख्या और सांस्कृतिक अस्तित्व को सामने लाएगा।

दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अच्छी तरह जानते हैं कि झारखंड की राजनीति का केंद्र आदिवासी भावना और पहचान है। राज्य निर्माण आंदोलन से लेकर आज तक जल-जंगल-जमीन और प्रांतीय अस्मिता सबसे प्रभावशाली राजनीतिक मुद्दे रहे हैं। भाजपा पिछले कुछ वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हेमंत सोरेन ने अलग धर्म कोड के मुद्दे को हवा देकर भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में ला खड़ा किया है।

हेमंत सोरेन। फाइल

इधर भाजपा की वैचारिक राजनीति आदिवासियों को व्यापक हिंदू समाज का हिस्सा मानती रही है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और क्षेत्रीय आदिवासी संगठन आदिवासी पहचान को अलग सांस्कृतिक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही वह वैचारिक अंतर है, जिस पर हेमंत सोरेन अपनी राजनीति को मजबूत कर रहे हैं। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह आदिवासी समुदाय को नाराज भी नहीं करना चाहती और अपनी वैचारिक रेखा से पूरी तरह अलग भी नहीं जा सकती। यदि पार्टी खुलकर अलग धर्म कोड का समर्थन करती है तो उसका पारंपरिक हिंदुत्व विमर्श प्रभावित हो सकता है। लेकिन विरोध करने पर आदिवासी क्षेत्रों में राजनीतिक नुकसान का खतरा है।

यही कारण है कि भाजपा इस मुद्दे पर बेहद सावधानी से कदम रखती दिखाई देती है। पार्टी आदिवासी विकास, योजनाओं और केंद्रीय सहायता के जरिये अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है, लेकिन पहचान आधारित राजनीति में वह उतनी सहज नहीं दिखती जितनी झामुमो। हेमंत सोरेन इसी राजनीतिक असहजता का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

यदि जनगणना में अलग सरना धर्म कोड लागू होता है तो देश में आदिवासी प्रकृति पूजक समुदाय की वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी। इससे भविष्य में नीति निर्माण और राजनीतिक समीकरणों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि यह मुद्दा केवल झारखंड तक सीमित नहीं रह गया है। हेमंत सोरेन ने इस मांग को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाकर खुद को आदिवासी राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है।

इस बीच भाजपा आदिवासी इलाकों में संगठनात्मक स्तर पर काफी सक्रिय हुई है। केंद्रीय योजनाओं, जनजातीय गौरव दिवस, आदिवासी नायकों के सम्मान और बूथ स्तर तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन झारखंड में केवल विकास का विमर्श पर्याप्त नहीं होता। यहां भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान की राजनीति का प्रभाव गहरा है। अलग धर्म कोड का सवाल आदिवासी समाज में भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है।

ऐसे में हेमंत सोरेन भाजपा को आदिवासी पहचान बनाम वैचारिक राजनीति के फ्रेम में घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यदि यह नैरेटिव मजबूत होता है तो भाजपा का अभियान प्रभावित हो सकता है, खासकर संथाल परगना और कोल्हान जैसे क्षेत्रों में। यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या यह मुद्दा चुनावी स्तर पर बड़ा असर डालेगा। इसका उत्तर पूरी तरह राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि केंद्र सरकार इस मांग पर सकारात्मक संकेत देती है तो उसका राजनीतिक लाभ भाजपा भी लेने की कोशिश करेगी। लेकिन यदि मामला लंबा खिंचता है तो हेमंत सोरेन इसे आदिवासी अधिकारों की अनदेखी के रूप में लगातार उठाते रहेंगे।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टी-20 टीम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए?

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या ईरान को दी जा रहीं ट्रंप की धमकियां बेअसर साबित हो रही हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

रिश्ते में मौसी लगें क्यों खाते हो खार,
भिजवा देते आप भी कुछ 'देसी' उपहार।
कुछ 'देसी' उपहार न लगती ज्यादा लागत,
जाते जब ननिहाल आपका होता स्वागत!
मोदी जी उपहार भले देते हों सस्ते,
पर लेते दिल जीत जीत लेते हैं रिश्ते!!

-ओम प्रकाश तिवारी

मंथन

राष्ट्रहित में त्याग की परंपरा

वसुधैव कुटुंबकम् का अर्थ केवल वैश्विक भाईचारा नहीं, साझा संसाधनों के प्रति उत्तरदायित्व भी है। संकट के समय में समाज की शक्ति त्याग और सामूहिक सहयोग से बढ़ती है

डा. मीना कुमारी जांगिड़
वरिष्ठ पत्रकार

भारत का इतिहास बताता है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी सेना, अर्थव्यवस्था या राजनीतिक नेतृत्व में नहीं होती, बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना में होती है जो संकट के समय समाज को अनुशासित और एकजुट बनाए रखती है। आज जब प्रधानमंत्री द्वारा विदेशी मुद्रा बचाने, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग, सार्वजनिक परिवहन अपनाने, अनावश्यक उपभोग सीमित करने, सोने की खरीद कम करने और 'वर्क फ्राम होम' जैसी अपीलें की जा रही हैं, तो इन्हें केवल आर्थिक निर्णयों के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के विचार के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

भारतीय ज्ञान परंपरा में संयम को केवल व्यक्तिगत सद्गुण नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता का आधार माना गया है। उपनिषदों से लेकर बौद्ध और जैन दर्शन तक, आवश्यकता और विलासिता के बीच संतुलन पर बल दिया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के सात अंगों में 'कोष' और 'जनपद' को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कौटिल्य लिखते हैं कि संकट के समय राजा को विलासिता सीमित करनी चाहिए, आयातित वस्तुओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि राज्य की आर्थिक शक्ति सुरक्षित रहे। यह विचार आज के स्वदेशी और विदेशी मुद्रा संरक्षण के आग्रह से सीधा संबंध रखता है। भारतीय प्रशासनिक चिंतन में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नीति नहीं थी, यह राजनीतिक स्वतंत्रता की शर्त मानी जाती थी।

साझा संपदा का संरक्षण : भारतीय परंपरा में जल, अन्न और ऊर्जा जैसे संसाधनों को 'साझा संपदा' माना गया। दक्षिण भारत की चोल और पांड्य व्यवस्थाओं में जलाशयों और सिंचाई टैंकों का सामुदायिक प्रबंधन होता था। राजस्थान में बावड़ियां और तालाब केवल जलस्रोत नहीं, बल्कि संकट प्रबंधन की व्यवस्था थे। युद्ध और अकाल के समय मुनादी कर लोगों से जल और अन्न के संरक्षण का आह्वान किया जाता था। यह सब आधुनिक 'सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट' की अवधारणा का भारतीय रूप था। मध्यकालीन भारत में भी युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, वह आर्थिक और सामाजिक अनुशासन की परीक्षा भी होता था। राजपूत और मराठा राज्यों में संकट के समय जनता को किलों में सुरक्षित पहुंचाने, कृषि भूमि बचाने और आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रित उपयोग की घोषणाएं की जाती थीं।

विश्व इतिहास में भी ऐसे उदाहरण अनेक हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटेन ने 'डिग फार विक्ट्री' अभियान चलाकर नागरिकों को घरों में खाद्यान्न उगाने के लिए प्रेरित किया। निजी वाहनों का उपयोग सीमित किया गया और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी गई। अमेरिका में पेट्रोल, रबर और धातुओं की बचत के लिए राष्ट्रीय अभियान चले। जापान ने युद्धकाल में औद्योगिक अनुशासन और न्यूनतम उपभोग संस्कृति अपनाई।

भारत ने भी स्वतंत्रता के बाद ऐसे अनुभव देखे। वर्ष 1965 के खाद्यान्न संकट और युद्धकाल में तबके प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान, जय किसान' का आह्वान किया। यह केवल नारा नहीं था, इसके पीछे भारतीय आत्मनिर्भरता का दर्शन था। देश में साप्ताहिक उपवास का आह्वान किया गया, ताकि अन्न की बचत हो सके। लोगों ने इसे सरकारी आदेश से अधिक राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया।

सोने की खरीद सीमित करने की अपील का भी भारतीय संदर्भ महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में सोना केवल आभूषण नहीं, बल्कि सुरक्षा और प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है। लेकिन आर्थिक संकट के समय अत्यधिक सोना आयात करना विदेशी मुद्रा पर दबाव डालता है। इसलिए विभिन्न समय में सरकारों ने नागरिकों से संयम बरतने की अपील की। आज जब सार्वजनिक परिवहन, स्वदेशी उपभोग और सीमित विलासिता की बात की जाती है, तो यह केवल आर्थिक रणनीति नहीं है, यह भारतीय ज्ञान परंपरा के उस विचार का आधुनिक रूप है जिसमें हमारा आचरण राष्ट्रहित से जुड़ा माना गया है।

इतिहास यह स्पष्ट करता है कि महान राष्ट्र केवल युद्ध जीतकर नहीं बनते, वे अपने नागरिकों की जीवनशैली, अनुशासन और सांस्कृतिक चेतना से मजबूत होते हैं। चाहे वह प्राचीन भारत का अन्न-संरक्षण हो, शास्त्री युग का उपवास अभियान हो, या आधुनिक समय में स्वदेशी और संसाधन संरक्षण की अपील इन सबका मूल संदेश एक ही है: राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण नागरिकों के दैनिक व्यवहार से होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उसने अर्थव्यवस्था, नैतिकता और समाज को अलग-अलग नहीं देखा। आज की नीतियों में यदि उस परंपरा के तत्व दिखाई देते हैं, तो यह केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की स्थिरता की दिशा में एक सांस्कृतिक पुनर्स्मरण भी है।

सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग से ऊर्जा संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। फाइल

एलजी इलेक्ट्रानिक्स को 692 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ

नई दिल्ली: घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी एलजी इलेक्ट्रानिक्स इंडिया ने गुरुवार को बताया कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के दौरान उसका शुद्ध लाभ 8.19 प्रतिशत घटकर 692.7 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वर्ष समान तिमाही में कंपनी को 754.54 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। हालांकि, बीती तिमाही में कंपनी का संचालन राजस्व 8.12 प्रतिशत बढ़कर 8,053.55 करोड़ रुपये रहा है। जनवरी-मार्च 2025 में कंपनी का संचालन राजस्व 7,448.42 करोड़ रुपये था। (प्रेट्र)

भू-राजनीतिक तनावों के बीच वैश्विक माल ढुलाई लागत में 28-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी भारत के इस्पात उद्योग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है।
- डीबी सुंदर रमम, वाइस प्रेसिडेंट, टाटा स्टील

सेंसेक्स 75,183.36 ▼ 135.03	निफ्टी 23,654.70 ▼ 4.30	सोना प्रति दस ग्राम ₹ 1,65,500 ▲ ₹ 600	चांदी प्रति किलो ग्राम ₹ 2,71,000 ▲ ₹ 5,000	डालर ₹ 96.36 ▼ ₹ 0.50	क्रूड प्रति बैरल $ 104.3

एक नजर में

10 रुपये प्रति शेयर का लाभांश देगी एलआइसी

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआइसी के बोर्ड ने अपने शेयरधारकों को 10 रुपये प्रति शेयर का लाभांश देने की सिफारिश की है। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के दौरान उसका शुद्ध लाभ 23 प्रतिशत बढ़कर 23,420 करोड़ रुपये और कुल आय बढ़कर 2,53,592 करोड़ रुपये रही है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 19 प्रतिशत बढ़कर 57,419 करोड़ रुपये रहा है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 48,151 करोड़ रुपये रहा है। (प्रेट्र)

पश्चिम एशिया संकट से गेल का लाभ 38% घटा

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को बताया कि जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के दौरान उसका शुद्ध लाभ 38 प्रतिशत घटकर 1,262.18 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई रुकावटें हैं। मार्च की शुरुआत से ही, ईरान युद्ध के कारण सबसे बड़े सप्लायर कतर से होने वाले लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात में रुकावट आ गई थी। (प्रेट्र)

आइपीओ से जेप्टो जुटा सकता है 11 हजार करोड़

नई दिल्ली: क्विक कामर्स प्लेटफार्म जेप्टो जुलाई में 11 हजार करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने की योजना बना रहा है। इसको इस महीने की शुरुआत में सेबी से आइपीओ लाने की मंजूरी मिल चुकी है। जेप्टो जल्द ही अपडेट आइपीओ दस्तावेज जमा करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि जेप्टो के संस्थापकों ने 31 जुलाई से पहले शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने का लक्ष्य रखा है। अगस्त 2023 में 1.4 अरब डालर के मूल्यांकन पर 20 करोड़ डालर जुटाए जाने के साथ जेप्टो को यूनिकार्न का दर्जा मिला था। (प्रेट्र)

बढ़ती महंगाई पर लगाम के लिए जून में ब्याज दरों को बढ़ा सकता है आरबीआइ

अगले माह के पहले सप्ताह में होगी केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक

- पश्चिम एशिया संकट से लगातार दबाव में है कच्चा तेल
- रुपये में लगातार गिरावट से आयातित वस्तुएं हो रही महंगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में हो रही लगातार गिरावट और पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ती महंगाई को देखते हुए आर्थिक विशेषज्ञ बैंक दरों में बढ़ोतरी का कयास लगाने लगे हैं। आरबीआइ की मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक जून के पहले सप्ताह में होगी, जिसमें बैंक दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अर्थशास्त्री का मानना है कि कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी और रुपये के कमजोर होने से महंगाई बढ़ रही है, जिस पर लगाम के लिए आरबीआइ यह कदम उठा सकता है।

आरबीआइ ने अपनी पिछली समीक्षा बैठक में बैंक दर में कोई बदलाव नहीं किया था। हालांकि, अभी खुदरा महंगाई की दर आरबीआइ के उच्चतम पैमाने से काफी नीचे हैं। आरबीआइ छह प्रतिशत से अधिक की खुदरा महंगाई दर को काबू से बाहर मानता है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर बढ़ोतरी के साथ 3.48 प्रतिशत पर पहुंच गई है। हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब चार रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इससे ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने माल भाड़ा में चार प्रतिशत बढ़ोतरी का एलान किया है, जिससे सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। रुपये में हो रही लगातार गिरावट से आयातित वस्तुएं महंगी होती जा रही है। औद्योगिक जिंसों के साथ कृषि जिंस भी महंगे हो रहे हैं। ऐसे में मई की खुदरा महंगाई दर चार प्रतिशत से अधिक रहने की उम्मीद की जा रही है। पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। अमेरिका और ईरान में कोई समझौता नहीं होता दिख रहा है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है और कीमतें प्रभावित हो रही हैं। सरकार ने आरबीआइ को दो प्रतिशत की घट-बढ़ के साथ खुदरा मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य दिया है।

3.5 लाख करोड़ रुपये का लाभांश दे सकता है आरबीआइ

मुंबई, आइएएनएस: आरबीआइ वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार को 2.7 लाख करोड़ से 3.5 लाख करोड़ रुपये तक का लाभांश दे सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सरप्लस ट्रांसफर पर विचार के लिए आरबीआइ बोर्ड की शुक्रवार को बैठक होगी। अगर अनुमान के ऊपरी स्तर को मंजूरी मिलती है तो यह आरबीआइ की तरफ से सरकार को अब तक का बससे ज्यादा लाभांश भुगतान होगा।

अब 270 गीगावाट के पार बिजली की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश में गुरुवार को बिजली की अधिकतम मांग 270.82 गीगावाट के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई। बुधवार को बिजली की अधिकतम मांग 265.44 गीगावाट थी। बता दें कि बिजली मंत्रालय ने अनुमान लगाया था कि इस गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग 270 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। बिजली मंत्रालय ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गुरुवार लगातार चौथे दिन बिजली की अधिकतम मांग अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। दोपहर 3:45 बजे 270.82 गीगावाट की अधिकतम मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि मांग में यह वृद्धि देशभर में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए कूलिंग अप्लायंसेज के ज्यादा इस्तेमाल से जुड़ी हुई लगती है। बिजली की अधिकतम मांग में थर्मल पावर की हिस्सेदारी 62.8 प्रतिशत, सोलर की 22.0 प्रतिशत, विंड की 5.0 प्रतिशत, हाइड्रो से 5.8 प्रतिशत और बाकी दूसरे स्रोतों की रही।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से 50 पैसे मजबूत हुआ रुपया

मुंबई, प्रेट्र: कच्चे तेल की कीमतों में ऊंचे स्तर से गिरावट आने के बाद गुरुवार को रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर से 50 पैसे बढ़कर डालर के मुकाबले 96.36 पर बंद हुआ। भू-राजनीतिक तनाव कम होने और रुपये में तेज उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए आरबीआइ के दखल की संभावना ने भी रुपये को मजबूती प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि हाल के भू-राजनीतिक तनाव के बाद रुपये में तेजी आई है, लेकिन निवेशक अभी तेल की कीमतों की संवेदनशीलता का अंदाजा लगा रहे हैं। इस बीच, रुपये का एक साल का फारवर्ड मार्केट बुधवार को 100 रुपये प्रति डालर के निशान को छू गया। इससे पता चलता है कि मुद्रा बाजार अगले 12 महीनों में रुपये के और कमजोर होने की आशंका जता रहा है।

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डालर के मुकाबले 96.25 पर खुला, फिर इंट्राडे ट्रेड में 96.05 के शुरुआती उच्चस्तर और 96.60 के निचले स्तर को छुआ। हालांकि, अंत में यह 96.36 पर बंद हुआ।

सोना 600 तो चांदी 5,000 रुपये बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र: गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सोने 600 रुपये बढ़कर 1,65,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले तीन कारोबारी दिनों में कीमती धातु 2,700 रुपये बढ़ी है। चांदी की कीमतों में भी रिकवरी दर्ज की गई और यह 5,000 रुपये बढ़कर 2,71,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

जेपी फर्टिलाइजर का 1,500 करोड़ में अधिग्रहण करेगी अदाणी पोर्ट्स

- कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है जेपी फर्टिलाइजर्स
- अदाणी पोर्ट्स ने कहा-इससे उत्तर भारत में लाजिस्टिक्स मौजूदगी बेहतर होगी

नई दिल्ली, प्रेट्र: अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनमिक जोन (एपीएसईजेड) 1,500 करोड़ रुपये में जेपी फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रीज (जेएफआइएल) में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए मंजूर समाधान योजना के तहत यह अधिग्रहण किया जाएगा।

जेपी फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रीज कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (केएफसीएल) की होल्डिंग कंपनी है। केएफसीएल के पास कानपुर में 243 एकड़ जमीन है और यह कंपनी के लाजिस्टिक्स बिजनेस के लिए बहुत उपयोगी है। शेयर बाजार को दी जानकारी में अदाणी पोर्ट्स ने कहा कि इस अधिग्रहण से कंपनी की उत्तर भारत में इनलैंड लाजिस्टिक्स मौजूदगी और सर्विस क्षमताएं और मजबूत होंगी।

जेपी पावर की 24 प्रतिशत हिस्सेदारी लेगी अदाणी पावर : अदाणी पावर ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी और अन्य तापीय परिसंपत्तियां करीब 4,193.59 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए जयप्रकाश एसोसिएट्स से अंतिम समझौते किए हैं। इसके अलावा, अदाणी पावर ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के चुर्क (उत्तर प्रदेश) स्थित 180 मेगावाट तापीय बिजली संयंत्र और अन्य संबंधित संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक व्यवसाय हस्तांतरण समझौता किया है।

30 हजार रुपये महंगे होंगे मारुति के वाहन

नई दिल्ली, प्रेट्र: दिग्गज कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने गुरुवार को अपने सभी वाहनों के मूल्य में 30 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा की। कंपनी ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि महंगाई के दबाव और प्रतिकूल लागत परिवेश के चलते मूल्य में यह वृद्धि की गई है, जो जून से लागू होगी। यह मूल्य वृद्धि माडल के अनुरूप अलग-अलग होगी।

कंपनी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से बढ़ती लागत के असर को कम करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अब जब महंगाई का दबाव काफी बढ़ गया है और लागत का प्रतिकूल माहौल बना हुआ है, तो कंपनी को बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार पर डालना पड़ रहा है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम हो। जीएसटी दरों में कटौती के बाद कंपनी ने पिछले वर्ष सितंबर में अपने वाहनों का मूल्य घटाया था।

पेटेंट में अव्वल, अंतिम उत्पाद बनाने में पिछड़ा है भारत

- नीति आयोग ने इनोवेशन, विज्ञान और तकनीक को लेकर सरकार को दिए कई सुझाव
- रिसर्च को अंतिम उत्पाद में बदलने के लिए डिजिटल फेलोशिप प्लेटफार्म बनाने का प्रस्ताव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नीति आयोग का मानना है कि रिसर्च और पेटेंट के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन मजबूत हो रहा है, लेकिन इन रिसर्च और पेटेंट को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने में अपेक्षा के अनुरूप कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इनोवेशन के आइडियाज आ रहे हैं, प्रोटोटाइप बन रहे हैं, लेकिन वह वैश्विक स्तर के अंतिम उत्पाद में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत में टेक्नोलाजी ट्रांसफर मैकेनिज्म की कमी है और बौद्धिक संपदा के प्रबंधन को लेकर स्पष्टता नहीं है।

गत वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में 1,43,729 पेटेंट फाइल किए गए जो पूर्व के वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक है। जानकारों का कहना है कि 10 प्रतिशत से कम पेटेंट ही अंतिम उत्पाद में तब्दील हो पाते हैं। आयोग का मानना है कि सीमित फंड और विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव की कमी से अधिकतर रिसर्च प्रयोगशाला तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसे में आयोग ने सुझाव दिया है कि पेटेंट और इनोवेशन (नवाचार) को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने के लिए औद्योगिक क्लस्टर में ही रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (आरडीआइ) क्लस्टर बनाए जाने चाहिए। रिसर्च को अंतिम उत्पाद में तब्दील करने में मदद के लिए विज्ञान निधि नामक डिजिटल फेलोशिप प्लेटफार्म भी बनाए जा सकते हैं।

आरएंडडी पर जीडीपी का दो प्रतिशत खर्च करना चाहिए

नीति आयोग ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि रिसर्च और डेवलपमेंट (आरएंडडी) पर भारत को अपनी जीडीपी का दो प्रतिशत खर्च करना चाहिए जबकि अभी यह खर्च जीडीपी का 0.5 प्रतिशत भी नहीं है। अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देश आरएंडडी व इनोवेशन पर अपने जीडीपी का दो प्रतिशत से अधिक खर्च करते हैं। नीति आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि औद्योगिक क्लस्टर में ही आरडीआइ क्लस्टर की स्थापना की जा सकती है। आरडीआइ क्लस्टर में विज्ञान व तकनीक से जुड़े विभिन्न फर्म के साथ सरकारी एजेंसी, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के केंद्र और स्टार्टअप शामिल होंगे। राज्यों में बनने वाले इस प्रकार के आरडीआइ क्लस्टर से सभी केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों व एमएसएमई को भी जुड़ना चाहिए।

सरकारी नीति पर अमल के लिए बनाया जाए संस्थान

आयोग ने इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च और पीएचडी के बाद के रिसर्च को समर्थन देने के लिए विज्ञान निधि नामक एक डिजिटल फेलोशिप प्लेटफार्म स्थापित करने की भी सिफारिश की है। नीति आयोग का मानना है कि आरडीआइ को लेकर सरकार की नीति और उस पर अमल के साथ उसकी निगरानी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फार साइंस पालिसी एंड गवर्नेंस (एनआइएसपीजी) की भी स्थापना होनी चाहिए। इसमें रिसर्च व इनोवेशन से जुड़े सभी डाटा के संग्रह के साथ विश्लेषण, मूल्यांकन करने का काम किया जा सकता है।

राष्ट्रीय फलक

'अमेरिकी कंपनियों ने भारत में 60 अरब डालर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई'

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, वैश्विक कंपनियों को भरोसेमंद ढांचा प्रदान करता है भारत

पीयूष गोयल। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि पिछले छह महीनों में अमेरिकी कंपनियों ने भारत में 60 अरब डालर से ज्यादा के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें एमेजोन और गूगल जैसी कंपनियों द्वारा बड़े डाटा सेंटर निवेश भी शामिल हैं।

अमेरिकन चैंबर आफ कामर्स की वार्षिक लीडरशिप समिट में गोयल ने कहा कि भारत वैश्विक कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद ढांचा प्रदान करता है और पैमाने, प्रतिभा व बाजार के अवसरों को इस तरह से जोड़ता है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भरोसेमंद साझेदार की तलाश में है और भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति सम्मान दिखाया है। साथ ही समय पर उच्च गुणवत्ता वाला काम भी करके दिखाया है। गोयल ने कहा कि भारत के पास कुशल प्रतिभाओं का एक विशाल भंडार है और 1.4 अरब महत्वाकांक्षी भारतीयों की मांग, बढ़ती आय और बढ़ते मध्यम वर्ग के जरिये यह अमेरिकी नवाचार को बड़े पैमाने पर विस्तार प्रदान करता है।

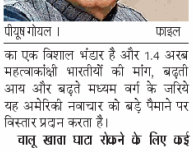

चालू खाता घाटा रोकने के लिए कई उपायों पर विचार : पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मौजूदा स्थिति पर नजर रखे हुए है और बढ़ते चालू खाता घाटे (सीएडी) को नियंत्रित करने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा रहा है। आरबीआइ के दो मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का सीएडी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़कर 13.2 अरब डालर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) हो गया, जो उससे पिछले वर्ष की समान अवधि में 11.3 अरब डालर था।

अगले महीने आएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल : उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार समझौते से जुड़ी शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अगले महीने भारत आ सकता है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या यह प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ आएगा तो गोयल ने इससे इन्कार किया।

अमेरिकियों को ठगने वाले भारत स्थित काल सेंटर का संचालन बंद

न्यूयार्क, प्रेट्र : अमेरिका के अधिकारियों ने भारत स्थित एक काल सेंटर का संचालन बंद कर दिया है, जिसने कथित तौर पर तकनीकी सहायता धोखाधड़ी के माध्यम से सैकड़ों बुजुर्ग अमेरिकियों से लाखों डालर ठग लिए। यह कार्रवाई वर्षों की जांच के बाद की गई, जिसमें पांच "टेलीमार्केटिंग जालसाजों" को गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया।

बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआइ) बोस्टन ने कहा कि जांच के कारण जालसाजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली काल रूटिंग कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया। पोस्ट में कहा गया है कि काल सेंटर धोखाधड़ी ने सैकड़ों बुजुर्गों को निशाना बनाया। इसमें कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में इस फर्जीवाड़े को नजरअंदाज करने की बात स्वीकार की है।

'चेक बाउंस में जुर्माना नहीं भरने पर जेल की सजा रकम के अनुपात में हो'

- हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए सजा घटाई, 40 हजार रुपये का मुआवजा बढ़ाया

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में कहा है कि जुर्माना या मुआवजा अदा नहीं कर पाने पर दी जाने वाली सजा (कैद) की अवधि बकाया रकम के अनुपात में होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की कीमत असंगत नहीं हो सकती और "कास्ट आफ लिबर्टी" का सिद्धांत समानता एवं न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।

जस्टिस अनूप चितकारा ने यह टिप्पणी हरियाणा के गुलाब सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए की। अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए याची की सजा को पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया, जबकि शिकायतकर्ता को दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ा दी। मामला 3.80 लाख रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा था। ट्रायल कोर्ट ने जुलाई 2024 में आरोपित को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की कैद और 5.70 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए सजा कम करने की मांग की। शिकायतकर्ता ने 50 हजार रुपये अतिरिक्त मुआवजे की मांग रखी, जबकि आरोपित ने 40 हजार रुपये बढ़ाने पर सहमति जताई। अदालत ने कहा कि समान परिस्थितियों वाले दोषियों को समान प्रकार की सजा मिले और जेल की अवधि बकाया राशि के अनुरूप हो। अदालत ने सजा को "पहले से भुगती गई अवधि" तक सीमित कर दिया और मुआवजे की राशि 5.70 लाख रुपये से बढ़ाकर 6.10 लाख रुपये कर दी। साथ ही आदेश दिया कि यदि आरोपित किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वीडियोकान के संस्थापक वेणुगोपाल धूत

नई दिल्ली, प्रेट्र: वीडियोकान के संस्थापक वेणुगोपाल धूत राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ग्रुप की दो इकाइयों वीडियोकान इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वीडियोकान आयल वेंचर्स लिमिटेड के लिए अलग-अलग दिवाला कार्यवाही को बरकरार रखा गया है। साथ ही न्यायाधिकरण के एक पूर्व के आदेश को भी रद कर दिया गया, जिसमें दोनों मामलों को साथ जोड़ने का निर्देश दिया गया था।

न्यायाधिकरण ने 14 मई को कहा था कि वीडियोकान इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वीडियोकान आयल वेंचर्स लिमिटेड के कर्जदाताओं ने दोनों कंपनियों की अलग प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कारपोरेट ऋण शोधन प्रक्रियाओं (सीआइआरपी) को स्वतंत्र चलाने की बात कही थी।

रेलवे भर्ती परीक्षा हिंसा मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे बरी

- स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर हुआ था उग्र प्रदर्शन
- इस मामले में राज ठाकरे सहित आठ लोगों को बनाया गया था आरोपित

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख देने वाले करीब 18 साल पुराने रेलवे भर्ती परीक्षा हिंसा मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। गुरुवार को ठाणे के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिजीत कुलकर्णी की अदालत ने पर्याप्त सुबूतों के अभाव में राज ठाकरे समेत सभी जीवित आरोपितों को बरी करने का आदेश सुनाया।

यह मामला 19 अक्टूबर 2008 का है, जब अखिल भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की परीक्षा देने के लिए उत्तर भारत (विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार) से बड़ी संख्या में परीक्षार्थी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचे थे। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर मनसे कार्यकर्ताओं ने कल्याण रेलवे स्टेशन और अन्य केंद्रों पर उग्र प्रदर्शन किया था। आरोप था कि मनसे कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय परीक्षार्थियों के साथ बेरहमी से मारपीट की और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तत्कालीन सरकार ने राज ठाकरे पर कार्यकर्ताओं को उकसाने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज कर उन्हें रत्नागिरी से गिरफ्तार किया था। इस मामले की लंबी सुनवाई पहले कल्याण कोर्ट और बाद में ठाणे रेलवे कोर्ट में चली। बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित और विरोधाभासों से भरा है। बताया कि चार्जशीट या मौखिक साक्ष्यों में ऐसा कोई सुबूत नहीं है जो साबित कर सके कि राज उस दिन घटनास्थल पर मौजूद थे।

लखनऊ में हिंदू युवक से प्रेम करने पर पिता ने की थी 15 साल की बेटी की निर्मम हत्या

- छपरा-गोमती नगर एक्सप्रेस में बक्सा व बैग में मिली थी किशोरी की सिर कटी लाश
- कोच के सीसी कैमरे के जरिये हत्यारे तक पहुंची जीआरपी, बहन-बहनोई भी गिफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ

हिंदू युवक से प्रेम करने पर 15 साल की किशोरी की निर्मम हत्या उसके पिता ने अपनी बहन और बहनोई के साथ मिलकर की थी। घर में ही बांके से शव को छह हिस्सों में काट डाला। फिर सिर को घर से कुछ दूरी पर स्थित तालाब में फेंक दिया, जबकि धड़ के पांच हिस्सों को बक्सा और बैग में पैककर छपरा-गोमती नगर एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी पर रख दिया था। जीआरपी ने हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ हत्यारे पिता, उसकी बहन और बहनोई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की दो बड़ी बेटियों ने हिंदू युवकों से प्रेम विवाह किया है। वह नहीं चाहता था कि छोटी बेटी भी ऐसा करे।

गत 17 मई को जीआरपी ने गोमती नगर स्टेशन (लखनऊ) की वाशिंग लाइन में छपरा-गोमती नगर एक्सप्रेस की एस-1 बोगी में लावारिस बक्सा और बैग से बिना सिर के पांच टुकड़ों में किशोरी की लाश बरामद की थी। जीआरपी ने सीसी कैमरे की फुटेज खंगाली तो कुशीनगर जिले के 44 वर्षीय ई-रिक्शा चालक विग्गन अंसारी तक पहुंची। पूछताछ में विग्गन ने मृतक की पहचान 15 वर्षीय बेटी के रूप में की। बताया कि बेटी हिंदू युवक से प्रेम विवाह करना चाहती थी। इसलिए हत्या की योजना बहनोई मोजिबुल्ला अंसारी और बहन नूरजहां के साथ मिलकर बनाई।

कंकाल बना सिर

तालाब में जाल डालकर जीआरपी ने गुरुवार सुबह एक सिर बरामद किया है। जीआरपी डीएनए जांच से शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। जिस घर में हत्या की गई, उसे सील कर दिया गया है। एक फारेंसिक टीम कुशीनगर जाकर जांच करेगी।

हिंदू युवक से प्रेम विवाह करने वाली दूसरी बेटी भी लापता

ग्रामीणों ने बताया कि हिंदू युवक से प्रेम विवाह से मना करने पर छोटी बेटी ने आत्महत्या का प्रयास किया था। आरोपित विग्गन की बड़ी बेटी खुशबू लापता है। ग्रामीणों ने उसकी भी हत्या का संदेह जताया। दूसरी बेटी नरगिस गांव के ही हिंदू युवक संग विवाह कर बाहर रह रही है।

गहनों का पता लगाने तांत्रिक के पास पहुंचा अधिकारी, हटाने का आदेश

- राजस्थान हाई कोर्ट ने नागौर एसपी को दिया जांच अधिकारी को बदलने का आदेश
- कहा- आपराधिक मामले की जांच किसी तांत्रिक के इशारों पर नहीं चल सकती

जागरण संवाददाता, जोधपुर

राजस्थान हाई कोर्ट ने नागौर जिले से संबंधित गहनों की चोरी के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आपराधिक मामले की जांच तांत्रिक के इशारों पर नहीं चल सकती। जस्टिस मुन्नरी लक्ष्मण की सिंगल बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नागौर एसपी को जांच अधिकारी को बदलने का आदेश दिया।

कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आदेश की प्रति मिलने के 15 दिन के भीतर जांच श्रीबालाजी थाने से हटाकर किसी अन्य थाने के सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊंची रैंक के अधिकारी को सौंपी जाए। जांच अधिकारी पर अनुसंधान के दौरान तांत्रिक की मदद लेने का आरोप है। बता दें कि 80 वर्षीय महिला ने श्रीबालाजी थाने में 8 मार्च 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि सात मार्च की रात को घर से उनके और उनकी बहू के गहने चोरी हो गए। इनमें डेढ़ तोला सोना, 300 तोला चांदी और 24 हजार कैश शामिल था। पुलिस न तो आरोपितों को गिरफ्तार कर पाई और न ही चोरी हुए जेवर बरामद कर सकी।

राजस्थान हाई कोर्ट। फाइल

2026 के शुरुआती चार महीनों (जनवरी से अप्रैल) के भीतर ही बांग्लादेश के 62 जिलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 505 खौफनाक वारदातें दर्ज की गई हैं। मानवाधिकार संगठन 'ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फार बांग्लादेश माइनारिटीज' की ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

ईरान बोला– देश से बाहर नहीं जाएगा यूरेनियम, ट्रंप ने कहा–लेकर रहेंगे

तनातनी बरकरार ▸ सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने यूरेनियम भंडार पर सख्त निर्देश दिए

अमेरिका के नए 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर विचार, पाकिस्तान ने मध्यस्थता तेज की

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौता एक बार फिर मुश्किलों में घिरता दिख रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को किसी भी स्थिति में देश से बाहर नहीं भेजेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि हम किसी भी तरह यूरेनियम हासिल कर लेंगे। हालांकि, हमें इसकी जरूरत नहीं है और संभवतः हम इसे नष्ट कर देंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि समझौता करने के लिए ईरान के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतें 107 डालर पर पहुंच गईं।

इस बीच, ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, बीते 24 घंटों में 31 जहाजों ने जलडमरूमध्य पार किया, जबकि करीब 30 अन्य जहाजों ने गुजरने की अनुमति मांगी है।

मोजतबा खामेनेई। फाइल

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

ईरान वार्ता में मिल रहे सकारात्मक संकेत : रूबियो

आइएएनएस के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को कहा कि ईरान के साथ जारी वार्ता में 'सकारात्मक संकेत' मिल रहे हैं। मियामी में पत्रकारों से बातचीत में रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की प्राथमिकता अब भी समझौते के जरिये समाधान निकालने की है। हालिया संपर्कों में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन ईरान की राजनीतिक व्यवस्था बंटी हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान की तेहरान यात्रा वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। हालांकि समझौता तय मानकर नहीं चला जा सकता।

रायटर की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की ओर से भेजे गए नए 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की समीक्षा के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने निर्देश दिया है कि संवर्धित यूरेनियम किसी भी हालत में विदेशी नियंत्रण में नहीं जाना चाहिए। ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान में इस मुद्दे पर व्यापक सहमति बन चुकी है।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने पुष्टि की कि अमेरिका का नया प्रस्ताव तेहरान को मिल गया है और उसकी समीक्षा की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका को अब भी "गहरे संदेह" की नजर से देखता है, लेकिन बातचीत "सद्भावना" से जारी है।

न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, ईरान के शीर्ष सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं कि संवर्धित यूरेनियम पर नियंत्रण छोड़ना देश की सुरक्षा को कमजोर कर देगा और भविष्य में अमेरिका तथा इजरायल की सैन्य कार्रवाई का खतरा बढ़ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) के अनुमान के अनुसार, ईरान के पास 60 प्रतिशत से अधिक संवर्धित करीब 440 किलो यूरेनियम मौजूद है। 90 प्रतिशत संवर्धन स्तर परमाणु हथियार निर्माण के लिए पर्याप्त माना जाता है।

एएनआइ के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान की ओर से पूरी तरह संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अमेरिका बहुत तेजी से सैन्य कार्रवाई का फैसला कर सकता है। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कब्जा है और ईरान वहां से गुजरनेवाले जहाजों से टोल नहीं वसूल सकता।

ईरान मुद्दे पर ट्रंप–नेतन्याहू में फोन पर तीखी बहस: रिपोर्ट

▸ एक्सियोस का दावा– फोन काल के बाद नेतन्याहू बेहद नाराज थे

▸ ट्रंप चाहते हैं समझौता, नेतन्याहू का इरादा ईरान को और कमजोर करने का

वाशिंगटन, एएनआइः ईरान के साथ जारी तनाव और संभावित शांति समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बातचीत हुई है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच ईरान के साथ आगे की रणनीति को लेकर गंभीर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। हालांकि, व्हाइट हाउस और इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन रिपोर्टों पर अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह बातचीत ऐसे समय हुई जब अमेरिका ईरान के साथ नए कूटनीतिक प्रयासों और संभावित समझौते पर विचार कर रहा है। वहीं इजरायल का रुख अब भी कठोर बना हुआ है और वह ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह कमजोर करने के लिए दोबारा सैन्य कार्रवाई के पक्ष में बताया जा रहा है।

एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि फोन काल के बाद नेतन्याहू बेहद नाराज और परेशान थे। एक सूत्र ने कहा कि बातचीत के बाद नेतन्याहू ने कहा कि उनके 'बाल आग की तरह जल रहे थे', यानी वह बेहद गुस्से और तनाव में थे। सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप अब भी समझौते की संभावना के पक्ष में हैं, हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि बातचीत विफल होने की स्थिति में सैन्य विकल्प खुला रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू ईरान की सैन्य तथा रणनीतिक संरचनाओं के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपनाने के समर्थक हैं।

बेंजामिन नेतन्याहू। फाइल

प्रेट्र के अनुसार, सीएनएन ने भी इजरायली सूत्रों के हवाले से कहा है कि इजरायल सरकार का एक प्रभावशाली धड़ा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने के पक्ष में है। ट्रंप द्वारा बार-बार कूटनीतिक रास्ते को प्राथमिकता दिए जाने से इस धड़े में नाराजगी बढ़ रही है। खबरों के मुताबिक, ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पर यह भी बताया कि मध्यस्थ देश एक 'लेटर आफ इंटेंट' के मसौदे पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमेरिका और ईरान भविष्य में हस्ताक्षर कर सकते हैं।

अमेरिका से समझौता वार्ता में ईरान के कट्टरपंथी जनरल वाहिदी की बढ़ी भूमिका

दुबई, एपी: अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने को लेकर चल रही वार्ता में ईरान के कट्टरपंथी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी की भूमिका तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। ईरान की अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख वाहिदी को अब अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान के कठोर रुख का प्रमुख रणनीतिकार माना जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, वाहिदी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के करीबी माने जाते हैं और युद्ध के बाद ईरानी सत्ता संरचना में उनका प्रभाव तेजी से बढ़ा है। फरवरी में अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद से वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति तय करने में उनकी निर्णायक भूमिका है।

वाशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फार द स्टडी आफ वार के मुताबिक, वाहिदी और उनके करीबी सहयोगियों ने न केवल युद्ध के दौरान ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया पर नियंत्रण मजबूत किया है, बल्कि अमेरिका के साथ वार्ता की दिशा भी वही तय कर रहे हैं। ईरान की रणनीति होर्मुज जलडमरूमध्य पर पकड़ बनाए रखने, तेल-गैस निर्यात बाधित करने और वैश्विक ऊर्जा संकट का दबाव बढ़ाने की रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की यह मांग कि ईरान अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को छोड़े, उसे लेकर भी वाहिदी सख्त रुख अपनाए हुए हैं।

न्यूज गैलरी

पाक के खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले में दो स्कूली बच्चों की मौत

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में गुरुवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर में ड्रोन हमले में दो स्कूली बच्चों की जान चली गई। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डान ने बताया कि यह घटना दोपहर में बाजौर के जिला मुख्यालय खार से 25 किलोमीटर दूर साही थांगी इलाके में हुई। मारे गए बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे जब वे ड्रोन की चपेट में आ गए। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि ड्रोन कहां से लांच किया गया था और हमले के लिए कौन जिम्मेदार था। (आइएएनएस)

ब्रिटेन में हेट मानीटर प्लेटफार्म किया गया लांच

लंदन: ब्रिटेन में हिंदू विरोधी घृणा की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करने में मदद के लिए एक नया प्लेटफार्म लांच किया गया है। एंटी-हिंदू हेट मानीटर (एएचएचएम) को लंदन में इंटरनेशनल सेंटर फार सस्टेनेबिलिटी (आइसीएफएस) में फ्यूचर आफ फेथ डेस्क के तहत एक कार्यशील परियोजना के रूप में वर्णित किया गया है। थिंक टैंक ने कहा कि इस सप्ताह लांच किए गए नए आनलाइन प्लेटफार्म द्वारा एकत्र किए गए डाटा का उपयोग ब्रिटेन होम आफिस, कानून प्रवर्तन, स्थानीय अधिकारियों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए किया जाएगा। आइसीएफएस ने कहा, इस मंच का लक्ष्य हिंदू समुदाय के भीतर एक सामूहिक आवाज का समर्थन करना है। (प्रेट्र)

क्रिकेट कनाडा के अध्यक्ष खोसा के घर पर गोलीबारी

ओटावा: अज्ञात बंदूकधारियों ने कनाडा के क्रिकेट संचालन निकाय के भारतीय मूल के अध्यक्ष के घर पर गोलीबारी की। इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में क्रिकेट कनाडा के अध्यक्ष चुने गए अरविंदर खोसा ने गोलीबारी की पुष्टि की है। स्थानीय समय बुधवार तड़के 4:40 बजे सरे में उनके घर पर गोलियां चलाई गईं। घर के दरवाजे, खिड़कियों और बाहरी हिस्से में पांच गोलियों के छेद दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने कहा है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन माना जा रहा है कि गोलीबारी जबरन वसूली से संबंधित है। (एपी)

कोरियाई युद्ध में '60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस' के योगदान को राजनाथ सिंह ने किया याद

पाजू (दक्षिण कोरिया), एएनआइ : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरियाई युद्ध की 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इम्जिन्गाक पीस पार्क में आयोजित एक मेमोरियल समारोह में भारतीय सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सात दशक पहले युद्ध के दौरान मानवता की सेवा करने वाली भारत की '60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस' के अद्वितीय साहस और बलिदान को याद किया। इस दौरान उन्होंने एक फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। समारोह में दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और स्मारक पट्टिका का अनावरण हुआ। युद्ध में उत्कृष्ट सेवा के लिए कर्नल ए.जी. रंगराज की भतीजी कल्पना प्रसाद को 'कोरियाई युद्ध नायक प्रमाण पत्र' (मई 2026) से सम्मानित किया गया।

▸ युद्ध में उत्कृष्ट सेवा के लिए कर्नल एजी रंगराज की भतीजी कल्पना प्रसाद को 'कोरियाई युद्ध नायक प्रमाण पत्र'

सियोल में गुरुवार को भारतीय युद्ध स्मारक के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र >>

रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा: इससे पहले, सियोल में राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आह्न ग्यू-बैक के बीच व्यापक द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों और सैन्य आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। इस दौरान डिफेंस साइबर, नेशनल डिफेंस कालेज और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

रक्षा मंत्री ने दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली योंग-चुल से भी मुलाकात की, जिसमें 'भारत-कोरिया रक्षा नवाचार त्वरक पारिस्थितिकी तंत्र' (काइंड-एक्स) के रोडमैप पर चर्चा हुई। बाद में, राजनाथ सिंह ने भारत-कोरिया रक्षा उद्योग बिजनेस राउंडटेबल की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने दक्षिण कोरियाई कंपनियों से भारत में उपलब्ध अवसरों के लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।

सिर्फ जन्मजात अमेरिकी के देश में सत्ता संभालने के प्रस्ताव का हो रहा विरोध

वाशिंगटन, प्रेट्र : दक्षिण कैरोलिना से कांग्रेसनल प्रतिनिधि नैन्सी मेस की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। डेमोक्रेट्स ने इसे घृणित और नस्लवाद से प्रेरित करार दिया। दरअसल, प्रस्ताव में नैन्सी ने मांग की है कि अमेरिका में जन्मे लोग ही सत्ता संभालें। इंटरनेट मीडिया पर बुधवार को एक पोस्ट में नैन्सी ने कहा कि उन्होंने संवैधानिक संशोधन के लिए 'लंबे समय से प्रतीक्षित संयुक्त प्रस्ताव' पेश किया है। यह वही मानक है जिसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पहले से ही पूरा करना आवश्यक है।' मेस ने अपने पोस्ट के साथ डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर, प्रमिला जयपाल और श्री थानेदार की तस्वीरें भी पोस्ट कीं। जहां उमर एक सोमाली अमेरिकी है, वहीं जयपाल और थानेदार दोनों भारतीय मूल के हैं। मेस कहा, अमेरिका के कानून लिखने वाले, जजों की पुष्टि करने वाले और देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की एक ही निष्ठा होनी चाहिए, अमेरिका।

भारत ने यूएन में पाकिस्तान के जघन्य कृत्यों को किया बेनकाब

▸ कहा, उसके जघन्य कृत्यों पर आश्चर्य नहीं, जो अपने ही लोगों पर करता है बमबारी

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र: संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा फिर उठाने पर पाकिस्तान को भारत ने कड़ा जवाब दिया और उसके जघन्य कृत्यों को बेनकाब किया। भारत ने पाकिस्तानी सैन्य बलों की सीमा पार हिंसा के कारण अफगान नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाओं को उजागर किया और कहा कि उस देश की आक्रामकता के ऐसे जघन्य कृत्यों पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो अपने ही लोगों पर बमबारी करता है और सुनियोजित तरीके से नरसंहार करता है।

भारत ने बुधवार को चीन की अध्यक्षता वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान यूएन में पाकिस्तानी राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद द्वारा जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर यह कड़ी प्रतिक्रिया दी। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने 'सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा' विषय पर सालाना चर्चा के दौरान कहा, 'यह विडंबना है कि नरसंहार के कृत्यों के अपने लंबे कलंकित इतिहास वाले पाकिस्तान ने उन मुद्दों को हवाला देने के लिए चुना, जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं।' उन्होंने कहा, 'दुनिया यह नहीं भूली है कि इसी वर्ष मार्च में रमजान के महीने में पाकिस्तान ने काबुल के अस्पताल पर बर्बर हवाई हमला किया था।

हरीश पर्वतनेनी।

संयुक्त राष्ट्र में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को दिया कड़ा जवाब

यूक्रेन ने ड्रोन से फिर बनाया रूसी रिफाइनरी को निशाना, लगी आग

800 किमी भीतर ड्रोन भेजकर किया तेल ढांचे पर हमला

कीव, एपी : यूक्रेन ने रूस की एक और रिफाइनरी पर बुधवार-गुरुवार की रात ड्रोन हमला किया। हमले से रिफाइनरी में आग लग गई और उससे उठने वाला काला धुंआ मीलों दूर से दिखाई दे रहा था। यूक्रेन ने रूस में 800 किलोमीटर भीतर ड्रोन भेजकर सिजरान आयल रिफाइनरी पर हमला किया।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की जानकारी देते हुए रूसी रिफाइनरी का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया है। रूस के सामरा क्षेत्र के गवर्नर व्याचेस्लाव फेडोरिश्चेव ने कहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में दो लोग मारे गए हैं लेकिन रिफाइनरी पर हमले का उन्होंने जिक्र नहीं किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के सीमावर्ती बेलगोरोद इलाके में भी कुछ लोग घायल हुए हैं जबकि रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन में एक नागरिक की मौत हुई है और छह घायल हुए हैं।

यूक्रेन के सस्ते ड्रोन बढ़ा रहे रूस की मुश्किल : यूक्रेन के पिछले कुछ दिनों में ड्रोन हमलों की अपनी क्षमता बढ़ाई है। यूक्रेन ने रूस में 1,400 किलोमीटर भीतर जाकर भी हमला किया है। इतना ही नहीं चंद रोज पर पहले यूक्रेन ने रूस की राजधानी मास्को के बाहरी इलाके में भी ड्रोन हमला किया था। रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन ने अपने हथियारों का भी विकास किया है।

मर्ज ने कहा, रूस से वार्ता करे ईयू

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूरोपीय संघ (ईयू) से अनुरोध किया है कि वह यूक्रेन को सशर्त सदस्यता दे और रूस के साथ वार्ता भी करे। ईयू से यूक्रेन का रिश्ता जुड़ने से युद्ध से बर्बाद हुए देश को बेहतर सहायता मिल जाएगी। जबकि रूस से वार्ता से युद्ध रुकने की संभावना बनेगी जो शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विदित हो कि ईयू 27 यूरोपीय देशों का समूह है।

अटलांटिक विमान हादसा मामले में एयरबस और एयर फ्रांस दोषी करार

पेरिस, रायटर: 2009 के अटलांटिक विमान हादसा मामले में पेरिस की एक अपीलीय अदालत ने गुरुवार को एयरबस और एयर फ्रांस को कारपोरेट हत्या का दोषी ठहराया। ट्रायल कोर्ट की ओर से मामले में इन्हें बरी किए जाने के तीन साल बाद यह फैसला आया है। रियो डी जेनेरियो से पेरिस आते समय एयर फ्रांस का यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार 228 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई थी।

एएफ447 पीड़ित संघ के अध्यक्ष डेनियल लैमी ने अदालत के बाहर कहा, 'न्याय पूरी तरह किया गया है।' लैमी ने विमान हादसे में अपने बेटे को खो दिया था। जबकि कुछ मृतकों के रिश्तेदारों ने फैसले को शांतिपूर्वक सुना और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फ्रांस के सबसे भीषण हवाई हादसे में 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया है। हादसे के दो वर्ष विमान के ब्लैक बाक्स पाए गए थे।

2027 से यूएई की नई तेल पाइपलाइन से फुजैराह बंदरगाह तक होगी तेल आपूर्ति

▸ यूएई प्रशासन का दावा, पाइपलाइन परियोजना का 50 प्रतिशत काम पूरा

▸ नई पाइपलाइन से होर्मुज पर निर्भरता घटेगी, तेल निर्यात क्षमता दोगुनी करने की तैयारी

प्रतीकात्मक

दुबई, रायटर : ईरान युद्ध के कारण फारस की खाड़ी में होर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ते तनाव ने खाड़ी देशों की चिंता बढ़ा दी है। ईरान की ओर से समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और हमलों के चलते क्षेत्र से तेल निर्यात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने फुजैराह बंदरगाह तक नई वेस्ट-ईस्ट पाइपलाइन परियोजना को तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि तेल आपूर्ति के लिए होर्मुज पर निर्भरता कम की जा सके।

यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडनोक के प्रमुख सुल्तान अल जबेर ने कहा कि नई पाइपलाइन का लगभग 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसे 2027 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। उनका कहना है कि युद्ध समाप्त होने की स्थिति में भी वैश्विक तेल आपूर्ति को युद्ध-पूर्व स्तर पर लौटने में कम से कम चार महीने लग सकते हैं, जबकि पूरी बहाली 2027 की पहली छमाही तक ही संभव हो पाएगी। यूएई की मौजूदा अबू धाबी क्रूड आयल पाइपलाइन (एडीसीओपी) प्रतिदिन 18 लाख बैरल तेल ढोने की क्षमता रखती है। यह पाइपलाइन ओमान की खाड़ी के रास्ते तेल निर्यात सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नई पाइपलाइन तैयार होने के बाद यूएई की वैकल्पिक निर्यात क्षमता और मजबूत होकर दोगुनी हो सकती है।

सुल्तान अल जबेर ने चेतावनी दी कि ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की स्थिति चिंताजनक रूप से कमजोर बनी हुई है।

उनके अनुसार, मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर करीब 400 अरब डालर का वार्षिक निवेश केवल प्राकृतिक उत्पादन गिरावट की भरपाई के लिए ही पर्याप्त है, जबकि अतिरिक्त कच्चे तेल उत्पादन क्षमता को मौजूदा 30 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर करीब 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक ले जाने की जरूरत है।

वैश्विक राजनीति की असली धुरी बनता जा रहा है चीन

▸ ट्रंप और पुतिन की मेजबानी कर चीन ने दिया बड़ा संदेश

▸ चीन ने दिखाया असली खेल, अब दुनिया उसी के इर्द-गिर्द घूमेगी

सिडनी, द कन्वर्सेशन : वैश्विक राजनीति में इस हफ्ते जो तस्वीर बीजिंग से निकली, उसने साफ कर दिया कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। कभी पूरी दुनिया को अपनी अंगुलियों पर नचाने वाला अमेरिका अब चीन के सामने उतना मजबूत नहीं दिख रहा, जबकि रूस भी सबसे भरोसेमंद साथी की तरह बीजिंग के दरवाजे पर खड़ा नजर आया। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया तो दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ घंटों बातचीत कर दुनिया को यह अहसास दिला दिया कि अब वैश्विक राजनीति की असली धुरी बीजिंग बनता जा रहा है।

ट्रंप की यह यात्रा साल 2017 के बाद पहली बीजिंग यात्रा थी। दूसरी तरफ पुतिन की यह चीन की 25वीं आधिकारिक यात्रा थी।

ट्रंप आए, लेकिन खाली हाथ लौटे : बीजिंग में ट्रंप और शी चिनफिंग की मुलाकात के दौरान हर तस्वीर और हर इशारे ने बहुत कुछ कह दिया। शी चिनफिंग का व्यवहार ऐसा था मानो वह दुनिया को बता रहे हों कि अब अमेरिका चीन को दबाने की ताकत खोता जा रहा है। मुलाकात के बाद ट्रंप को न कोई बड़ा समझौता मिला, न संयुक्त बयान और न ही कोई बड़ी सफलता।

बीजिंग में 15 मई को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रायटर

सबसे चौंकाने वाला पल तब आया, जब शी चिनफिंग ने थ्यूसीडाइड्स ट्रैप का जिक्र किया। यह वह सिद्धांत है जिसमें कहा जाता है कि जब कोई नई ताकत तेजी से उभरती है, तो पुरानी ताकत उससे डरकर टकराव की राह पकड़ लेती है।

शी ने सीधे सवाल किया कि क्या चीन और अमेरिका इस टकराव से बचकर नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं? चीन ने ट्रंप की यात्रा के जरिये दुनिया को यह दिखा दिया कि अब वह अमेरिका को अपने लिए सबसे अहम देश नहीं मानता।

अब दुनिया की राजनीति बीजिंग से होकर गुजरेगी : कभी दुनिया की राजनीति अमेरिका के इर्द-गिर्द घूमती थी। वाशिंगटन तय करता था कि किस देश से दोस्ती करनी है और किसे अलग-थलग करना है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है।

ट्रंप और पुतिन दोनों को बीजिंग आना पड़ा। दोनों को चीन की जरूरत महसूस हुई। यही सबसे बड़ा संकेत है कि दुनिया की नई ताकत कौन बन रही है। चीन अब अमेरिका और रूस को आपस में लड़ाने की राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि खुद को उस केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, जहां से होकर बड़ी ताकतों की राजनीति गुजरती है।

पुतिन के लिए चीन बना सबसे बड़ा सहारा

जहां ट्रंप को ज्यादा सफलता नहीं मिली, वहीं पुतिन अपने पुराने और अच्छे दोस्त शी चिनफिंग के साथ मजबूत रिश्तों का प्रदर्शन करते नजर आए। दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और ऊर्जा समेत करीब 20 समझौते हुए। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के लिए चीन सबसे बड़ा आर्थिक सहारा बन चुका है। बीजिंग में एक निजी मुलाकात के दौरान ट्रंप ने जब पूछा कि क्या शी दूसरे नेताओं को भी अपने बेहद गोपनीय झोंगनानहाई परिसर में बुलाते हैं, तो शी ने कहा कि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन पुतिन यहां आ चुके हैं। हालांकि चीन ने पुतिन की हर मांग पूरी नहीं की। रूस चाहता था कि पावर आफ साइबेरिया-2 गैस पाइपलाइन परियोजना पर अंतिम समझौता हो जाए, ताकि रूसी गैस सीधे चीन पहुंच सके। दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

बीजिंग में 20 मई को पुतिन और शी चिनफिंग। एपी

एक ही दिन में तीन भारतीयों समेत 274 पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़े

▸ रिकार्ड बनाने वाली इस टीम में शामिल थे तुलसी रेड्डी, संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल

काठमांडू, प्रेट्र : तीन भारतीयों सहित 274 पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में चढ़ाई कर विश्व रिकार्ड बनाया है। सभी 274 पर्वतारोही बुधवार को 8,848.86 मीटर की चोटी पर पहुंच गए। कीर्तिमान बनाने वाली इस टीम में शामिल तीन भारतीय पर्वतारोही तुलसी रेड्डी पालपुनूरी, संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा पर्वतारोहियों के माउंट एवरेस्ट पर नेपाल की तरफ से चढ़ाई करने का रिकार्ड 2019 में बना था, जब 223 पर्वतारोही शिखर पर पहुंचे थे।

नेपाल में अभियान संचालक संघ के महासचिव ऋषि राम भंडारी ने बताया कि 150 नेपाली शेरपाओं सहित ये पर्वतारोही एक ही दिन में शिखर पर पहुंचे। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने भी नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपना ही रिकार्ड तोड़ दिया है, वहीं नेपाल की ल्हाकपा शेरपा रिकार्ड 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनीं।

बीएसएफ की महिला टीम ने फतह किया माउंट एवरेस्ट, गाया वंदे मातरम्: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की महिला पर्वतारोहियों की टीम ने गुरुवार को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। बीएसएफ की हीरक जयंती और राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शिखर पर पहुंचने के बाद टीम ने राष्ट्र को समर्पित 'वंदे मातरम्' गाकर गौरव का अहसास कराया। बीएसएफ के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी महिला पर्वतारोहण दल ने एवरेस्ट फतह की है। बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि इस टीम में लद्दाख की कांस्टेबल कौसर फातिमा, बंगाल की मुनमुन घोष, उत्तराखंड की रबेका सिंह और कारगिल के त्सेरिंग चोरोल शामिल थीं।

दैनिक जागरण धूम धड़ाका आइपीएल 19 www.jagran.com शुक्रवार 22 मई, 2026

बल्लेबाज	रन
साई सुदर्शन	638
शुभमन गिल	616
वैभव सूर्यवंशी	579

गेंदबाज	विकेट
भुवनेश्वर कुमार	24
कैगिसो रबादा	24
अंशुल कंबोज	21

सबसे बड़ी हार के साथ बाहर हुई चेन्नई सुपरकिंग्स

मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने सीएसके को 89 रन से हराया, बल्लेबाजों के बाद गुजरात के गेंदबाजों ने बरपाया कहर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : बल्लेबाजी में साई सुदर्शन (84), शुभमन गिल (64) और जोस बटलर (57*) की तिकड़ी के बाद गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज (3/26), कैगिसो रबादा (3/32) और राशिद खान (3/18) की तिकड़ी ने चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) पर ऐसा कहर बरपाया कि उसे आइपीएल इतिहास में अपनी सबसे बड़ी हार मिली। अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में पांच बार की चैंपियन टीम 13.4 ओवर में 140 रन पर आलआउट हो गई और गुजरात ने 89 रन के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की। इस हार के साथ ही सीएसके की प्लेआफ में पहुंचने की उम्मीदें भी धूमिल हो गईं। इससे पहले, चेन्नई की रन अंतर से सबसे बड़ी हार 2013 में मिली थी, तब उसे मुंबई इंडियंस ने 60 रन से हराया था।

चेन्नई सुपरकिंग्स की शुरुआत इतनी खराब रही कि टीम पूरे मुकाबले में कभी लय हासिल ही नहीं कर सकी। सिराज, रबादा और राशिद ने चेन्नई को पूरी तरह दबाव में रखा। अंगुली की चोट के बावजूद खेलने उतरे संजू सैमसन पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जिससे चेन्नई की मुश्किलें शुरुआत में ही बढ़ गईं। इसके बाद कप्तान रुतुराज गायकवाड़ खुद को तीसरे नंबर पर लेकर आए, ताकि पारी को संभाला जा सके, लेकिन यह रणनीति भी सफल नहीं रही। सिराज ने नई गेंद से कहर बरपाते हुए शुरुआती दो ओवरों में ही तीन विकेट झटक लिए। पावरप्ले के भीतर ही मैट शार्ट के रूप में चौथा विकेट गिरने तक चेन्नई मुकाबले से काफी पीछे हो चुकी थी। ऐसे मुश्किल समय में शिवम दुबे ने केवल 17 गेंदों में 47 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए गुजरात के गेंदबाजों पर कुछ देर दबाव बनाया। एक समय ऐसा लगा कि वह मैच को रोचक बना सकते हैं, लेकिन राशिद खान की गेंद पर शुभमन ने शिवम का अद्भुत कैच लपका, इसके साथ ही चेन्नई की बची खुची उम्मीदें समाप्त हो गईं। टीम के आखिरी चार विकेट सिर्फ चार रन के भीतर गिर गए।

शिवम दुबे के विकेट पर जश्न मनाते शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ● प्रेट्र

आइपीएल में चेन्नई की सबसे बड़ी हार

रन	बनाम	स्थान	साल
89	गुजरात	अहमदाबाद	2026
60	मुंबई	मुंबई	2013
54	पंजाब	मुंबई	2022
50	आरसीबी	चेन्नई	2025
46	मुंबई	चेन्नई	2019

7 वीं शतकीय साझेदारी की गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने, यह आइपीएल में सर्वाधिक शतकीय साझेदारी हैं

स्कोर बोर्ड

टास: सीएसके (गेंदबाजी) परिणाम: गुजरात टाइटंस 89 रन से जीता

गुजरात टाइटंस: 229/4 (20 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
सुदर्शन का. शार्ट बो. कंबोज	84	53	7/4
शुभमन का. शिवम बो. जानसन	64	37	7/3
बटलर अविजित	57	27	5/4
तेवतिया रन आउट	0	1	0/0
वाशिंगटन का. उर्विल बो. मुकेश	7	3	0/1

अतिरिक्त : 17 (लेबा : 3, नोबा : 1, वा: 13)

विकेटपतन : 1-125 (शुभमन, 12.2), 2-207 (सुदर्शन, 18.2), 3-207 (तेवतिया, 18.3), 4-229 (वाशिंगटन, 19.6) गेंदबाजी : मुकेश 4-0-36-1, जानसन 4-0-47-1, गुरजपनीत 4-0-31-0, कंबोज 4-0-56-1, नूर 3-0-41-0, शिवम 1-0-15-0

चेन्नई सुपर किंग्स : 140 (13.4 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
सैमसन का. बटलर बो. सिराज	0	1	0/0
शार्ट का. प्रसिद्ध बो. रबादा	24	14	3/1
रुतुराज बो. सिराज	16	7	1/2
उर्विल का. प्रसिद्ध बो. सिराज	0	2	0/0
कार्तिक रन आउट	19	15	3/0
ब्रेविस का. होल्डर बो. राशिद	8	10	0/0
शिवम का. शुभमन बो. राशिद	47	17	4/4
कंबोज का. होल्डर बो. राशिद	19	8	1/2
नूर का. एंड बो. रबादा	1	5	0/0
मुकेश अविजित	2	2	0/0
जानसन का. बटलर बो. रबादा	0	1	0/0

अतिरिक्त : 4 (वा: 4)

विकेटपतन : 1-0 (सैमसन, 0.1), 2-29 (रुतुराज, 2.2), 3-29 (उर्विल, 2.4), 4-51 (शार्ट, 5.1), 5-63 (कार्तिक, 6.6), 6-116 (शिवम, 10.3), 7-136 (कंबोज, 12.1), 8-138 (ब्रेविस, 12.4), 9-140 (नूर 13.3) गेंदबाजी : सिराज 3-0-26-3, रबादा 3.4-0-32-3, अरशद 2-0-24-0, होल्डर 2-0-27-0, राशिद 2-0-18-3, प्रसिद्ध 1-0-13-0

अंक तालिका		मैच	जीत	हार	रद	नेट रन रेट	अंक
1	आरसीबी (Q)	13	9	4	0	+1.065	18
2	गुजरात (Q)	14	9	5	0	+0.695	18
3	हैदराबाद (Q)	13	8	5	0	+0.350	16
4	राजस्थान	13	7	6	0	+0.083	14
5	पंजाब	13	6	6	1	+0.227	13
6	कोलकाता	13	6	6	1	+0.011	13
7	चेन्नई (E)	14	6	8	0	-0.345	12
8	दिल्ली	13	6	7	0	-0.871	12
9	मुंबई (E)	13	4	9	0	-0.510	8
10	लखनऊ (E)	13	4	9	0	-0.702	8

शीर्षक्रम के आगे बेबस चेन्नई के गेंदबाज : गुजरात के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर अधिकांश रन बनाकर टीम के लिए मजबूत नींव तैयार की। गिल ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया, जबकि साई सुदर्शन ने शुरुआत में संयम दिखाया। पावरप्ले खत्म होते ही दोनों बल्लेबाजों ने गियर बदल दिया और मैदान के चारों ओर आकर्षक शाट्स खेलने शुरू कर दिए। दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए और पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी कर डाली। यह आइपीएल इतिहास में गिल और सुदर्शन की सातवीं शतकीय साझेदारी रही, जिससे उन्होंने डेविड वार्नर-शिखर धवन और ट्रेविस हेड-अभिषेक शर्मा की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया। पावरप्ले में गुजरात ने बिना विकेट खोए 62 रन बना लिए थे। इसके बाद जब चेन्नई ने स्पिनर नूर अहमद को गेंदबाजी पर लगाया तो गिल ने उन्हें भी नहीं बख्शा और लगातार दो छक्के जड़ दिए। 10 ओवर में गुजरात का स्कोर बिना विकेट के 111 रन पहुंच चुका था। गिल के आउट होने के बाद भी गुजरात की रफ्तार धीमी नहीं हुई। साई सुदर्शन और जोस बटलर ने मोर्चा संभालते हुए चेन्नई के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। पारी के अंतिम ओवरों में सुदर्शन ने अंशुल कंबोज की लो फुलटास गेंद पर पाइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर दर्शकों का मनोरंजन किया। बटलर भी पूरी लय में नजर आए।

शीर्ष स्थान पर लगीं रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु की निगाहें

इशान किशन

विराट कोहली

सनराइजर्स और आरसीबी के बीच हैदराबाद में आज होगी रोमांचक भिड़ंत

हैदराबाद, प्रेट्र: गत चैंपियन रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जब शुक्रवार को अपने आखिरी आइपीएल लीग मैच में आमने-सामने होंगी तो दोनों की कोशिश शीर्ष दो में जगह बनाने की होगी। आरसीबी अभी अंक तालिका में 18 अंक लेकर शीर्ष पर है और 10 टीम में उसका नेट रन रेट 1.065 सबसे अच्छा है। शुक्रवार को जीत उसे पहला स्थान और फाइनल में पहुंचने के दो मौके दिला देगी। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद 13 मैच में 16 अंक से तीसरे स्थान पर है और गुजरात टाइटंस के बराबर है, लेकिन नेट रन रेट के मामले में पीछे है। सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट 0.350 है जबकि गुजरात टाइटन्स का 0.400 है। शीर्ष दो में जगह बनाने के लिए उसे आरसीबी को बड़े अंतर से हराना होगा और उम्मीद करनी होगी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम गुजरात टाइटंस को हरा दे।

आरसीबी ने फिर किया शानदार प्रदर्शन: कप्तान रजत पाटीदार की अगुआई में आरसीबी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। विस्फोटक बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी के मेल से आरसीबी ने लगातार दूसरे सत्र में खुद को खिताब के दावेदार के तौर पर साबित किया है। दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने शीर्ष क्रम में अपनी निरंतरता को नए सिरे से परिभाषित करना जारी रखा है और 13 मैच में 542 रन बनाए हैं। वहीं, देवदत्त पडिक्कल का सत्र भी अच्छा रहा है। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जोड़ी ने भी आरसीबी की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। भुवनेश्वर इस सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक रहे हैं और नयी गेंद से लगातार कमाल दिखाते रहे हैं। वहीं, हेजलवुड ने अहम मौकों पर असरदार स्पैल डाले हैं। कृणाल पांड्या ने भी अपने हरफनमौला प्रदर्शन से प्रभावित किया है और विविधता भरी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया है। लेग-स्पिनर सुयश शर्मा और आलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने भी योगदान दिया है। आरसीबी की टीम इस सत्र में उतार-चढ़ाव देखने वाली सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध प्रबल दावेदार के तौर पर मैदान में उतरेगी।

खेल डायरी

किरण मोरे की निगरानी में ट्रायल्स का समापन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : 20 और 21 मई को ट्राइडेंट क्रिकेट अकादमी की ओर से हाई टेक वर्ल्ड स्कूल गाजियाबाद में बियांड रीच प्रीमियर लीग (बीआरपीएल) ने सफलतापूर्वक अपने ट्रायल्स का समापन किया। ट्रायल्स में दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों से आए हजारों उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दो दिनों तक चले बीआरपीएल के इन ट्रायल्स पर पूर्व भारतीय विकेटकीपर और बीआरपीएल चयन समिति के प्रमुख किरन मोरे ने अपनी निगाहें बना कर रखीं और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बारीकी से आकलन किया। बीआरपीएल का उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील शर्मा ने कहा कि दिल्ली व आसपास से आए खिलाड़ियों का जुनून देखना प्रेरणादायक रहा।

ट्रायल्स के दौरान किरण मोरे

एशियन लीजेंड्स लीग का आगाज दो जून से

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: एशियन लीजेंड्स लीग के दूसरे सीजन का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट दो जून 2026 से केन्या के नैरोबी स्थित प्रसिद्ध जिमखाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले सीजन को मिली शानदार सफलता को देखते हुए लीग इस बार और भी बड़े स्तर पर वापसी करने जा रही है। 20 ओवर के प्रारूप में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 19 हाई वोल्टेज मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला छह जून को इंडियन रायल्स और पाकिस्तान पैंथर्स के बीच खेला जाएगा। एशियन लीजेंड्स लीग सीजन-2 में इंडियन रायल्स, पाकिस्तान पैंथर्स, श्रीलंकन लायंस, अफगानिस्तान पठांस, बांग्लादेश टाइगर्स और रेस्ट आफ एशियन स्टार्स जैसी फ्रेंचाइजी टीमें शामिल होंगी।

अनुकूल राय को भारत-ए टीम में मिली जगह

नई दिल्ली, प्रेट्र : हरफनमौला अनुकूल राय को गुरुवार को श्रीलंका में होने वाली आगामी त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत-ए टीम में चुना गया जो सीनियर टेस्ट और वनडे टीम में चुने गए हर्ष दुबे की जगह लेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज अनुकूल घरेलू क्रिकेट में झारखंड के लिए खेलते हैं और आइपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा हैं। बीसीसीआइ ने कहा कि पुरुष चयन समिति ने आगामी त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत-ए टीम में अनुकूल को चुना है। वह हर्ष दुबे की जगह लेंगे जो भारतीय सीनियर टीम में चुने गए हैं।

अश्मिता चालिहा क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

कुआलालंपुर, प्रेट्र: अश्मिता चालिहा मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में गुरुवार को महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जबकि भारत के बाकी खिलाड़ी हारकर बाहर हो गए। अश्मिता ने मलेशिश की गोह जिन वेइ को 21-13, 21-16 से हराया। अब उनका सामना आठवीं वरीयता प्राप्त डेनमार्क की लाइन होजमार्क जाएर्सफेल्ट से होगा, जिन्होंने भारत की मालविका बंसोड़ को करीब एक घंटे तक चले मुकाबले में 21-16, 8-21, 15-21 से हराया। अन्य मुकाबले में देविका सिहाग को चीन की चेन युफेइ ने 21-16, 21-13 से हराया। मिक्स्ड डबल्स में सात्विक और राधिका शर्मा भी अमेरिका के प्रेसले स्मिथ और जेनी गेइ से 12-21, 25-27 से हार गए।

डायमंड लीग से बढ़ा आत्मविश्वास, अब लक्ष्य ग्लास्गो में पदक : पारुल

अभिषेक त्रिपाठी ● जागरण

नई दिल्ली : भारत की लंबी दूरी की धाविका पारुल चौधरी अब केवल एशियाई स्तर की खिलाड़ी नहीं रह गई हैं। पिछले एक साल में उन्होंने डायमंड लीग जैसी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में नियमित भाग लेकर खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया है। पारुल का मानना है कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा है और इससे उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है।

मेरठ की 31 वर्षीय एथलीट 2022 एशियाई खेलों में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण और 3000 मीटर स्टीपलचेज (बाधा दौड़) में रजत पदक जीत चुकी हैं। वहीं पिछले साल गुमी में हुई एशियाई चैंपियनशिप में पारुल ने दोनों स्पर्धाओं में रजत पदक जीता था। पारुल का लक्ष्य अब इस साल जुलाई में होने वाले ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पदक जीतना है।

पारुल चौधरी ● फाइल फोटो

पारुल ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में कहा कि पहले भारतीय एथलीटों को विदेशों में खेलने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह 2016 से राष्ट्रीय कैंप का हिस्सा थीं, लेकिन उन्हें पहली बार 2022 में विदेश में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला।

भारत की लंबी दूरी की धाविका पारुल चौधरी ने कहा, पहले विदेश में खेलने के मौके कम थे, अब हालात बदल रहे

अब युवा खिलाड़ियों को लगातार अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर मिल रहा है, जिसका फायदा भारतीय एथलेटिक्स को मिल रहा है। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड में अब तक स्प्रिंट और फील्ड इवेंट के खिलाड़ियों को ज्यादा पहचान मिली है, लेकिन पारुल ने लंबी दूरी की दौड़ में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार खेलने से खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन को समझने और सुधारने का मौका मिलता है। लंबी दूरी की दौड़ के अंतिम चरण को सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। पारुल के अनुसार अंतिम एक किलोमीटर में खुद को मजबूत बनाए रखना बेहद अहम होता है और इसके लिए कोच विशेष ट्रेनिंग और रणनीति तैयार करते हैं।

पारुल ने बताया कि बेंगलुरु में ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स साइंस, रिकवरी मानिटरिंग और फिटनेस से जुड़ी सभी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे प्रदर्शन में लगातार सुधार हो रहा है। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों की क्वालीफाइंग टाइमिंग की बराबरी करने वाली पारुल ने कहा कि अगर उन्हें क्वालिफाई करने का मौका मिलता है तो उनका लक्ष्य वहां भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करना होगा। फिलहाल उनका पूरा फोकस निरंतर सुधार और बड़े मंच पर देश के लिए पदक जीतने पर है।

अलकराज की अनुपस्थिति में नोवाक के पास मौका : सानिया

शेखर झा ● जागरण

नई दिल्ली : साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 24 मई से शुरू होने जा रहा है। दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ियों के बीच इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस बार कार्लोस अलकराज पुरुष सिंगल्स में नहीं खेलेंगे और भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का कहना है कि अलकराज के नहीं होने पर नोवाक जोकोविक के पास खिताब जीतने का अच्छा मौका है।

सानिया ने जोकोविक की जीत की संभावनाओं पर सानिया ने कहा कि कार्लोस अलकराज की गैरमौजूदगी से उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभी वह ज्यादातर हार सिर्फ जानिक सिनर और अलकराज से ही खाते हैं। 38-39 साल की उम्र में भी उनका शीर्ष स्तर पर बने रहना अविश्वसनीय है। सिनर इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, लेकिन नोवाक अब भी शीर्ष तीन खिलाड़ियों में हैं। उन्होंने हमेशा लोगों, उम्र और सीमाओं को गलत साबित किया है। उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सानिया मिर्जा ● एक्स

पूर्व टेनिस खिलाड़ी ने कहा, क्ले कोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों के लिए खेलना बड़ी चुनौती

तीन बार की डबल्स ग्रैंडस्लैम चैंपियन सानिया मिर्जा ने फ्रेंच ओपन में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौतियों को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि क्ले कोर्ट पर हमारा खेल हार्ड कोर्ट या ग्रास कोर्ट जितना मजबूत नहीं है। इसलिए यह मुश्किल जरूर होता है। क्ले कोर्ट पर ज्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि, युकी भांबरी जैसे खिलाड़ी बहुत अच्छी रिटर्न करते हैं। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह उनकी पसंदीदा सतह है या नहीं। कुल मिलाकर, क्ले कोर्ट पर खेलना काफी चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा सानिया ने क्वालीफायर में भारतीय खिलाड़ी करमन कौर थांडी की वापसी को सकारात्मक संकेत बताया। उन्होंने कहा कि करमन ने अपनी प्रोटेक्टेड रैंकिंग के जरिए वापसी की है, जो इस बात का प्रमाण है कि चोट लगने से पहले वह अच्छे स्तर पर खेल रही थीं। सानिया ने कहा कि लगभग दो साल बाद कोर्ट पर लौटने वाले खिलाड़ी का तुरंत आंकलन करना सही नहीं होगा। सानिया ने कहा कि इंजरी से वापसी में मानसिक मजबूती अहम होती है, क्योंकि खिलाड़ी के मन में फिटनेस, प्रदर्शन, दोबारा चोट लगने जैसे कई सवाल चलते रहते हैं।

फ्रेंच ओपन 2026 का प्रसारण भारत में 24 मई से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी कानून में संशोधन की तैयारी : मांडविया

नई दिल्ली, प्रेट्र : खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को कहा कि प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति और वितरण को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी कानून में बदलाव किया जाएगा और ऐसे पदार्थों की खिलाड़ियों को आपूर्ति करने वालों को पांच साल तक जेल का सुझाव रखा गया है। जनता से सुझावों के लिए ये संशोधन खेल मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए हैं। इनके अनुसार, खिलाड़ी को डोपिंग के उद्देश्य से या उसके संबंध में कोई प्रतिबंधित पदार्थ देता है तो उसे पांच साल तक कारावास या दो लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। मांडविया ने कहा कि यह संशोधित विधेयक संसद के अगले सत्र में लाया जाएगा।

खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति करने वालों को पांच साल की सजा का सुझाव

खेल मंत्री ने कहा, डोपिंग अब सिर्फ खेलों से जुड़ा एक उल्लंघन नहीं है बल्कि यह खिलाड़ियों का शोषण करने वाला एक संगठित इकोसिस्टम बन चुका है। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों की सुरक्षा करना और डोपिंग से लाभ कमाने वाले आपराधिक नेटवर्क को समाप्त करना है। उन्होंने प्रस्तावित ढांचे के बारे में बताया कि सिर्फ डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन या पाजीटिव टेस्ट के आधार पर खिलाड़ी को अपराधी नहीं ठहराया जाएगा।

ईस्ट बंगाल बना चैंपियन, 22 साल बाद जीती ट्राफी

फुटबाल डायरी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : भारतीय फुटबाल के इतिहास में ईस्ट बंगाल ने नया अध्याय जोड़ दिया। लाल-पीली ब्रिगेड ने इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) का खिताब जीतकर 22 साल का खिताबी सूखा खत्म कर दिया। अपने अंतिम मुकाबले में ईस्ट बंगाल इंटर काशी को 2-1 गोल से हराकर चैंपियन बना। शुरुआत ईस्ट बंगाल के लिए अच्छी नहीं रही और इंटर काशी ने पहले बढ़त बना ली। इसके बाद ईस्ट बंगाल ने शानदार वापसी करते हुए दो गोल दागे और मैच अपने नाम कर लिया। यूसुफ एजेज्जारी और मोहम्मद राशिद ने टीम के लिए गोल किए।

इस ऐतिहासिक जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने दो दशक से अधिक समय से चले आ रहे ट्राफी के सूखे को समाप्त कर दिया। क्लब के समर्थकों के लिए यह पल बेहद भावुक और गर्व से भरा रहा। जीत के बाद कोलकाता समेत देशभर में ईस्ट बंगाल समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। पूरे सत्र में ईस्ट बंगाल ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने दबाव वाले मुकाबलों में संयम बनाए रखा और आखिरकार अंतिम मैच में खिताब अपने नाम कर लिया। आइएसएल इतिहास में पहली बार लीग चरण समाप्त होने के बाद अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम को ट्राफी दी गई।

विजेता ट्राफी के साथ जश्न मनाते ईस्ट बंगाल के खिलाड़ी ● आइएएनएस

एस्टन विला ने जीता यूरोपा लीग का खिताब

इस्तांबुल, एपी: एस्टन विला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को फ्रीबर्ग को 3-0 से हराकर यूरोपा लीग खिताब जीत लिया। इस खिताब के साथ विला ने 30 साल से चले आ रहे ट्राफी के सूखे को समाप्त किया। विला के समर्थक इंग्लैंड के भावी किंग प्रिंस विलियम ने मैच खत्म होने की सीटी बजते ही जोरदार जश्न मनाया। 1996 के इंग्लिश लीग कप के बाद यह पहला मौका था, जब एस्टन विला ने कोई बड़ा खिताब जीता। विला ने 1982 में यूरोपा कप जीता था। इस तरह ट्राफी 44 साल बाद मिली है। पहले हाफ में यूरी टिलेमैंस और एमी बुएंडिया के गोल ने एस्टन विला दबदबा बनाया। मार्गन रोजर्स ने एस्टन विला के लिए तीसरा गोल किया।

जर्मन गोलकीपर मैनुअल संन्यास से लौटे, खेलेंगे विश्व कप

फीफा वर्ल्ड कप 21 दिन शेष

बर्लिन, एपी: अनुभवी गोलकीपर मैनुअल नुएर ने कोच यूलियन नेगल्समैन के कहने पर फुटबाल से संन्यास का फैसला बदलकर 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शुरू होने जा रहे फुटबाल विश्व कप के लिए जर्मनी की टीम में वापसी की है। 40 वर्ष के नुएर ने 2024 यूरो चैंपियनशिप के बाद फुटबाल से विदा ली थी। उन्हें अब विश्व कप के लिए जर्मनी की 26 सदस्यीय टीम में चुना गया है। नूयेर ने जर्मनी के लिए 124 मैच खेले हैं और उनका आखिरी मैच यूरो 2024 क्वार्टर फाइनल था, जिसमें जर्मनी को स्पेन ने अतिरिक्त समय में 2-1 से हराया था। जर्मन टीम 31 मई को फिनलैंड के विरुद्ध और छह जून को अमेरिका के विरुद्ध अभ्यास मैच खेलेगी। जर्मनी की टीम में मैनुअल नुएर के अलावा ओलिवर बाउमैन, अलेक्जेंडर नुबेल भी गोलकीपर के रूप में शामिल किए गए हैं।

मैनुअल नुएर ● फाइल फोटो, एएफपी

विश्व कप से पहले अमेरिकी होटल उद्योग को बड़ा झटका

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: फीफा विश्व कप में सबसे अधिक मैचों की मेजबानी करने जा रहे अमेरिका की होटल उद्योग को टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही बड़ा झटका लगा है। अमेरिकन होटल एंड लाजिंग एसोसिएशन (एएचएलए) की ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि अमेरिका के लगभग हर मेजबान शहर में विश्व कप को लेकर प्रशंसकों की होटलों की बुकिंग उम्मीद से बेहद कम है। यह रिपोर्ट फीफा के उस दावे से मेल नहीं खा रही है, जिसमें कहा गया था कि इस विश्व कप के लिए 50 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री की जा चुकी है। ऐसे में फीफा पर फर्जी डिमांड पैदा करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। एएचएलए का कहना है कि फीफा ने अपने उपयोग के लिए बहुत अधिक कमरे ब्लाक (आरक्षित) कर लिए, जिससे बाजार में एक फर्जी डिमांड पैदा हो गई। बाद में जब फीफा ने बड़ी संख्या में इन कमरों को रद्द किया, तो होटल खाली रह गए और अब वहां कोई बुकिंग नहीं मिल रही है। हालांकि, फीफा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि इतने बड़े आयोजन के लिए भारी बुकिंग सामान्य प्रक्रिया थी और अब तय समय सीमा से पहले ही बुकिंग को रद्द कर कमरों को रिलीज कर दिया गया है। एएचएलए अमेरिका का सबसे बड़ा होटल संघ है। उसका मानना है कि कम बुकिंग का कारण मैचों के टिकटों की भारी कीमत, सभारी टैक्स और मौजूदा राजनीतिक माहौल है।

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

कोशिश करना मेरा काम है

दिल से

फिल्म 'हालीडे' में ग्रे किरदार से करियर की शुरुआत करने वाले फ्रेडी दारुवाला आगामी फिल्म 'द वाइव्स' को लेकर चर्चा में हैं। इंडस्ट्री में 10 साल पूरे कर चुके फ्रेडी दारुवाला ने स्मिता श्रीवास्तव के साथ साझा किए इंडस्ट्री के कई दिलचस्प रंग...

हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार रहे, जिन्होंने शुरुआत खलनायक के तौर पर की, उसके बाद उनके कदम विविध किरदारों को निभाने की ओर बढ़े। अभिनेता फ्रेडी दारुवाला भी उनमें से एक हैं। उन्होंने फिल्म 'हालीडे' में खलनायक के तौर पर दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। धीरे-धीरे खुद को अलग-अलग भूमिकाओं में आजमाया ताकि टाइपकास्ट न हो जाएं।

@freddy_daruwala (इंस्टा.)

आगामी दिनों में फिल्म 'द वाइव्स' में नजर आने वाले फ्रेडी कहते हैं, 'मुझे तब भी इस बात का डर था और आज भी है कि कहीं मैं टाइपकास्ट न हो जाऊं। एक बात मैंने इन 10 वर्षों में इंडस्ट्री में सीखी है कि एक अभिनेता अपनी महत्वाकांक्षा, अहमियत और स्वीकार्यता के बीच लगातार झूलता रहता है। महत्वाकांक्षा तो रहती है, बहुत कुछ करना होता है, लेकिन एक हद तक यह स्वीकार भी करना पड़ता है कि जो मिल रहा है, वही करना है। निश्चित रूप से मैंने कोशिशें की हैं। मेरी कोशिशें सफल हो रही हैं या विफल, इन दोनों का ही श्रेय मुझे जाएगा।'

हमारे साथ जुड़े हैं लोग

फ्रेडी तयशुदा कार्य अवधि को लेकर कहते हैं, 'अपने काम को शिद्दत से करना हमारा कर्तव्य है। हमारे साथ हमारा काम ही नहीं, सेट पर 250 लोग भी जुड़े होते हैं। हमें सुनिश्चित करना होता है कि जो भी काम कर रहे हैं, अच्छे से हो ताकि सबका संतुलन बना रहे। उसमें घंटे और दिन नहीं देखे जाते, बस काम देखा जाता है।' कलाकार इन दिनों अपने पीआर पर भी काफी जोर दे रहे हैं। खुद को हर जगह दिखाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। इस चलन को लेकर फ्रेडी कहते हैं, 'पेड पीआर करके हर बार काम नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि जो प्रसिद्ध है, वो टैलेंटेड भी हो। इनका भेद इंडस्ट्री धीरे-धीरे जानने लगी है।'

चर्चा में

कान में छाया देसी ग्लैमर

79वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेत्रियों ने शानदार लुक्स, परिधानों और दमदार प्रेजेंस से वैश्विक मंच पर अमिट छाप छोड़ी है। फ्रांस के पैलेस आफ फेस्टिवल्स एंड कांग्रेस के रेड कार्पेट पर देसी संस्कृति व आधुनिक वेस्टर्न गाउन का कैसा संगम देखने को मिला, बता रही हैं आरती तिवारी...

सभी फोटो- एएफपी

लड़की ब्यूटीफुल

अभिनेत्री आलिया भट्ट ने कान 2026 में इंटरनेशनल विंटेज और भारतीय परंपरा का जादुई कांबिनेशन पेश किया। उन्होंने तरुण तहिलियानी के कस्टम आइवरी और मैरून गाउन-साड़ी फ्यूजन से लेकर डेनिएल फ्रेंकेल के फेडेड ब्लू मिंट गाउन तक कई बेहतरीन परिधान पहने। उनके लुक में विक्टोरियन कोर्सेट, पारंपरिक चंदेरी धोती स्कर्ट और बारीक जरी की कलाकारी साफ दिखाई दी। भारत पवेलियन के उद्घाटन के दौरान उन्होंने पारंपरिक नथ, बिंदी व हाथफूल पहनकर भारतीय धरोहर को पुनर्जीवित किया। मिनिमल मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल ने उनकी रायल प्रेजेंस को प्रसारित किया।

कल्याणी का जादू

दक्षिण भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करते हुए अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने इस साल कान डेब्यू किया स्ट्रैपलेस गाउन के साथ। इस परिधान में डीप पर्पल बाडीकान चोली के साथ काले रंग का शिमरी बार्डर लगा था। गाउन पर हाथ से की गई हजारों महीन मोतियों की कढ़ाई इसकी मुख्य विशेषता थी। उनकी फ्रेश, क्लासी और आत्मविश्वास से भरी प्रेजेंस ने वैश्विक सिनेमा के मंच पर कमाल का जादू चलाया।

दिल से देसी

अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने इस साल कान 2026 में अपनी 'बास गर्ल' और 'देसी हेरिटेज' दोनों छवियों को बखूबी दर्शाया। पारंपरिक लुक के लिए उन्होंने 'शांति बनारस' की डीप प्लम बनारसी साड़ी चुनी, जिस पर सोने के तारों से हाथी और खजूर के पेड़ों के आधुनिक मोटिफ्स बने थे। रेड कार्पेट पर उन्होंने गैब्रिएला हर्स्ट के स्ट्रक्चर्ड डबल-ब्रेस्टेड ब्लेजर सूट और इमान अलाजला के ड्रामेटिक ब्लैक मखमली गाउन में वेस्टर्न पावर-ड्रेसिंग दिखाई। उन्होंने लुक को चमड़े के हैंडबैग, दिल के आकार के हीरे के हार और टेंपल ज्वेलरी के साथ पूरा किया।

क्लासिक क्वीन

कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू कर रहीं तारा सुतारिया ने बेहतरीन फैशन सेंस से सभी को प्रभावित किया। रेड कार्पेट पर चलने के लिए उन्होंने आल-व्हाइट एलीगेंट गाउन चुना, जो उन पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। अपने इस क्लासिक मोनोक्रोम परिधान के साथ तारा ने पन्ने (एमराल्ड) और हीरों का नेकलेस और झुमके टीम-अप किए गए थे। मेकअप को साफ्ट-ग्लैम रखते हुए उन्होंने न्यूड लिप्स और स्लीक बन हेयरस्टाइल चुना। उनकी ग्रेसफुल प्रेजेंस ने रेड कार्पेट पर लक्जरी और क्लासिक हालीवुड क्वीन वाली वाइब्स बिखेरीं।

राजसी अंदाज

अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने चिरपरिचित शाही अंदाज और ग्रेस के साथ कान के रेड कार्पेट पर कदम रखा। उन्होंने 'जेड बाय मोनिका एंड करिश्मा' की खूबसूरत पारंपरिक शैंपेन-सिल्क टिशू साड़ी पहनी, जिसके साथ डार्क रेड लिपस्टिक का कंट्रास्ट कमाल का था। उनका लुक बेहद कम और सिलेक्टेड डायमंड ज्वेलरी के साथ 'लेस इज मोर' (कम ही ज्यादा है) पर आधारित था। उनकी प्रेजेंस को इंटरनेट मीडिया पर टाइमलेस विजुअल ट्रीट कहकर सराहा गया।

फैशन का जलवा

कान फिल्म फेस्टिवल में लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड शोपार्ड के मशहूर मिरेकल गाला शो के लिए पहुंचीं जैक्लीन फर्नांडीज कैरोलिन काउचर द्वारा डिजाइन की गई स्ट्रैपलेस ब्लैक मिनी ड्रेस पहनी। इसके साथ उन्होंने डायमंड नेकलेस, स्पाइरल ईयररिंग्स और ब्रेसलेट को पेयर किया। इस हाई-प्रोफाइल शाम में आमंत्रित होने वाली वह इकलौती भारतीय सेलेब्रिटी रहीं। इस इवेंट में उनके साथ बेला हदीद, डेमी मूर व एड्रियाना लीमा जैसी कई ग्लोबल हस्तियां भी शामिल हुई थीं।

परी हूं मैं

हर साल की तरह इस बार भी उर्वशी रौतेला भव्य फैशन में दिखीं। वियतनामी लेबल 'जोलिपोली' का यह कस्टम शीयर और लैवेंडर मरमेड-स्टाइल गाउन चांदी के क्रिस्टल, मोती, सीक्विन और हैवी जरी के काम से जगमगा रहा था। गाउन का आकर्षण उसके स्ट्रक्चर्ड कोर्सेट डिजाइन व बाजुओं से निकलते लंबे केप स्लीव्स थे, जो पंखों जैसा लुक दे रहे थे। मांगटीका नुमा हेडपीस, भारी झुमके और चमकीला ब्रेसलेट उन्हें बेहद ड्रामेटिक और ध्यान खींचने वाला बनाए रहा।

इन दिनों

सिनेमा की पिच पर क्रिकेट का जुनून

इन समय देश में इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) का रोमांच चरम पर है। क्रिकेट के प्रति जुनून को देखते हुए फिल्मकार उसे पर्दे पर लाते रहे हैं। सिनेमा और क्रिकेट के इस सुपरहिट कनेक्शन को भुनाने के लिए निर्देशकों की तैयार है पलटन। दीपेश पांडेय का आलेख...

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में वर्ष 2002 की नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद सौरव गांगुली द्वारा लार्ड्स की बालकनी में टीशर्ट लहराने वाला दृश्य आज भी लोगों के जेहन में ताजा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के इसी जुनून और संघर्ष को राजकुमार राव फिल्म 'दादाः द सौरव गांगुली स्टोरी' में जीवंत करने की तैयारी में हैं। चार जून को रिलीज हो रही फिल्म 'पेद्दी' में अभिनेता रामचरण भी क्रिकेट की पिच पर नजर आएंगे। 'लगान' के बाद आमिर खान वर्ष 1962 में हुई पहली भारत-पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट सीरीज पर फिल्म लाने की तैयारी कर रहे हैं।

होती है कठिन तैयारी

दादा की बायोपिक को लेकर राजकुमार सौरव गांगुली के बंगाली लहजे को अपनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तैयारियों के बारे में राजकुमार बताते हैं, 'मेरे लिए सबसे बड़ी शारीरिक और तकनीकी चुनौतियों में से एक है बाएं हाथ से बल्लेबाजी सीखना। मैं दाहिने हाथ से काम करता हूं, जबकि सौरव बाएं हाथ के बल्लेबाज रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली को हूबहू अपनाने के लिए घंटों क्रिकेट की कड़ी ट्रेनिंग की है ताकि आवश्यक मसल मेमोरी विकसित हो सके।' इससे पहले फिल्म 'जर्सी' में क्रिकेटर की भूमिका निभा चुके शाहिद कपूर भी तैयारियों की कठिनाई के बारे में बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि शौकिया खिलाड़ियों के लिए पेशेवर खिलाड़ियों जैसी फिटनेस हासिल करना आसान नहीं होता।

बढ़ती संभावनाएं

क्रिकेट फिल्मों की बढ़ती संख्या के पीछे एक बड़ी वजह खेल से निकलकर सामने आ रही प्रेरक कहानियां भी हैं। आइपीएल और महिला प्रीमियर लीग जैसे मंचों ने कई नए खिलाड़ियों को पहचान दी है। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और उर्विल पटेल समेत कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। यही वजह है कि फिल्मकार क्रिकेट को इंसानी संघर्ष और सपनों की कहानी के रूप में भी देख रहे हैं। इसका उदाहरण फिल्म 'कौन प्रवीण तांबे?' रही, जिसमें अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने उस क्रिकेटर की कहानी निभाई, जिसने 41 वर्ष की उम्र में आइपीएल में डेब्यू किया। श्रेयस कहते हैं, 'जब मैंने प्रवीण तांबे को पहली बार आइपीएल में खेलते हुए देखा तो लगा कि यह तो उम्र में थोड़े बड़े लग रहे हैं। फिर पता चला उन्होंने 41 वर्ष की उम्र में आइपीएल में डेब्यू किया है। तब बतौर अभिनेता और फिल्मकार दिमाग में आया कि यह तो बहुत अच्छी कहानी हो सकती है। डेब्यू करने से पहले वह कहां थे, उनके क्या संघर्ष रहे, उनकी 20-22 साल के संघर्ष की कहानी लोगों के बीच पहुंचाना जरूरी है।'

मिलती मिली- जुली प्रतिक्रिया

क्रिकेट आधारित फिल्मों को लेकर बाक्स आफिस के आंकड़े मिले-जुले रहे हैं। 'लगान' ने अच्छी कमाई के साथ आस्कर के नामिनेशन तक का सफर तय किया। 2016 में आई 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' ब्लाकबस्टर साबित हुई। शाहिद कपूर अभिनीत 'जर्सी' व तापसी पन्नू की 'शाबाश मिट्ठू' (भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज की बायोपिक) को दर्शकों ने नकार दिया था।

आमिर की बनेगी बायोपिक

हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर के दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन की बायोपिक की घोषणा की गई। आमिर के दोनों हाथ नहीं है। इस फिल्म के निर्देशक निशिल सेठ का कहना है, 'बेशक क्रिकेट आमिर की जिंदगी का बड़ा हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी उससे कहीं आगे है। मुझे आमिर के मानवीय पहलुओं और उनके इस पड़ाव तक पहुंचने की कहानी में ज्यादा दिलचस्पी है। जब हम स्क्रीन पर ऐसी कहानियां या पात्र देखते हैं, तो हम असल में उस पात्र के सपनों और कमजोरियों से मिलते हैं। इससे एक इंसान को हीरो बनाने में मदद मिलती है!'

'पेद्दी' में अभिनेता रामचरण

मनोरंजन के हर अपडेट और अधिक खबरों के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।

आज का भविष्यफल- 22 मई, 2026 शुक्रवार

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष षष्ठी।
राहुकाल: प्रातः 10:30 से 12 बजे तक।
दिशाशूल: पश्चिम।
विशेष: सप्तमी तिथि क्षय।

कल 23 मई 2026 का पंचांग

कल का दिशाशूल: पूर्व। **कल की भद्रा:** प्रातः 05:05 से सायं 04:41 तक। **कल का पर्व एवं त्योहार:** दुर्गाष्टमी
विशेष: सप्तमी तिथि क्षय, बुध उदय पश्चिम में।
विक्रम संवत 2083 शके 1948 उत्तरायण, उत्तरगोल, वसंत ऋतु अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी 28 घंटे 28 मिनट तक, तत्पश्चात नवमी मघा नक्षत्र 26 घंटे 10 मिनट तक, तत्पश्चात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र ध्रुव योग 06 घंटे 14 मिनट तक, तत्पश्चात व्याघात योग सिंह में चंद्रमा।

मेष: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा।
वृष: परिवार के सदस्य से तनाव मिल सकता है। ससुराल पक्ष से वाद-विवाद करने से बचें।
मिथुन: रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
कर्क: आर्थिक मामलों में सुधार होगा। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।
सिंह: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों मे रुचि बढ़ेगी। सफलता हासिल करेंगे।
कन्या: तनाव मिल सकता है। मन अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।
तुला: शासनसत्ता का सहयोग रहेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।
वृश्चिक: महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी।
धनु: पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
मकर: उपहार की प्राप्ति या सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन जीवनसाथी के कारण तनाव मिल सकता है।
कुंभ: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
मीन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान या शिक्षा के कारण चिंतित रहेंगे।

वर्ग पहेली-3342

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं:-
1. जगमगाना, प्रकाश देना (4)। 3. अंधकार, अंधेरा (3)। 5. शोभा, देना, सुंदर लगना (3)। 6. किस समय (2)। 8. दाह करना (3)। 10. एक नंबर का छंटा हुआ (3)। 11. पतिव्रता स्त्री, साध्वी स्त्री (2)। 13. वंदन करने योग्य (4)। 15. उसके उपरांत या बाद (4)। 16. नस, नाड़ी, जिद (2)। 18. व्याकुल, अधीर (3)। 19. सहस्र (3)। 21. प्रतिष्ठा, नासिका (2)। 23. पाचन क्रिया में सहायक (3)। 24. सीमावर्ती क्षेत्र, हद (3)। 25. चंचल, शरारती (4)।

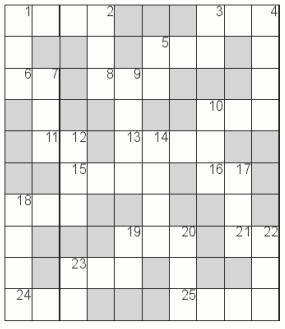

ऊपर से नीचे:-
1. बदन पर सफेद दाग का रोग (3)। 2. क्रुद्ध, दुखी (3)। 3. वृक्ष का धड़ (2)। 4. समावेश (4)। 5. कुर्बान, नष्ट (2)। 7. वाद-विवाद (3)। 9. जिसको लज्जा हो (4)। 10. शायरी करने वाला (3)। 12. आधा..., आधा बटेर (3)। 14. द्वार, फाटक (4)। 17. आभूषण, बंधक (3)। 18. गुप्त बात, मंत्रणा (4)। 19. अधिकार, सत्य (2)। 20. रहने का भाव (3)। 22. किवाड़ (3)। 23. पत्ता, पत्र (2)।

कल का हल

स	रा	स	र				ना	य	क
ह			डा	ह	क	र	ना		रा
सा	झे	दा	र		थ		रू		ह
	ल			जा	न		प	सी	ना
	म	ग	र			स		ना	
	न		दी			दी	न	ता	
न	दी	श		सि	वा			न	
र		क		त		क	ल	ना	द
मा		टी	ल	म	टो	ल			ह
नी	ह	र				म	हा	ज	न

सुडोकू-3342

8		5		2		3		4
	9						2	
		2	6		7		9	
2				8		4		7
	4		7		5			
7				4			1	6
3			5					1
		4		9		7		
6			8		3			9

कल का हल

8	4	2	9	3	1	6	7	5
3	7	1	2	5	6	8	9	4
9	6	5	4	8	7	1	2	3
7	3	9	6	1	5	4	8	2
5	2	6	8	4	9	3	1	7
4	1	8	3	7	2	9	5	6
2	9	3	5	6	8	7	4	1
1	5	4	7	9	3	2	6	8
6	8	7	1	2	4	5	3	9

राष्ट्रीय फलक

हम जहां रहते हैं, वहां प्रकृति का संरक्षण करें: डा. भागवत

नईदुनिया, शहडोल : सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके लिए समाज को सहयोग दें और समाज से सहयोग लें। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार रखना आज बहुत आवश्यक है। हम जहां रहते हैं, वहां प्रकृति का संरक्षण करें। संघ प्रमुख ने स्वयंसेवकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का सदुपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया।

संघ प्रमुख गुरुवार को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ता विकास वर्ग में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। इसमें मध्य क्षेत्र के चार प्रांत-मालवा, मध्य भारत, महाकोशल और छत्तीसगढ़ के 383 स्वयंसेवक प्रशिक्षण ले रहे हैं। डा. भागवत ने स्वयंसेवकों से कहा कि सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर स्वयंसेवक लगातार नजर रखें।

30 दिनों में साढ़े सात लाख श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ

बृजेश भट्ट • जागरण

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में इस वर्ष प्रतिदिन 28 से 30 हजार श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। यात्रा के पहले 30 दिनों में ही साढ़े सात लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 30 हजार अधिक हैं। यात्रा के दौरान अब तक 28375 श्रद्धालु हेलीकाप्टर सेवा के माध्यम से धाम पहुंचे हैं। हेली सेवा से अब तक करीब 28 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। अनुमान है कि एक महीने के भीतर ही 200 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हो चुका है। वहीं गुरुवार को बदरीनाथ धाम में 26,711 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसी तरह यमुनोत्री धाम में भी गुरुवार को पहली बार सर्वाधिक 16,694 श्रद्धालु पहुंचे। 18 मई को 16,136 ने यमुनोत्री धाम में दर्शन किए थे। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के मौके पर ही 38 हजार श्रद्धालु पहुंचे थे, जो कि केदारनाथ यात्रा के इतिहास में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

केदारनाथ धाम में दर्शनों को उमड़ी भक्तों की भीड़। साभार : सतीश गैरोला

मध्यमेश्वर धाम में विराजमान हुए बाबा द्वितीय केदार

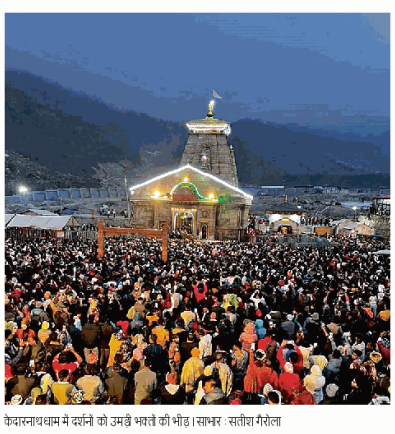

जासं, रुद्रप्रयाग : द्वितीय केदार मध्यमेश्वर धाम के कपाट कर्क लग्न में गुरुवार पूर्वाह्न 11:30 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। गुरुवार को बाबा की चल विग्रह उत्सव डोली अपने अंतिम पड़ाव गौंडार से सुबह 10 बजे मध्यमेश्वर धाम पहुंची। सुबह 10:30 बजे मंदिर के मुख्य द्वार पर पूजा शुरू हुई और तय मुहूर्त पर कपाट खोल दिए गए।

इसके बाद पुजारी शिव शंकर लिंग ने भगवान मध्यमेश्वर के स्वयंभू लिंग को समाधि रूप से शृंगार रूप दिया और फिर दर्शन का क्रम शुरू हो गया। बता दें कि शीतकाल के समापन या कपाट खुलने के तुरंत बाद स्वयंभू शिवलिंग को विशेष सामग्री से ढककर समाधि रूप दिया जाता है। ऐसे में शिवलिंग से समाधि हटाकर उन्हें निर्मल और प्राकृतिक रूप में लाया जाता है। इस मौके पर 1,135 श्रद्धालुओं ने बाबा मध्यमेश्वर के दर्शन किए।

राम मंदिर निर्माण में प्रयुक्त औजारों को भी सहेजेगा ट्रस्ट

▶ योजना है कि जुड़े सभी अभिलेखों व साक्ष्यों को डिजिटलाइज्ड करा रामकथा संग्रहालय में प्रदर्शित हों

रामघाट स्थित मंदिर निर्माण कार्यशाला। जागरण

जागरण संवाददाता, अयोध्या

जन्मभूमि पर निर्मित दिव्य-भव्य राम मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त औजारों को भी श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट संरक्षित करेगा। इन्हें भविष्य में श्रीरामजन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला में प्रदर्शित करने की भी योजना है।

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की योजना है कि मंदिर से जुड़े सभी अभिलेखों व साक्ष्यों को डिजिटलाइज्ड कराकर रामकथा संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाए। इसी क्रम में उन औजारों को भी सहेजने की योजना बनी है, जिनका उपयोग मंदिर निर्माण के निमित्त हुआ। पत्थरों की तराशी में प्रयुक्त छेनी, हथौड़ी, मुंगरी, घुमावदार आरी, स्टोन कटर मशीन, ग्राइंडर पालीशर आदि सहित सभी औजारों को संरक्षित करने की योजना है। उस कटर मशीन को भी संरक्षित किया जाएगा, जो निर्माण कार्यशाला में अभी रखी है। इसे विहिप ने वर्ष 1990 में 40 लाख रुपये की लागत से खरीदा था। इस मशीन से लगभग एक लाख घनफीट पत्थरों की कटाई हुई थी।

चिली में आया था इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप

1960 में आज ही चिली में 9.5 तीव्रता का वाल्डिविया भूकंप आया था। इसे अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। इसके कारण आई सुनामी ने हवाई, जापान और फिलीपींस के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। इस आपदा में 6000 लोगों की मौत हुई थी।

डा. शेफील्ड ने शुरू किया टूथपेस्ट में प्लास्टिक ट्यूब का उपयोग

1892 में आज ही अमेरिका के दंत चिकित्सक डा. वाशिंगटन शेफील्ड ने टूथपेस्ट ट्यूब का आविष्कार किया था। इससे पहले, टूथपेस्ट जार में बेचा जाता था, जिसे असुविधाजनक और अस्वास्थ्यकर माना जाता था। पहले ट्यूब टिन से बनती थी। बाद में प्लास्टिक ट्यूबों का उपयोग होने लगा।

कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा

स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का जन्म 1963 में आज ही राजस्थान के कोटा में हुआ था। 14 जून, 1985 को भारतीय वायु सेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। 27 मई, 1999 को कारगिल में आपरेशन सफेद सागर के तहत वे लड़ाकू विमान मिग-21 से दुश्मन के ठिकानों की जानकारी जुटा रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने मिसाइल से उनके विमान को निशाना बनाया, जिसके बाद उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। एलओसी के पार पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंधक बना लिया और टार्चर करने के बाद गोली मार दी। उनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

ध्यान अधिक असरदार, अल्फावेव्स बदलती हैं दिमाग

अध्ययन ▶ आइआइटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने खिलाड़ियों और ध्यान लगाने वालों के ब्रेन सिग्नलों की तुलना की

तीन अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के ब्रेन सिग्नल्स का विश्लेषण किया गया

अखिलेश तिवारी । जागरण

कानपुर : आमतौर पर माना जाता है कि खेलकूद से मानसिक स्वास्थ्य सबसे अच्छा होता है, लेकिन आइआइटी के ताजा अध्ययन से पता चला है कि खेल से अधिक असरदार ध्यान है। इससे मस्तिष्क अधिक शांत, एकाग्र व संतुलित रहता है।

जब आप शांत या ध्यान की मुद्रा में होते हैं तो आपका दिमाग विशेष प्रकार की तरंगें 'अल्फावेव्स' छोड़ता है, जो दिमाग को बदलती हैं। अब शोधकर्ता इसी दिमागी रहस्य को सुलझाने में जुटे हैं कि तनाव निर्णय लेने की क्षमता, वर्किंग मेमोरी व नफा-नुकसान के आकलन को कैसे प्रभावित करता है।

आइआइटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर तुषार संधान की देखरेख में चल रहे इस अध्ययन में कुल 85 लोगों (सब्जेक्ट्स) को शामिल किया गया। इसमें तीन अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के ब्रेन सिग्नल्स का विश्लेषण किया गया। पहली में नियमित रूप से मेडिटेशन (ध्यान) करने, दूसरी में खेलकूद में सक्रिय रहने वाले युवा व छात्र, तीसरी में कभी मेडिटेशन या विशेष फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने वाले शामिल किए गए। प्रो. तुषार के अनुसार, इन तीनों श्रेणियों के ईईजी (इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम) सिग्नल्स में पाया गया कि स्पोर्ट्स की तुलना में ध्यान करने

प्रतीकात्मक

वाले लोगों के मस्तिष्क पर इसके कहीं अधिक सकारात्मक व गहरे प्रभाव थे। खेलकूद गतिविधियों का तनाव कम करने में 15 से 30 प्रतिशत तक योगदान है, जबकि मेडिटेशन करने वालों के मस्तिष्क में असर 20 से 40 प्रतिशत तक मिला। शांत दिमाग काम को और अच्छा करने लायक बनाता है। उन्होंने बताया कि 'आइईईई एक्सप्लोर' में रिपोर्ट के अनुसार, तनावग्रस्त व्यक्ति को दोनों कानों में 8-12 हर्ट्ज की अलग-अलग फ्रीक्वेंसी वाली 'बाइन्यूरलबीट्स' सुनाने पर अल्फा वेव्स में भारी बढ़ोतरी देखी गई है व तनाव तुरंत कम हुआ। इसलिए अब एक ऐसे 'वस्तुनिष्ठ' पैमाना या आटोमेटेड माडल पर काम किया जा रहा है, जो दिनभर के उतार-चढ़ाव के बीच तनाव के बारे में सटीक नतीजा दे सके।

आधुनिक गैजेट्स और एआइ के मेल से अध्ययन

प्रो. संधान के नेतृत्व में टीम मस्तिष्क के 'फ्रंटल लोब' में अल्फा तरंगों की गतिविधि की भी जांच कर रही है। मस्तिष्क का यही हिस्सा सही-गलत का फैसला करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके लिए टीम कई आधुनिक व स्वदेशी उपकरणों का उपयोग कर रही है। इसमें कस्टम 3डी प्रिंटेड हेडबैंड हैं, जो लचीले सिलिकान इलेक्ट्रोड से बने हैं व मस्तिष्क के ईईजी सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं। इसी तरह स्मार्टवाच-दिल की धड़कनों व कार्डियक एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए है, जबकि प्रो. संधान की टीम द्वारा विकसित एक विशेष एआइ एल्गोरिदम भावनाओं को पहचानने व तनाव के स्तर का विश्लेषण करने के लिए ईईजी डेटा को प्रोसेस करता है।

तुषार संधान। स्वयं

'राजा शिवाजी' की सफलता का जश्न

मुंबई में बालीवुड अभिनेता सलमान खान और रितेश देशमुख गुरुवार को फिल्म 'राजा शिवाजी' की सफलता के जश्न में शामिल हुए। पिछले दिनों के गुस्से के बाद सलमान खान ने पैपराजी से बातचीत की। फिल्म 'राजा शिवाजी' ने दुनिया भर में 117 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट में सलमान खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वफादार योद्धा और अंगरक्षक जीवा महाला का रोल किया है। एएनआइ

इधर-उधर

ट्रंप जैसे बालों वाला भैंसा बना इंटरनेट स्टार

भैंसे को आकर्षक हेयरस्टाइल ने दिलाई पहचान ● इंटरनेट मीडिया

ढाका, एजेंसी : बांग्लादेश के नारायणगंज में इन दिनों अनोखा भैंसा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 700 किलो वजन वाले इस दुर्लभ एल्बिनो भैंसे का नाम डोनाल्ड ट्रंप रखा गया है, क्योंकि इसके सिर पर उगे सुनहरे बाल हूबहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हेयरस्टाइल जैसे दिखाई देते हैं। इस भैंसे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भैंसे के मालिक जियाउद्दीन मृधा ने बताया कि उनके छोटे भाई ने मजाक-मजाक में इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप रख दिया था।

आयुर्वेद की दवाएं फोलिक एसिड सप्लीमेंट के समान असरदार

- ▶ आइसीएमआर और सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज द्वारा मल्टीसेंट्रिक क्लिनिकल ट्रायल में पता चला
- ▶ यह परीक्षण 18-49 आयु वर्ग की 4,000 ऐसी गैर गर्भवती महिलाओं पर किया गया, जो एनीमिया से पीड़ित थीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किए गए बहु केंद्रित क्लिनिकल परीक्षण में पाया गया है कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दो आयुर्वेदिक औषधियां मध्यम एनीमिया वाली महिलाओं में म आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के समान प्रभावी हैं। फेज-3 रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल (आरसीटी) के नतीजे 20 मई को आरसीएमआर द्वारा आयोजित " पहला आइसीएमआर वार्षिक क्लिनिकल ट्रायल मीट 2026" के दौरान पेश किए गए।

समान रूप से प्रभावी : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस अध्ययन में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के इलाज में आयुर्वेदिक दवाओं अकेले पुनर्नवाड़ी मंडूर और द्राक्षावलेह के साथ मिलाकर प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। भारत में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया एक बड़ी जन स्वास्थ्य समस्या है। इस अध्ययन में इन आयुर्वेदिक दवाओं की तुलना पारंपरिक आयरन फोलिक एसिड थेरेपी से की गई। यह परीक्षण लगभग 4,000 गैर-गर्भवती महिलाओं के बीच किया गया, जो 18-49 आयु वर्ग में मध्यम एनीमिया से ग्रस्त थीं। शोधकर्ताओं ने 90 दिनों की अवधि में हीमोग्लोबिन स्तर और अन्य क्लिनिकल परिणामों का मूल्यांकन किया। बयान में यह कहा गया कि निष्कर्षों ने यह दर्शाया कि दोनों आयुर्वेदिक हस्तक्षेप मानक आयरनफोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के समान प्रभावी थे। राष्ट्रीय स्तर की इस बैठक में नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, नियामक प्राधिकरणों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एकत्रित किया गया, ताकि भारत के क्लिनिकल परीक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और साक्ष्य-आधारित समग्र चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जा सके। कार्यक्रम में आइसीएमआर के महानिदेशक डा. राजीव बहल व केंद्रीय आयुष सचिव राजेश कोटेचा सहित स्वास्थ्य और विज्ञानी समुदाय के विशेषज्ञों व हितधारकों ने भाग लिया।

प्रतीकात्मक

37 विशेषज्ञों के साथ विकसित की गई रिपोर्ट : गणमान्य व्यक्तियों ने उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने और स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाने के लिए मजबूत क्लिनिकल अनुसंधान प्रणालियों, नैतिक शासन और एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों के वैज्ञानिक सत्यापन के महत्व पर ज़ोर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान आइसीएमआर ने "भारत में 'फर्स्ट-इन-ह्यूमन' फेज 1 क्लिनिकल परीक्षणों को आगे बढ़ानाः विनियामक मार्गों और अवसरों पर एक डेल्फी अध्ययन" शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी की। यह रिपोर्ट फार्मास्यूटिकल उद्योग, अनुबंध अनुसंधान संगठनों, अकादमिक संस्थानों और राष्ट्रीय नियामक एजेंसियों के 37 विशेषज्ञों के साथ दो दौर की परामर्श के माध्यम से विकसित की गई थी, जिसमें भारत में प्रारंभिक चरण के क्लिनिकल परीक्षणों को आगे बढ़ाने में बाधाओं की पहचान की गई। रिपोर्ट ने नियामक क्षमता को मजबूत करने, अनुमोदन तंत्र को सरल बनाने और एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करने की सिफारिश की। इस कार्यक्रम में भारत में बहु केंद्र अनुसंधान के लिए एकल नैतिक समीक्षा के संचालन संबंधी दिशानिर्देश" भी जारी किए गए, जिसका उद्देश्य देश भर में बहु-केंद्र अध्ययनों के लिए नैतिक समीक्षा तंत्र को समन्वयित करना है।

जेनेटिक म्यूटेशन से आटिज्म के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा होती है प्रभावित

अनुसंधान

एक अध्ययन में पाया गया है कि आटिज्म के लिए जिम्मेदार जेनेटिक म्यूटेशन की गंभीरता उन तंत्रों पर हावी हो सकती है जो महिलाओं को न्यूरोडेवलपमेंटल डिसआर्डर से बचाते हैं। आटिज्म विकार महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक प्रभावित करता है। माना जाता है कि महिलाओं के पास जैविक सुरक्षात्मक तंत्र होते हैं जो इस स्थिति के प्रति संवेदनशीलता को कम करते हैं।

योनसेई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लेखक यूनी ली ने कहा, "हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि महिलाओं में सीएचडी8 से संबंधित शिथिलता के खिलाफ सुरक्षात्मक जैविक तंत्र हो सकते हैं, लेकिन गंभीर म्यूटेशन उन सुरक्षात्मक प्रभावों को खत्म कर सकते हैं। यह इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि जेनेटिक पृष्ठभूमि व म्यूटेशन शक्ति के आधार पर आटिज्म की गंभीरता और लिंग संबंधी भिन्नता क्यों हो सकते हैं।" जीन 'सीएचडी8' को आटिज्म और अन्य न्यूरोडेवलपमेंटल स्थितियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारकों में से एक माना जाता है। यह क्रोमैटिन संरचना, डीएनए, आरएनए व प्रोटीन युक्त एक जटिल मैक्रोमोलेक्यूल को रीमाडलिंग करके मस्तिष्क के विकास में शामिल जीन की गतिविधि को विनियमित करने में मदद करता है। शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला व्यवहार्य माउस माडल विकसित किया है, जिसमें माता-पिता से विरासत में मिला समान सीएचडी8 म्यूटेशन होता है। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

करण पर धोखेबाजी के आरोपों का तेजस्वी ने किया बचाव

चार साल से डेट कर रहे हैं करण व तेजस्वी। (@tejasswiprakash)

हर किसी का अपना अपना अतीत होता है। यह कहना है अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश का अपने ब्वायफ्रेंड और अभिनेता करण कुंद्रा पर लग रहे धोखेबाजी के अरोपों पर। दरअसल, तेजस्वी से पहले करण अभिनेत्री अनुषा दांडेकर के साथ करीब साढ़े तीन साल तक रिलेशनशिप में थे। अनुषा ने कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू में बिना करण का नाम लिए अपने पूर्व ब्वायफ्रेंड पर धोखा देने और दूसरी लड़कियों के साथ रहने का आरोप लगाया था। जिसके बाद लोग इंटरनेट मीडिया पर करण पर धोखेबाजी का आरोप लगाने लगे। हालांकि, उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी उनके सपोर्ट में खड़ी दिखी। हाल ही में तेजस्वी ने रियलिटी शो देसी ब्लिंग में करण पर लग रहे आरोपों पर कहा कि हम सभी का अपना अतीत होता है। कुछ लोगों का अतीत लोगों के बीच सामने आ जाता है। उन्होंने (करण) धोखेबाजी की या नहीं, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच मुझे बताई है। वह सोचते हैं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या जानती है, लेकिन आपको (तेजस्वी) मेरे बारे में सच पता होना चाहिए। इस दौरान करण से शादी को लेकर आ रही खबरों पर तेजस्वी ने कहा कि मेरा एक ब्वायफ्रेंड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं शादी करूं। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि हम सगाई कब करने जा रहे हैं।

एनिमल में बाबी देओल की खलनायक भूमिका से खुश नहीं थे धर्मेंद्र

साल 2023 में प्रदर्शित फिल्म एनिमल में अभिनेता बाबी देओल ने अबरार की भूमिका में खूब सुर्खियां बटोरी। यह एक ऐसे क्रूर खलनायक की भूमिका थी जो बोल नहीं पाता है। बाबी ने इस फिल्म में अपने डांस स्टाइल से लेकर एक्शन तक खूब सराहना बटोरी थी। हालांकि, उनके पिता और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र बेटे की इस भूमिका से खुश नहीं थे। इस बारे में बाबी ने हाल ही में अभिनेता शेखर सुमन के शो शेखर टुनाइट में बताया कि फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खेलों से जुड़ी एक इवेंट में उनकी तस्वीर देखकर इस रोल का प्रस्ताव दिया था। बाबी ने कहा कि जब मुझे संदीप रेड्डी वांगा का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि तेरे जो एक्सप्रेशन (हाव भाव) हैं इस फोटोग्राफ में, वो मुझे पसंद आए। मैं आपको अपनी इस फिल्म में चाहता हूं। आगे बाबी ने बताया कि उनके पिता धर्मेंद्र इस रोल को लेकर खुश नहीं थे। बाबी ने कहा कि एनिमल जब लगी, तो पापा ने पूछा कि तू विलेन (खलनायक) है? तो मैंने कहा कि हांजी पापा, लेकिन अच्छा रोल है। बता दें कि बाबी आगामी दिनों में फिल्म बंदर में नजर आएंगे।

फिल्म अल्फा में भी खलनायक भूमिका में दिखेंगे बाबी। फाइल

अपने निर्णयों पर बेटी को गर्व करते हुए देखना चाहते हैं इमरान

हर पिता चाहता है कि उसके बच्चों की नजर में उसके लिए हमेशा गर्व और सम्मान दिखे। डेल्ही बेल्ही और मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्मों के अभिनेता इमरान खान की सोच भी इससे अलग नहीं है। इमरान तो अपनी फिल्मों का चुनाव भी बेटी को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। फिल्म कट्टी बट्टी के बाद अभिनय से दूरी बनाने के 11 साल बाद इमरान अब दानिश असलम निर्देशित फिल्म से वापसी के लिए तैयार हैं। इससे पहले वह इस साल प्रदर्शित फिल्म हैप्पी पटेल : खतरनाक जासूस में मेहमान भूमिका में दिखे थे। एक पिता के तौर पर इमरान कहते हैं, 'मुझे सच में इस बात की बड़ी फिक्र रहती है कि बड़ी होकर मेरी बेटी मेरे निर्णयों के बारे में क्या सोचेगी? यही आगे बढ़ने के लिए एक शानदार तरीका भी लगता है। जैसे-जैसे वो बड़ी हो रही है, मैं चाहता हूं कि वो पीछे मुड़कर देखे कि मैं उसके लिए किस तरह का पिता रहा हूं। साथ ही वह मेरे क्रिएटिव निर्णयों को भी देखे, जो मैंने बतौर कलाकार लिया है। मैं चाहता हूं कि वो मेरी फिल्मों को बेझिझक देख सके और हम दोनों इस बारे में बातें कर सकें, तो अच्छा लगेगा। मैं उन कहानियों से दूर रहना चाहूंगा, जिन प वो मुझसे पूछे कि आपने ऐसा कैसे किया?

वापसी को लेकर हर पहलुओं पर तैयारी कर रहे हैं इमरान। फाइल

अभिनय में स्वयं को साबित करना चाहते हैं जेस्सी। इंस्टाग्राम (@jesse_lever)

ऐसे मौके का इंतजार था : जेस्सी लीवर

जब पिता फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम हो, तो बच्चों पर भी स्वयं को साबित करने का दबाव अपने आप आ जाता है। कामेडियन और अभिनेता जानी लीवर के बेटे और अभिनेता जेस्सी लीवर हालिया प्रदर्शित फिल्म आईआईजी : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ जाम्बिज में पहली बार केंद्रीय भूमिका में नजर आए। इससे पहले वह बार और ये साली आशिकी जैसी फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभा चुके हैं। जेस्सी को ऐसी केंद्रीय भूमिका वाले मौके की तलाश काफी दिनों से थी। वह बताते हैं, 'पापा और बहन (कामेडियन और अभिनेत्री जैमी लीवर) तो स्टैंडअप कामेडी करते रहे हैं, लेकिन मैंने कभी स्टैंडअप कामेडी नहीं की। मैंने हमेशा बतौर अभिनेता फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा था, तैयारी भी उसी हिसाब से की थी। उसके लिए पांच-छह साल पहले एक्टिंग का कोर्स भी किया था। बतौर कलाकार जब आपको कोई केंद्रीय भूमिका निभाने का मौका मिलता है, तो उससे इंडस्ट्री में स्थापित होने में मदद मिलती है। मैं ऐसे मौके की तलाश में था, और वह मौका मिल ही गया, जिसमें लोग देख पाएं कि हां, ये कलाकार भूमिकाएं भी निभा सकता है। फिल्म मिलने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी बहन जैमी को बताया, हम दोनों के बीच महज डेढ़ साल का अंतर है।

जिनको नहीं जानती उनकी राय की परवाह नहीं : सबा आजाद

सात सवाल

बीते दिनों पेट में गंभीर संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हुई अभिनेत्री और गायिका सबा आजाद अब स्वस्थ हैं। वह वेब शो हूज योर गायनेक? सीजन 2 में एक बार फिर डा. विदुषी कोठारी की भूमिका में नजर आई हैं। वहीं दूसरी ओर वह वेब सीरीज स्टार्म की शूटिंग कर रही हैं। उनकी फिल्म बंदर भी अगले महीने रिलीज होगी। उन्होंने की खास बातचीत :

● पर आप अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हैं। यह आदत कहां से शुरू हुई?

-बचपन से। मैं छह या सात साल की उम्र से ही ओडिसी डांस सीख रही थी। डांस क्लास रोज होती थी, उसके साथ ही एक्सरसाइज हो जाती थी और मेरे पापा फिटनेस को लेकर बहुत सजग थे। वो हमें ट्रैकिंग के लिए लेके जाते थे और रविवार को दिल्ली में राक क्लाइम्बिंग के लिए लेकर जाते थे।

● जब आपने इस शो के पहले सीजन के लिए हां कहा था, तब आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी थी?

-मुझे लगा कि महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं होती। जबकि ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर बात होनी चाहिए। इस शो में उन बातों को हास्य और मजाक के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। अक्सर गंभीर विषयों को अगर हल्के अंदाज में कहा जाए, तो वे ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं और लोगों के मन में बेहतर तरीके से बैठ जाते हैं।

● सिनेमा की तुलना में ओटीटी महिलाओं की कहानी को नए नजरिए से दिखा रहा है?

-मुझे लगता है कि कहानी, विषय को लेकर ओटीटी ज्यादा जोखिम ले रहा है क्योंकि यहां पर बाक्स आफिस आंकड़ों का डर नहीं है, जो सिनेमा में बैठा हुआ है। अभिनेत्रियों के लिए जो भूमिकाएं लिखी जा रही हैं, वे अब काफी बेहतर हो गई हैं। अब अभिनेत्रियां पूरे शो का भार अपने कंधों पर उठा रही हैं।

● हाल ही में किसी अभिनेत्री ने कहा था कि सबसे पहले अभिनेत्रियों की फीस काट दी जाती है। आपकी फीस कभी कम की गई?

-मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ भी होगा, तो शायद मुझे उसका पता नहीं चला। मुझे नहीं मालूम कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन पे पैरिटी, यानी बराबर भुगतान, बिल्कुल नहीं है यह मुझे पता है। अगर आप उतनी ही लंबाई का रोल कर रहे हैं, उतनी ही अहमियत वाला रोल कर रहे हैं, और उतने ही दिनों की शूटिंग भी कर रहे हैं, तब भी आपको उतनी फीस नहीं मिलेगी। हालांकि अब चीजें बेहतर हो रही हैं, कुछ हद तक।

● बंदर और स्ट्राम का हिस्सा बनने की क्या वजह रही?

-सबसे पहले, मैं अजीतपाल सिंह (स्ट्राम के निर्देशक) की बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इसलिए स्क्रिप्ट मेरे पास आने से पहले ही, तय कर लिया था कि मैं यह जरूर करूंगी। हाल ही में मैंने इसकी शूटिंग पूरी की है। बंदर में कई थिएटर कलाकार हैं, अनुराग कश्यप जैसे बेहतरीन निर्देशक हैं। वह स्क्रिप्ट को सिर्फ एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करते हैं। (स्मिता श्रीवास्तव)

@sabazad

● आपने कहा था ट्रोलिंग को लेकर अपनी मोटी चमड़ी कर ली है। किस अनुभव ने आपको इतना मजबूत बनाया?

-अगर आप देखें तो औरतों की लगातार ट्रोलिंग होती है। आप कोई भी बेहतर से बेहतर एक्टर को देख लें, उनकी अपीयरेंस, काम और उनकी निजी जिंदगी के बारे में दुनिया को लगता है कि वो उस पर लेक्चर दे सकते हैं। क्योंकि आप पब्लिक प्रापर्टी हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप वो सुनते रहेंगे तो आपकी जिंदगी उसी में खोकर रह जाएगी। फिर आपको बोलना पड़ता है कि मैं इन लोगों को निजी तौर पर नहीं जानती। उनकी राय की परवाह नहीं करती। अगर मैं आपसे सलाह नहीं लूंगी मैं आपसे आलोचना भी नहीं लूंगी। ये सिंपल सी बात है। मेरे अपने लोग हैं जिनकी मैं आलोचना सुनूंगी और सलाह सुनूंगी।

● आप फ्रांस में छुट्टियां मना के आई हैं। कैसी रही छुट्टियां ?

-इस बार मैं बस छुट्टी के लिए गई थी क्योंकि मेरी उससे पहले सेहत थोड़ी खराब थी। एक दुर्लभ पैरासाइट की वजह से इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि सलाद को ठीक से धोया नहीं गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूं।

आमिर ने माना-बेटे की फिल्म फ्लाप होने से हुई निराशा

> हम फिल्में दर्शकों के लिए बनाते हैं। अगर उन्हें किसी कारण से फिल्म पसंद नहीं आती, तो कहीं न कहीं हमारे काम में कमी रह गई। फिल्म फ्लाप होने पर मेरा दिल टूट जाता है, मैं महीनों तक डिप्रेशन में चला जाता हूं, क्योंकि फिल्म हमारे बच्चे जैसी होती है।

@amirkhanactor_

हिंदी सिनेमा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने साल 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित फिल्म महाराज से अभिनय में कदम रखा था। उसके बाद जब बारी टिकट खिड़की पर परीक्षा की आई, तो जुनैद अपनी दोनों ही फिल्मों लवयापा और एक दिन में असफल रहें। एक दिन को तो उनके पिता आमिर खान ने ही प्रोड्यूस किया था। अब आमिर ने स्वीकारा है कि बेटे की फिल्म की असफलता से उन्हें निराशा हुई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'फिल्में असफल होने पर मेरा तो दिल टूट जाता है। हम फिल्में दर्शकों के लिए बनाते हैं। वो टिकट खरीद कर फिल्में देखकर मजा लेने आते हैं। अगर फिल्म उन्हें नहीं पसंद आती है, तो जरूर आपके काम में कोई कमी है। दर्शकों का मन तो यह नहीं कहता है ना कि चलो यार एक बुरी फिल्म देखकर आते हैं। सब अपना पैसा खर्च करके अच्छी फिल्में देखने जाते हैं। अगर दर्शकों को निराशा हुई है, तो कहीं न कहीं हमारे ही संवाद में कोई न कोई कमी रह गई है, जो हमको समझना चाहिए और आगे सही करना चाहिए।' आमिर ने आगे कहा कि मैं तो फिल्म फ्लाप होने बाद दो-तीन महीनों तक डिप्रेशन में चला जाता हूं। फिल्म आपके बच्चे की तरह होती है, जब वो नहीं चलती है तो वो चीज बहुत दर्द देती है।